।। संगच्छध्वम् संवदध्वम् ।।

समाचार पचीसा

राजनीति का जनपक्षकार

● वर्ष-5
● अंक-263
रायपुर, शनिवार 20 जून 2026
● पृष्ठ-8
● मूल्य-3 रु.

पेज-8> वनांचल के युवाओं का पराक्रम ...

पीएम मोदी ने युवाओं को दी 2400 करोड़ की सौगात

दुनिया भारत के लिए खोल रही दरवाजे, नहीं गंवाना चाहिए मौका

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत देशभर के युवाओं को बड़ी सौगात दी। उन्होंने करीब 2,400 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि जारी की और कहा कि भारत के युवाओं के सामने आज अभूतपूर्व अवसर हैं। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि दुनिया अब भारत के लिए अपने दरवाजे खोल रही है और युवाओं को इन अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने रोजगार, स्टार्टअप, नवाचार और वैश्विक बाजारों में भारत की बढ़ती भूमिका को विकसित भारत के लक्ष्य से जोड़ा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना के तहत अब तक करीब 70 लाख रोजगार सृजित हुए हैं। लगभग 70 लाख पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी मिला है। उन्होंने बताया कि करीब 20 लाख युवाओं ने अपनी पहली नौकरी में छह महीने पूरे किए हैं और इनमें से लगभग 10 लाख युवाओं को योजना के तहत प्रोत्साहन राशि दी गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सीधे

लाभार्थियों के बैंक खातों में भेजी गई है, जो सिर्फ आर्थिक सहायता नहीं बल्कि युवाओं की मेहनत का सम्मान भी है।

नए वैश्विक अवसर खुल रहे

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि आज दुनिया भारत के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले भारत के लिए खिड़की तक नहीं खुलती थी, लेकिन अब दुनिया के कई देश भारत के साथ व्यापार और निवेश बढ़ाने को उत्सुक हैं। उन्होंने युवाओं और उद्योगों से अपील की कि भारत ने करीब 40 देशों के साथ जो मुक्त व्यापार समझौते किए हैं, उनका पूरा लाभ उठाया जाए। उनके अनुसार इन समझौतों से भारतीय उद्योगों को नए बाजार मिल रहे हैं और रोजगार के नए अवसर भी पैदा हो रहे हैं।

स्टार्टअप क्रांति ने कितना बदला है?

प्रधानमंत्री ने कहा कि एक समय देश में केवल 500 स्टार्टअप थे, लेकिन आज उनकी संख्या बढ़कर 2 लाख से अधिक हो गई है। उन्होंने कहा कि अब देश का लगभग हर जिला स्टार्टअप संस्कृति से जुड़ रहा है। प्रधानमंत्री के अनुसार यह बदलाव बताता है कि आने वाले वर्षों में भारत के युवा वैश्विक स्तर पर नवाचार, उद्यमिता और आर्थिक विकास का नेतृत्व कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत के भविष्य को लेकर बेहद उत्साहित है और यह विश्वास युवाओं की क्षमता पर आधारित है।

रोजगार बढ़ाने उठाए कदम

प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने रोजगार के हर क्षेत्र को मजबूत करने का प्रयास किया है। उन्होंने बताया कि बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, डिजिटल अर्थव्यवस्था, अंतरिक्ष, स्टार्टअप और नवाचार जैसे क्षेत्रों में नए अवसर तैयार किए गए हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर प्रतिभाशाली युवा को अवसर मिले, हर नए विचार को मंच मिले और जो युवा अपना काम शुरू करना चाहते हैं, उन्हें पूरा सहयोग मिले।

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में शामिल है और विकसित भारत का रास्ता युवाओं के सपनों, कौशल और क्षमताओं से होकर गुजरता है। उन्होंने कहा कि दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था और नई तकनीकों की तैयारी कर रही है, जबकि भारत अपने युवाओं को भविष्य के लिए तैयार करने में जुटा है। प्रधानमंत्री ने भरोसा जताया कि भारतीय युवा न केवल दुनिया की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे, बल्कि उनसे आगे बढ़कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और भारत को वैश्विक नेतृत्व की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे।

पीएम ने कहा कि दुनिया भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार हो रही है और भारत भविष्य की अर्थव्यवस्था का नेतृत्व करने की तैयारी कर रहा है। दुनिया फ्यूचर टेक्नोलॉजी की ओर आगे बढ़ रही है और भारत अपने युवाओं को फ्यूचर रेडी बनाने में जुटा है। यही भारत के युवाओं के लिए सबसे बड़ा अवसर है, और हमें इस अवसर का पूरा लाभ उठाना है।

मोदी जबरदस्त वक्ता, कई काम सही किए: थरूर

नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की तारीफ की। पीएम मोदी हाल ही में भारत में सरकार के सबसे लंबे समय तक लगातार सेवा करने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बने हैं। थरूर ने पीएम मोदी को %जबरदस्त वक्ता% बताया, जिनकी सोच बहुत साफ और स्पष्ट है। इस दौरान, उन्होंने सांप्रदायिक बंटवारे और संवैधानिक संस्थाओं के कमजोर होने को लेकर चिंता भी जताई।

उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि हम सभी मानते हैं कि उनमें बहुत ज्यादा उत्साह और ऊर्जा है, उनकी एक सोच है। आप उस सोच से सहमत हों या न हों, वे अपनी बात को बहुत अच्छे से रखते हैं। वे एक जबरदस्त वक्ता हैं, शायद हिंदी में इस देश ने जितने भी बेहतरीन वक्ता देखे हैं, उनमें से एक वे भी हैं।

उन्होंने कहा कि वे खासतौर पर उन लोगों तक पहुंचते हैं, जो वह भाषा बोलते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर उनकी मौजूदगी बहुत प्रभावशाली है और इसमें कोई शक नहीं कि वे भारतीय जीवन, समाज और राजनीति के कई पहलुओं पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहे हैं। थरूर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था और खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास, निश्चित रूप से पीएम मोदी की उपलब्धियों में से एक है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसमें अभी भी सुधार की गुंजाइश है।

उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी के कार्यकाल में कुछ नकारात्मक बातें भी देखने को मिली हैं और सिर्फ सकारात्मक पहलुओं पर ही ध्यान नहीं दिया जा सकता। उन्होंने कहा कि हमें देश में बढ़ती फूट, सांप्रदायिक बंटवारे और सत्ताधारी पार्टी व उनके समर्थकों द्वारा बढ़ावा दिए जा रहे ऐसे राजनीतिक बयानों की चिंता है, जिनसे दुर्भाग्यवश आबादी का एक बड़ा हिस्सा अलग-थलग पड़ गया है। कांग्रेस नेता ने कहा कि देश के दक्षिणी हिस्से में लोग संघवाद के अस्तित्व को लेकर चिंतित हैं।

थरूर ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में हमारे लोकतंत्र की स्वतंत्र और स्वायत्त संस्थाओं को जिस तरह से खोखला किया गया है, उसे लेकर कई तरह की वास्तविक चिंताएं हैं। उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से मुझे लगता है कि उन्होंने (पीएम मोदी ने) कई काम सही किए हैं, लेकिन इस दौरान ऐसी कई चीजें भी हुई हैं, जो भारत के लिए उतनी अच्छी नहीं हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से आज राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था, किसानों के हित में संचालित योजनाओं, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली।

>>विस्तृत समाचार पेज-3 पर

पासपोर्ट अब हर भारतीय का अधिकार: जयशंकर

नई दिल्ली। भारत में पासपोर्ट बनवाने की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में कहीं अधिक आसान, तेज और सुलभ हो गई है। विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वार्षिक क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी सम्मेलन में कहा कि आज पासपोर्ट सेवा पूरी तरह लोकतांत्रिक हो चुकी है और यह विकसित भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण इंजन का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले पासपोर्ट बनवाना एक विशेष सुविधा माना जाता था, लेकिन अब यह आम नागरिकों तक आसानी से पहुंच चुका है। यही वजह है कि देश में पासपोर्ट की मांग लगातार बढ़ रही है।

जयशंकर ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में भारत में 138 लाख से अधिक पासपोर्ट जारी किए गए हैं। यह आंकड़ा भारतीयों की बढ़ती आकांक्षाओं और वैश्विक स्तर पर अवसरों की तलाश को दर्शाता है। उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ यूरोप दौरे का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया भर में भारतीय प्रतिभा की मांग तेजी से बढ़ रही है। जी7 देशों, फ्रांस और

स्लोवाकिया जैसे देशों में भारतीय युवाओं और पेशेवरों की क्षमता को काफी सम्मान मिल रहा है। ऐसे में पासपोर्ट भारतीयों के लिए वैश्विक अवसरों का द्वार बनता जा रहा है।विदेश मंत्री ने कहा कि पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम संस्करण 2.0 ने वैश्विक गतिशीलता को नई पहचान दी है। उनके अनुसार पासपोर्ट केवल एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह आर्थिक प्रगति, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और राष्ट्रीय पहचान का एक महत्वपूर्ण साधन है। उन्होंने कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि पासपोर्ट प्राप्त करना नागरिकों के लिए संघर्ष नहीं बल्कि उनका अधिकार बने। इसी सोच के तहत सेवाओं को और अधिक पारदर्शी तथा डिजिटल बनाया गया है।सम्मेलन में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2014 में देश में केवल 77 पासपोर्ट सेवा केंद्र थे। अब इनकी संख्या बढ़कर 545 से अधिक हो गई है। इसके अलावा 454 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भी काम कर रहे हैं। इससे छोटे शहरों और दूरदराज के इलाकों के लोगों को भी पासपोर्ट सेवाओं का लाभ मिल रहा है।

प्रमुख समाचार

प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मुर्मू आज ओडिशा दौरे पर रहेंगे

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को ओडिशा का दौरा करेंगे। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू भी इस दौरे में प्रधानमंत्री के साथ रहेंगी। इस खास मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी शिरकत करके पूरे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगी। इस दौरान प्रधानमंत्री कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। राष्ट्रपति और

प्रधानमंत्री सुबह लगभग 11:15 बजे मयूरभंज जिले के पहाड़पुर गांव का दौरा करेंगे। आदिवासी और ग्रामीण लोगों को बीच शैक्षणिक अवसर, कौशल विकास और सामाजिक-आर्थिक सशक्तीकरण को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम माना जा रहा है। दोपहर करीब 1 बजे, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मयूरभंज जिले के रायरांगपुर में ओडिशा सरकार के दो साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। विकास धारा, ओडिशा सारा विषय पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान 47,600 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस अवसर पर सभा को संबोधित भी करेंगे।

राम मंदिर दान विवाद, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे : योगी

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को अयोध्या में कई धार्मिक, सांस्कृतिक और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। यह सब ऐसे समय में हो रहा है जब राम मंदिर से जुड़े चंदे और वित्तीय पारदर्शिता पर सवाल उठ रहे हैं और कथित हेराफेरी को लेकर

विवाद जारी है। इसी बीच सीएम योगी का बड़ा बयान सामने आया है। पूरे विवाद पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने साफ तौर पर कहा है कि जिसके पास भी किसी भी तरह के सबूत है वह उन्हें विशेष जांच दल को सौंपे। इसके साथ ही उन्होंने भरोसा बताया है की जांच पूरी होने के बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। योगी ने यह भी कहा कि जांच में जो लोग भी दोषी पाए जाएंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होगी। योगी ने कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट का इंतजार हम सभी को करना चाहिए। उन्होंने अपील करते हुए कहा कि कोई भी इस मामले में अनर्गल बयान न दे। विपक्ष पर निशान चाहते हुए योगी ने कहा कि जो लोग कभी राम भक्तों पर गोली चलाने का काम करते थे, आज वही उपदेश दे रहे हैं।

ममता को एक और झटका, पूर्व मंत्री मल्लिक ने छोड़ी टीएमसी

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री ज्योति प्रिया मल्लिक ने शुक्रवार को घोषणा की कि उन्होंने खराब सेहत का हवाला देते हुए टीएमसी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे को सार्वजनिक करते हुए पूर्व मंत्री ने कहा किउन्होंने पार्टी नेतृत्व को अपने फैसले के

बारे में पहले ही बता दिया था। उन्होंने आगे कहा कि मैंने अपनी बेहद खराब सेहत के कारण ञस्ष्ट के सभी पदों से इस्तीफ़ा दे दिया है। यह घटनाक्रम टीएमसी द्वारा संगठन में बड़े फेरबदल और मल्लिक को नई वर्किंग कमेटी में शामिल करने के कुछ ही दिनों बाद हुआ है। बता दें कि मल्लिक को ममता बनर्जी का बेहद खास माना जाता रहा है। उन्होंने ममता सरकार में एक दशक तक अहम मंत्रालय संभाला। मल्लिक 2011 से 2021 तक राज्य के खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रहे थे। मल्लिक को अक्टूबर 2023 में कथित राशन वितरण घोटाले के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद उनके राजनीतिक करियर को बड़ा झटका लगा था।

सपा टूटेगी, शिवपाल बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष : ओपी राजभर

लखनऊ। ओमप्रकाश राजभर ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीडीए समारोह में मुरादाबाद वाली सांसद नहीं पहुंची न? पीट देगा अहीर, पीट देगा अल्पसंख्यक (सपाई) से अब हर कोई दूर है। सांसद ने मना कर दिया न? बाद में कह रही होंगी

कि बताया नहीं गया, सूचना नहीं मिली या छुपाया गया। क्या सच में यही हुआ है? सुभासपा प्रमुख ने अपने पोस्ट में लिखा, जो कह रहा हूं मान लो। बगावत और बागियों का नेतृत्व तो बागी बलिया की भूमि ही करेगी, क्योंकि ब्राह्मण सब भूल सकता है, पर अपमान नहीं। राजभर ने आगे कहा, पार्टी तो टूटेगी, क्योंकि एक इंटरव्यू में सनातन ने कहा है कि सनातन, सनातन है, था और सनातन के साथ ही जाएगा। सनातनी होने का दावा कौन लोग करते हैं? इसी बीच, राजभर ने शिवपाल यादव को लेकर बड़ा दावा किया। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, बाकी बची हुई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष असली चाचा ही बनेगा क्योंकि वही दोबारा पार्टी खड़ा कर सकता है।

ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट : कांग्रेस ने पर्यावरण मंत्री को लिखा पत्र

नई दिल्ली। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने शुक्रवार को पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को लेकर पत्र लिखा। इसमें उन्होंने पारदर्शिता की कमी का मुद्दा उठाया। इसके साथ ही जोर देकर कहा कि परियोजना के अलग- अलग पहलुओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन स्पष्ट रूप से

अपर्याप्त हैं। कांग्रेस नेता का यह नया पत्र पिछले कुछ वर्षों में इस परियोजना को लेकर उनके और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव के बीच हुए पत्रों के आदान-प्रदान की पृष्ठभूमि में आया है। पूर्व पर्यावरण मंत्री ने यादव को लिखे अपने नए पत्र में कहा, 3 जून, 2026 के मेरे पत्र के जवाब में 13 जून, 2026 को आपकी प्रतिक्रिया के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद, हालांकि यह निराशाजनक और असंतोषजनक थी। मुझे यह कहते हुए खेद है कि ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना के विभिन्न पहलुओं के पर्यावरणीय प्रभाव आकलन स्पष्ट रूप से अपर्याप्त हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों से बेहद कम हैं। रमेश ने बताया कि इन बातों का विस्तृत उल्लेख उनके पहले के पत्रों में किया गया था, जिनका यादव के पास कोई सार्थक उत्तर नहीं था।

नारी शक्ति का एक दशक, विकसित भारत उत्कर्ष के बने भागीदार

श्रीमती अन्नपूर्णा देवी

देश के किसी भी गाँव, बस्ती या सुदूर इलाके में जाइए- हर घर की रसोई में एक जैसी बदली हुई हवा महसूस होगी द्य चूल्हे के जिस काले धुएँ ने कभी नई दुल्हन की आँखों में आँसू भरे थे, उज्ज्वला की नीली लौ ने उसे विदा कह दिया है। जो माँ कभी कोसों दूर से पानी ढोती थी, आज उसकी बेटी के पास 'हर घर जल' का अपना नल है। खेत के पीछे की वह शर्मनाक मजबूरी अब इतिहास है- आँगन में स्वच्छ भारत का शौचालय गरिमा के साथ खड़ा है। सिर पर पक्की छत है, और उसके मालिकाना हक पर पहली बार- घर की महिला का नाम लिखा है। पर्स में जन-धन की पासबुक है और फोन में यूपीआई का ऐप है।

यह किसी पोस्टर पर छपी कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के बारह वर्षों में महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा सच है, जिसे देश की करोड़ों महिलाएँ हर रोज़ जी रही हैं। यह उस दौर की दास्तान है जिसमें नारी शक्ति दशक के विजन के साथ भारतीय नारी विकसित भारत की शिल्पकार बन रही है।

इस बदलाव की विशालता को समझने के लिए एक दशक पीछे लौटिए। एक समय मातृ मृत्यु दर 212 थी। निर्भया जैसी घटना पर देश का आक्रोश सड़कों पर था, लेकिन व्यवस्था में नीतिगत इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती थी। महिला आरक्षण विधेयक 1996 से चार बार अधर में लटका रहा और ट्रिपल तलाक पर दशकों तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। चूल्हा साँसों में कालिख घोलता था। दूरस्थ हैंडपंप रोज़मर्रा की बेबसी का प्रतीक था द्य भारतीय नारी एक नई सुबह की प्रतीक्षा में अपने हिस्से की उम्मीद बचाए हुए थी।

शुरुआत करते हैं सबसे पवित्र आँकड़े- जीवन का अधिकार से। देश में मातृ मृत्यु दर तेजी से घटकर 212 से 88 पर आ गई है। यूएन-एमएमईआईजी के अनुसार जहाँ वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर में महज़ 48% की कमी आई, वहीं भारत ने 86% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की है। संस्थागत प्रसव 38.7% से

बढ़कर 90.6% हो चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने चार करोड़ से अधिक माताओं के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक सीधे हस्तांतरित कर सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ बचपन की नींव मजबूत की है।

देश में बने 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों ने महिलाओं को गरिमा दी। 10.5 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शनों ने धुएँ से मुक्ति दी। आज 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल का पानी पहुँच चुका है- जबकि 2014 में महज 17% परिवारों के पास यह सुविधा थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 4 करोड़ घरों में से 73% घर महिलाओं के नाम पर हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सरकारी रिकॉर्ड्स पर माँ-बहनों का नाम गर्व से दर्ज है।

गरिमा से स्वामित्व आया, और स्वामित्व ने निर्णय लेने का आत्मविश्वास दिया। आर्थिक भागीदारी का यह विस्तार बैंक खाते से शुरू होकर उद्यमिता तक पहुँचा है द्य लगभग 56 करोड़ जन-धन खातों में 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।

विश्व बैंक मानता है- भारत ने एक दशक में खाता-स्वामित्व के जेंडर गैप को शून्य पर ला दिया है, जो वैश्विक वित्तीय समावेशन के इतिहास में अभूतपूर्व है। मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक जमानत-मुक्त ऋणों में से 68त्न ऋण महिलाओं को मिले हैं। स्टैंड-अप इंडिया ने महिला उद्यमियों को 43,000 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों ने 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाई है। निर्धारित समय से पहले 3 करोड़ बहनें 'लखपति दीदियाँ' बन चुकी हैं।

यह बदलाव शिक्षा और रोजगार में भी स्पष्ट है द्य देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी वर्ष 2017-18 के 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह भागीदारी 47.6% तक पहुँच चुकी है। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक 4.53 करोड़ खातों में 3.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है। उच्च शिक्षा में हमारा जेंडर समानता सूचकांक 1 के पार है और शिक्षा में बेटियों की भागीदारी 43% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से एक है। यह परिवर्तन केवल अनुभवों में नहीं, एसआरएस, एनएफएचएस, पीएलएफएस , विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र- हर रिपोर्ट एक ही दिशा की ओर इशारा करती है- भारतीय महिला के लिए पहुँच बढ़ी है और आत्मनिर्भरता का नया आसमान खुला है।

इसी आर्थिक-सामाजिक चेतना का विस्तार राजनैतिक और लोकतांत्रिक भागीदारी में दिख रहा है। वर्ष 2019 के आम चुनावों में पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 31.2 करोड़ महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया।

दंतेवाड़ा में कलेक्टर ने टीम के साथ किया वनांचल क्षेत्रों के गांवों का दौरा

दंतेवाड़ा। जिले के कलेक्टर देवेश कुमार ध्रुव ने गुरुवार को अतिदुर्गम वनांचल क्षेत्रों का दौरा किया। प्रशासन की टीम इंद्रावती नदी के दूसरी ओर पहुंची और संदेश दिया कि प्रशासन की पहुंच जिले के अंतिम गांव तक भी हो सकती है। उन्होंने विकासखंड गीदम के ग्राम पंचायत गुमलनार के आश्रित गांव भिरसापारा और पालोडी का दौरा किया।

कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ काउरगांव के बिंगूपारा से पैदल यात्रा शुरू की। घने जंगलों और कठिन पहाड़ी रास्तों से होकर करीब 6 से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर वे भिरसापारा पहुंचे। वापसी के दौरान कलेक्टर ने इंद्रावती नदी पार कर ग्राम पंचायत गुमलनार का भी दौरा किया।

यहां सरपंच मालती इस्तामी ने बताया कि बारिश के दिनों में नदी के कारण आवागमन पूरी तरह बंद हो जाता है, जिससे ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। कलेक्टर ने इस समस्या के समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि स्थानीय जरूरतों के अनुसार पंचायतों के माध्यम से विकास कार्यों को और मजबूत किया जाएगा।

करीब 42 घरों वाले भिरसापारा में ग्रामीणों ने कलेक्टर का स्वागत किया। गांव में किसी भवन की जगह इमली के बड़े पेड़ के नीचे जनचौपाल लगाई गई। कलेक्टर ने ग्रामीणों के बीच बैठकर उनकी समस्याएं सुनीं। उन्होंने पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, राशन वितरण, सड़क और आवागमन जैसी मूलभूत सुविधाओं की जानकारी ली। मानसून को देखते हुए कलेक्टर ने ग्रामीणों से पूछा कि अगले चार महीनों के लिए पर्याप्त राशन उपलब्ध है या नहीं। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को समय रहते जरूरी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

वहीं, कलेक्टर ने मितानिनों और ग्रामीणों से चर्चा कर गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण, टीकाकरण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति जानी। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। दौरे के दौरान कलेक्टर ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। उन्होंने बच्चों को मिलने वाले पोषण आहार, शैक्षणिक गतिविधियों और उपलब्ध सुविधाओं की समीक्षा की।निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बच्चों को गर्म भोजन के साथ उबले अंडे भी दिए जा रहे हैं। कलेक्टर ने इस व्यवस्था की सराहना करते हुए बच्चों के पोषण और स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए।

भिरसापारा के बाद कलेक्टर पैदल ही पालोडी पहुंचे। 26 घरों वाले इस गांव में भी उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।

ग्रामीणों ने कहा कि पहली बार किसी जिला कलेक्टर को जंगल और पहाड़ पार कर उनके गांव तक पहुंचते देखा है। इससे उन्हें भरोसा हुआ है कि उनकी समस्याएं अब सीधे प्रशासन तक पहुंचेंगी।

मुंगेली में स्पंज आयरन प्लांट में 3 मजदूर झुलसे

मुंगेली। मुंगेली जिले के सरगांव क्षेत्र में स्थित स्पंज आयरन प्लांट में हुए हादसे में वहां काम कर रहे 3 मजदूर झुलस गए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है।

मुंगेली जिले के सरगांव रामबोड़ स्थित प्लांट में औद्योगिक दुर्घटना हुई। नियमित मेंटेनेंस काम के दौरान कीलन डिस्चार्ज गेट जाम होने के कारण उसका मेंटेनेंस किया जा रहा था। इसी दौरान गेट अचानक खुल गया, जिससे गर्म स्पंज आयरन बाहर आ गया।

इस घटना में वहां काम करने वाले तीन मजदूर आंशिक रूप से झुलस गए। घायलों में बिहार औरंगाबाद निवासी अमित कुमार,मध्यप्रदेश के होशंगाबाद के योगेश मीणा और ओडिशा के बालेश्वर के रहने वाले अमरेश दत्ता शामिल हैं। घटना के तुरंत बाद कंपनी प्रबंधन ने एम्बुलेंस से सभी घायलों को बिलासपुर के अपोलो अस्पताल पहुंचाया। इनमें से अमित कुमार को बेहतर उपचार के लिए कालड़ा अस्पताल, रायपुर रेफर किया गया है।औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग से सूचना मिलते ही जिला प्रशासन के अधिकारी तत्काल मौके पर पहुंचे। प्रशासन की टीम ने राहत और उपचार व्यवस्था का जायजा लिया और अस्पताल पहुंचकर घायलों के स्वास्थ्य की जानकारी ली। अस्पताल प्रबंधन ने बताया कि सभी घायल खतरे से बाहर हैं और उनकी स्थिति सामान्य और स्थिर है। जिला प्रशासन घायलों के उपचार और आवश्यक सहायता पर लगातार निगरानी रख रहा है। प्रशासन ने घटनास्थल का मुआयना भी किया है। दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जांच संबंधित विभाग द्वारा की जा रही है।

आदतन अपराधी रज्जाक अली पर एनएसए लगाने की तैयारी

कोरबा। कोरबा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बीजेपी नेता पर जानलेवा हमला करने वाले पूर्व जनपद उपाध्यक्ष आदतन अपराधी रज्जाक अली को गिरफ्तार कर लिया है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में रज्जाक का जुलूस निकाला गया था। आपराधिक पृष्ठभूमि और मौजूदा गतिविधियों के मद्देनजर अब रज्जाक के विरुद्ध राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम(ह्क्) की गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध कर उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। हाल ही में रज्जाक अली ने सिविल लाइन रामपुर थाना क्षेत्र में 15 जून को बालक क्षेत्र के बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष शिवबालक सिंह तोमर की पिटाई की थी। तोमर ने ही शिकायत दर्ज कराई थी। प्रार्थी के अनुसार, जिला जेल के पास रज्जाक अली और उसके साथियों ने पुरानी रंजिश के कारण उनका रास्ता रोका। गाली-गलौज की और जान से मारने की धमकी दी। रज्जाक ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर लोहे के डंडे और अन्य हथियारों से प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया।जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं। इस मामले में पुलिस ने धारा 296, 351(3), 109(1), 3(5) बीएनएस और आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। दरअसल जिला जेल में तोमर के कोई रिश्तेदार निरुद्ध है। जिससे मिलने तोमर जिला जेल पहुंचे हुए थे। पुराने मामले को लेकर तोमर और रज्जाक के बीच पुरानी रंजिश थी।

रज्जाक ने तोमर से कहा था कि वह उस मामले से दूर रहें, जेल में निरुद्ध अपने रिश्तेदार का साथ ना दें। कोरबा सीएसपी प्रतीक चतुर्वेदी ने बताया कि कानून-व्यवस्था को चुनौती देने वाले किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा।

बलरामपुर दौरे पर पीडब्ल्यूडी के सचिव, निर्माणाधीन कार्यों का लिया जायजा

बलरामपुर। पीडबल्यूडी विभाग के सचिव मुकेश बंसल बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के दौरे पर पहुंचे। यहां उन्होंने निर्माणाधीन सड़क सेतु और भवनों का निरीक्षण किया। साथ ही विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्माण कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने धीमी गति से किए जा रहे सड़क निर्माण कार्य को लेकर अपनी नाराजगी भी जाहिर की।आयोजित बैठक में कलेक्टर चंदन त्रिपाठी, वनमण्डलाधिकारी आलोक बाजपेई और लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियंता वी.के। भतपहरी सहित वरिष्ठ विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे। पीडब्ल्यूडी सचिव ने बैठक के दौरान अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाते हुए समय-सीमा में पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने हर कार्य की नियमित मॉनिटरिंग करने और ठेकेदारों के साथ समन्वय बनाकर कार्यों को गति देने को कहा।

बैठक में बलरामपुर-रामानुजगंज-सनावल, कामेश्वरनगर, कपिलदेवपुर, गणेशमोड़, जनकपुर, रमेशपुर-शंकरपुर, चंपा से बादा और कुसमी-कोरंधा मार्ग निर्माण की समीक्षा की। उन्होंने कई भवनों के निर्माण और अधोसंरचना परियोजनाओं के साथ ही शासकीय महाविद्यालय भवन के कार्यों की भी जानकारी ली। कहा कि निर्माण कार्यों में विलंब किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं है। लोक निर्माण विभाग के सचिव ने बैठक के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग-343 और कंठीघाट में निर्माणाधीन सड़क का निरीक्षण किया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग-343 का निरीक्षण करते हुए कहा कि बरसात के पहले नाली निर्माण एवं जल निकासी संबंधी सभी काम समयबद्ध रूप से पूरे किए जाएं, ताकि वर्षा के दौरान आवागमन बाधित न हो।

कालिक पोतने वाला हैवान पति गिरफ्तार

कोरिया। पत्नी के साथ क्रूरता के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह मामला पटना थाना क्षेत्र के कटकोना पंडोपारा गांव का है, जहां पति-पत्नी के रिश्ते को शर्मसार करने वाली वारदात को आरोपी ने अंजाम दिया। आरोपी ने ना सिर्फ मारपीट की बल्कि उसके बाल काटे और यूरिन पिलाने की भी कोशिश की। पति-पत्नी का चरित्र शंका को लेकर विवाद हुआ था। जिसके बाद पीड़िता पिछले करीब एक साल से अपने पति जितेंद्र घसिया और बच्चों से अलग रह रही थी। वर्तमान में वह पंडोपारा में अपने एक रिश्तेदार के घर पर रह रही थी। पीड़िता के अनुसार, 14 जून को उसका पति जितेंद्र वहां पहुंचा और फिर विवाद करने लगा। विवाद बढ़ने पर आरोपी ने बेरहमी से मारपीट की बल्कि हैवानियत की सारी हदें पार कर दीं। आरोप है कि पति ने महिला के हाथ-पैर बांध दिए और बेरहमी से मारपीट की। इसके बाद जबरन उसके बाल काटकर सिर का मुंडन कर दिया और चेहरे पर कालिख पोत दी। पीड़िता ने पुलिस को दी शिकायत में यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने पहले बच्चों से उसके ऊपर यूरिन कराया और बाद में वही पेशाब उसे जबरन पिलाने की भी कोशिश की। घटना के बाद पीड़िता किसी तरह हिम्मत जुटाकर पटना थाना पहुंची और शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भारतीय न्याय संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने केस में और भी सख्त धाराएं जोड़ीं हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी जितेंद्र घसिया को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। पीड़िता के बयान के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है। घटना एक बार फिर महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों और घरेलू हिंसा की भयावह तस्वीर को बयां कर रही है।

जनपद उपाध्यक्ष समेत बीजेपी नेता के खिलाफ इंजीनियर संघ लामबंद

सक्ती। सक्ती जिले में सब इंजीनियर शरद देवांगन के साथ हुए मारपीट का मामला एक बार फिर से गरमा रहा है,एफआईआर के बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने पर अब छत्तीसगढ़ इंजीनियर डिप्लोमा एसोसिएशन संघ अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गया है। संघ का कहना है कि जब तक आरोपी जनपद उपाध्यक्ष सीताराम चंद्रा की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक कोई भी काम पर नहीं लौटेगा।वहीं संघ ने चेतावनी भी दी है कि आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने की स्थिति में सात दिन बाद यह आंदोलन पूरे प्रदेश में देखने को मिलेगा।

जैजैपुर जनपद पंचायत में पदस्थ आरईएस सब इंजीनियर शरद देवांगन को बीजेपी जनपद उपाध्यक्ष सीताराम चंद्रा सहित कई नेताओं ने कमरे में बंद कर के मारपीट की थी।इसके बाद इंजीनियर शरद देवांगन सहित कई अधिकारी थाने में मामले में की एफआईआर कराने पहुंचे,लेकिन नेता के दबाव में पुलिस कार्रवाई नहीं हुई। वहीं अब इंजीनियर संघ के आंदोलन पर बैठने के बाद एफआईआर तो दर्ज कर ली गई है लेकिन मारपीट करने वाले जनपद उपाध्यक्ष एवं बीजेपी नेता की गिरफ्तारी करने में पुलिस टाल मटोल कर रही है जिससे नाराज इंजीनियर संघ ने अब आंदोलन को ओर तेज करने का फैसला किया है। अब संघ ने इसके विरोध में पूरे प्रदेश भर के इंजीनियर्स को आंदोलन में उतारने की बात कही है।

छत्तीसगढ़ प्रमुख समाचार

बस्तर के 30 छात्र सीखेंगे सेमीकंडक्टर चिप निर्माण

जगदलपुर। बस्तर संभाग के छात्रों के लिए तकनीकी शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में बड़ी सौगात मिलने जा रही है। बस्तर संभाग के 30 मेधावी छात्र देश के प्रतिष्ठित संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में सेमीकंडक्टर चिप मैनुफैक्चरिंग की विशेष ट्रेनिंग लेने जाएंगे। 12 जुलाई से 24 जुलाई तक आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए छात्रों का चयन विश्वविद्यालय में आयोजित इंटरनल टेस्ट के आधार पर तैयार की जाने वाली मेरिट सूची से किया जाएगा। चयनित छात्रों को राज्यपाल ट्रेनिंग के लिए हरी झंडी दिखाएंगे। सभी छात्र हवाई जहाज में सवार होकर चेन्नई के लिए रवाना होंगे। छात्रों के लिए हवाई जहाज का पूरा खर्चा दंतेवाड़ा कलेक्टर ने उठाया है। जिसमें बस्तर कलेक्टर का भी सहयोग है। बस्तर विश्वविद्यालय के कुलपति मनोज कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान छात्र सेमीकंडक्टर चिप निर्माण, माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स और आधुनिक डेटा ट्रांसफर तकनीकों की बारीकियां सीखेंगे। यह प्रशिक्षण उन्हें भविष्य की उन्नत तकनीकों और उद्योगों के लिए तैयार करेगा।

4.5 करोड़ का गांजा जब्त केलों की आड़ में हो रही थी तस्करी

पिथौरा। महासमुंद पुलिस की ओर से अवैध मादक पदार्थों के व्यापार को जड़ से खत्म करने के लिए 'सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक' मुहिम चलाई जा रही है। इसी कड़ी में पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। बसना पुलिस ने 4.5 करोड़ रुपये के गांजा तस्करी सिंडिकेट के मुख्य सरगना और नशा माफिया विनय शर्मा उर्फ पंडित जी को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल, बसना पुलिस ने 17 अप्रैल को पलसापाली बैरियर पर नाकाबंदी कर एक आयशर माल वाहक वाहन एपी39 टीटी 4556 को रोका था। पुलिस को चकमा देने के लिए वाहन में कच्चे केलों के नीचे छिपाकर 29 प्लास्टिक बोरियों में 912.760 किलो अवैध गांजा रखा गया था, जिसकी अनुमानित कीमत 4 करोड़ 56 लाख 38 हजार रुपये आंकी गई थी। मौके से पुलिस ने 4 फर्जी नंबर प्लेट भी बरामद की थी। यह खेप ओडिशा के कंधमाल से लोड होकर उत्तर प्रदेश के शामली में आरोपी विनय शर्मा के पास पहुंचाई जा रही थी। मामले की विवेचना के दौरान पूर्व में पकड़े गए।

खाद संकट पर किसानों का फूटा गुस्सा, किया प्रदर्शन

खैरागढ़। खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही क्षेत्र में खाद संकट गहराने लगा है। यूरिया और डीएपी खाद की कमी से परेशान किसानों का आक्रोश ग्राम पैलीमेटा में देखने को मिला, जहां बड़ी संख्या में किसानों ने सड़क पर उतरकर चक्काजाम किया और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। किसानों का कहना है कि बुवाई का महत्वपूर्ण समय चल रहा है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में खाद उपलब्ध नहीं होने के कारण खेती-किसानी का कार्य प्रभावित हो रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि खाद वितरण केंद्रों में लगातार कमी बनी हुई है, जिससे उन्हें बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और समय पर कृषि कार्य पूरा करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। किसानों का यह प्रदर्शन जिला पंचायत सदस्य निर्मला विजय वर्मा, जिला महामंत्री लाल रोहित सिंह पुलस्त्य और जनपद सदस्य प्रेमलाल साहू के नेतृत्व में आयोजित किया गया। प्रदर्शन के दौरान किसानों ने खाद की समस्या का समाधान करने की मांग करते हुए प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की।

कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क में दिखी मां की ममता

जांजगीर चांपा। कोटमी सोनार गांव मगरमच्छ अभ्यारण के नाम से प्रसिद्ध हैं। पहले यहां सभी तालबों में मगरमच्छ पाए जाते थे, लेकिन सरकार ने इन मगरमच्छों को अनुकूल वातावरण देने और ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए गांव के मुढ़ा तालाब में 50 एकड़ से ज्यादा जगह संरक्षित किया हैं। उनके सहवास के साथ साथ ब्रीडिंग के लिए रेत और मिट्टी का टीला भी तैयार किया है। जहां मगरमच्छ अपना वंश वृद्धि कर रहे हैं। कोटमी सोनार क्रोकोडाइल पार्क में जून माह में मादा मगरमच्छ अपने अंडों से निकले बच्चों पर अपनी ममता उड़ेलती है। बच्चों के अंडों से निकलने के बाद अपने जबड़े मे दबाकर उन्हें पानी में रहने की कला सिखाती हैं। साथ ही नर मगरमच्छों से नन्हे बच्चों की रक्षा के लिए मादा मगरमच्छ हमेशा बच्चों के आसपास तालाब के किनारे ही बैठी रहती हैं। पार्क में हैचिंग का काम पूरा हो गया है। नर मगरमच्छ अक्सर छोटे बच्चों को खा जाते हैं, इसकी निगरानी की जा रही है साथ ही मादा मगरमच्छ भी बच्चों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाती रहती है।

ट्रैक्टर जब्ती के बाद किसान ने खाया जहर, जांच शुरू

बलौदाबाजार। कसडोल क्षेत्र में एक किसान के जहरीले पदार्थ का सेवन किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़ित किसान ने आरोप लगाया है कि महानदी से रेत लेकर आने के दौरान उसका ट्रैक्टर प्रशासन ने जब्त किया और ट्रैक्टर छोड़ने के एवज में 50 हजार रुपए की मांग की। पैसे नहीं देने पर ट्रैक्टर को थाने भिजवा दिया गया। परिवारवालों ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया है।जहां उसका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार किसान कमल ओगरे का ट्रैक्टर महानदी क्षेत्र से रेत लेकर लौट रहा था। इसी दौरान राजस्व विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर को जब्त कर लिया ।पीड़ित किसान का आरोप है कि ट्रैक्टर छोड़ने के लिए पैसे मांगे गए। किसान का कहना है कि उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह इतनी बड़ी राशि दे सके। इसी कारण वह मानसिक रूप से परेशान हो गया। परिजनों के अनुसार ट्रैक्टर जब्त होने और कथित मांग से परेशान किसान ने बाद में जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।

तेंदुए का आतंक, शाम होते ही पहरा, गांव में पसरा सन्नाटा

कांकेर। सरोना वन परिक्षेत्र के गट्टागुडम गांव में तेंदुए का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। बीते 6 दिनों में तेंदुए ने चार ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया है। लगातार हो रहे हमलों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। हालात ऐसे हैं कि शाम होते ही लोग अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते हैं और पूरा गांव सन्नाटे में डूब जाता है।वन विभाग ट्रैप कैमरे लगाकर तेंदुए पर निगरानी रख रहा है, लेकिन ग्रामीण जल्द ठोस कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तेंदुए की मौजूदगी ग्रामीणों के लिए बड़ी चिंता का विषय बन गई है। पिछले छह दिनों के भीतर तेंदुए ने चार अलग-अलग ग्रामीणों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इनमें दो घटनाएं ऐसी भी रहीं, जब तेंदुआ घर के भीतर घुस गया और सो रहे लोगों पर हमला कर दिया। हमलों में घायल ग्रामीणों का इलाज कराया गया है, लेकिन लगातार हो रही घटनाओं ने पूरे गांव में भय का माहौल पैदा कर दिया है। तेंदुए के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अब ग्रामीण अकेले घर से निकलने से बच रहे हैं। लोग लाठी-डंडा लेकर समूह में बाहर निकल रहे हैं। शाम ढलते ही गांव की गलियां सुनसान हो जाती हैं। बच्चे घरों के बाहर खेलने नहीं निकल रहे हैं और किसान भी खेतों में जाने से डर रहे हैं। ग्रामीणों की सबसे बड़ी चिंता स्कूली बच्चों को लेकर है, क्योंकि स्कूल जंगल के नजदीक स्थित है। आए दिन घटना हो रही है। शासन से गुहार है कि जितनी जल्दी हो सके तेंदुए को पकड़ें। गांव में दहशत है। स्कूल भी खुल गया है, बच्चों को बाहर नहीं निकलने देते। हम गांव वाले भी झुंड में निकलते हैं। लोगों में बहुत दशहत है-जोगेन्द्र सिन्हा, ग्रामीण रात में अपनी सुरक्षा के लिए डंडा पकड़कर निकलते हैं। वनविभाग प्रयास कर रहा है। हमने डीएफओ साहब को भी घटनास्थल दिखाया है। अबतक चार घटना हुआ है। हम चाहते हैं कि जल्द ही तेंदुए को पकड़ें। हमें बच्चों की चिंता है। खेत जाने में भी डर लग रहा है- हरचंद नेताम, ग्रामीण घायल महिला के पड़ोसी ग्रामीण मानेसिंह यादव ने बताया कि रात करीब 12 बजे एक वृद्ध महिला पर तेंदुए ने उस समय हमला कर दिया, जब वह घर में सो रही थी। महिला की चीख-पुकार सुनकर वह मौके पर पहुंचे और किसी तरह तेंदुए को भगाया, तब तक तेंदुआ महिला के सिर पर पंजों से हमला कर चुका था और वह गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बाद में उसे स्वास्थ्य केंद्र ले जाकर उपचार कराया गया।

लगातार बढ़ते खतरे को देखते हुए ग्रामीण वन विभाग से गांव के अलग-अलग स्थानों पर पिंजरे लगाने और तेंदुए को पकड़कर सुरक्षित स्थान पर भेजने की मांग कर रहे हैं।

खतरनाक जर्जर स्कूल भवन की अब तक नहीं हुई मरम्मत

कांकेर। छत्तीसगढ़ में नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत हो चुकी है।लेकिन शुरुआत भले ही नई हुई हो जो पुरानी समस्याएं हैं ,उनका समाधान अब तक नहीं हो सका है।कांकेर जिला के कोयलीबेड़ा ब्लॉक के बंगोघोड़ियां गांव में ऐसी ही एक समस्या है,जिसके निवारण का इंतजार यहां के ग्रामीण कर रहे हैं। ये समस्या एक अदद प्राथमिक स्कूल से जुड़ी है। पुराना स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुका है।ऐसे में बच्चों को वहां पढ़ाना किसी खतरे से कम नहीं,लिहाजा ग्रामीणों ने कचरा प्रबंधन के लिए तैयार किए गए टिन शेड के कमरों को स्कूल संचालित करने के लिए दिया।लेकिन बच्चों के लिए बनाई गई ये वैकल्पिक व्यवस्था स्थायी समाधान के रुप में बदलती जा रही है। वर्षों से जर्जर पड़े स्कूल भवन के कारण बच्चों की कक्षाएं पंचायत के कचरा शेड में संचालित हो रही हैं। भीषण गर्मी और बुनियादी सुविधाओं के अभाव में 11 बच्चे कचरा शेड में बैठकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर हैं। बंगोघोड़ियां गांव का प्राथमिक स्कूल लंबे समय से जर्जर हालत में है। भवन की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि उसे बच्चों के लिए असुरक्षित मानते हुए उपयोग से बाहर कर दिया गया है। स्कूल में कुल 11 छात्र-छात्राएं पढ़ाई करते हैं। भीषण गर्मी, पर्याप्त जगह की कमी और मूलभूत सुविधाओं के अभाव के बावजूद बच्चे नियमित रूप से स्कूल पहुंच रहे हैं। इन बच्चों के सपने भी बड़े हैं। कोई सेना में अधिकारी बनना चाहता है तो कोई पढ़-लिखकर अपने परिवार और गांव का नाम रोशन करने का सपना देख रहा है। लेकिन शिक्षा की यह बदहाल व्यवस्था उनके सपनों के रास्ते में बड़ी बाधा बनती नजर आ रही है। बच्चों का कहना है कि वे पढ़-लिखकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें एक सुरक्षित और बेहतर स्कूल भवन की जरूरत है।

संक्षिप्त समाचार

मुख्यमंत्री से छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष ने की सौजन्य मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय से शुक्रवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री संजय अग्रवाल ने सौजन्य मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री साय ने श्री संजय अग्रवाल को छत्तीसगढ़ योग आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि योग भारत की प्राचीन एवं गौरवशाली परंपरा का अभिन्न अंग है, जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन स्थापित करने का प्रभावी माध्यम है। उन्होंने प्रदेश में योग को जन-जन तक पहुंचाने तथा युवाओं, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को योग से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए जाने की आवश्यकता पर बल दिया। मुलाकात के दौरान योग के संवर्धन तथा प्रदेश में योग संबंधी गतिविधियों को और अधिक प्रभावी बनाने से संबंधित विभिन्न विषयों पर भी चर्चा हुई। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि छत्तीसगढ़ योग आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्री अग्रवाल के नेतृत्व में प्रदेश में योग के प्रचार-प्रसार, जनजागरूकता तथा स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के प्रयासों को नई गति मिलेगी।

राज्यपाल से सुप्रीम कोर्ट में छत्तीसगढ़ की स्टैंडिंग काउंसिल सुश्री जैन ने की भेंट

रायपुर। राज्यपाल श्री रमेन डेका से शुक्रवार को लोकभवन में सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ शासन की स्टैंडिंग काउंसिल के रूप में कार्यरत युवा अधिवक्ता सुश्री सुगंधा जैन ने सौजन्य भेंट की। सुश्री सुगंधा जैन एनसीईआरटी अंतर्गत राष्ट्रीय शैक्षिक योजना और प्रशासन संस्थान में बाहरी पॉश प्रशिक्षक के रूप में भी कार्यरत है तथा वे वर्ष 2025 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मूट कोर्ट प्रतियोगिता में भारत की ओर से जज की भूमिका निभाने वाली पहली भारतीय बनी थी। राज्यपाल ने उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें शुभकामनाएं दी। भेंट के दौरान उनकी माता श्रीमती इंदिरा जैन भी उपस्थित थी।

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में आवेदन 22 से

रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के माध्यम से बच्चों को राज्य के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक फीस, आवासीय सुविधा, भोजन, गणवेश, लेखन सामग्री सहित अन्य आवश्यक खर्चों का वहन कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराकर उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं चयन संबंधी विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू होगी तथा 3 जुलाई 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल https://shramevjayate.cg.gov.in/shramik पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, श्रमेव जयते ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, श्रमेव जयते ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी।

दियागांव जलाशय के जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग के लिए 4.96 करोड़ रू. स्वीकृत

रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल संसाधनों के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया है। शासन के जल संसाधन विभाग द्वारा कांकेर जिले के विकासखंड दुर्गकोंदल के अंतर्गत दियागांव जलाशय के जीर्णोद्धार एवं नहर लाइनिंग कार्य के लिए 4 करोड़ 96 लाख 58 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के पूर्ण होते ही क्षेत्र के कुल 178 हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सुनिश्चित सिंचाई सुविधा मिलने लगेगी, जिससे स्थानीय किसानों की फसलों की पैदावार में बढ़ोतरी होगी। दियागांव जलाशय के जीर्णोद्धार और नहर लाइनिंग के इस महत्वाकांक्षी कार्यों के पूरे होने से क्षेत्र के कृषि परिदृश्य में बड़ा बदलाव आएगा। योजना के क्रियान्वयन को गति देने के लिए जल संसाधन विभाग द्वारा मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार जल संसाधन विभाग, जगदलपुर को इस कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कर दी गई है।

प्रदेश के कृषि विकास मॉडल का अध्ययन करने पहुंचा महाराष्ट्र का विधायक दल

किसान हितैषी नीतियों ने दिलाई छत्तीसगढ़ को नई पहचान, मुख्यमंत्री साय से महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल ने की मुलाकात

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से शुक्रवार को राजधानी रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल ने सौजन्य मुलाकात की।प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी व्यवस्था, किसानों के हित में संचालित योजनाओं, कृषि क्षेत्र में किए जा रहे सुधारों तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री साय ने प्रतिनिधिमंडल का आत्मीय स्वागत करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ कृषि प्रधान राज्य है और यहां की बड़ी आबादी खेती-किसानी पर निर्भर है। राज्य सरकार किसानों की आय बढ़ाने, कृषि को लाभकारी बनाने तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने प्रतिनिधिमंडल को बस्तर की समृद्ध आदिवासी कला एवं संस्कृति के प्रतीक बस्तर आर्ट का स्मृति-चिन्ह भेंट कर उनका स्वागत किया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और राज्य सरकार किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए समन्वित रूप से कार्य कर रही हैं। छत्तीसगढ़ में किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के साथ-साथ कृषि निवेश में सहायता, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, आधुनिक तकनीकों का उपयोग और फसल विविधीकरण को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी की जा रही है। राज्य सरकार द्वारा खरीफ विपणन वर्ष में लगभग 141 लाख मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया है, जो देश में धान खरीदी के सबसे बड़े अभियानों में से एक है। उन्होंने कहा कि किसानों की सुविधा के लिए प्रदेशभर में लगभग 2700 धान उपार्जन केंद्र संचालित किए जा रहे हैं, जहां पारदर्शी एवं सुव्यवस्थित तरीके से धान की खरीदी की जाती है। धान के सुरक्षित भंडारण के लिए संग्रहण केंद्रों और गोदामों का व्यापक नेटवर्क विकसित किया गया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके लिए पंजीयन से लेकर धान तौल, परिवहन और भुगतान तक की प्रक्रिया को तकनीक आधारित और सरल बनाया गया है। किसानों को समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करने के साथ ही विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत किया जा रहा है।

प्रतिनिधिमंडल को मुख्यमंत्री ने कृषक उन्नति योजना सहित राज्य सरकार द्वारा किसानों के हित में संचालित विभिन्न योजनाओं की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार खेती को अधिक लाभकारी बनाने तथा किसानों की आय में निरंतर वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि के साथ-साथ पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य आयवर्धक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आमदनी में वृद्धि हो रही है।

चर्चा के दौरान महाराष्ट्र के विधायक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने बताया कि छत्तीसगढ़ से लगे महाराष्ट्र के चार जिलों में बड़ी संख्या में किसान धान की खेती करते हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की धान खरीदी व्यवस्था, किसानों को मिलने वाला समर्थन और प्रशासनिक प्रबंधन अत्यंत प्रभावी एवं अनुकरणीय है। राज्य में किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने तथा खरीदी प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए किए गए प्रयास सराहनीय हैं। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि छत्तीसगढ़ का धान खरीदी मॉडल किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण का सफल उदाहरण है। उन्होंने इस मॉडल के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर महाराष्ट्र के धान उत्पादक क्षेत्रों में भी ऐसे प्रयासों को आगे बढ़ाने की बात कही।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्यों के बीच अनुभवों और सफल मॉडलों का आदान-प्रदान देश के कृषि क्षेत्र को और अधिक मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस प्रकार के अध्ययन भ्रमण से राज्यों को एक-दूसरे के सफल अनुभवों से सीखने और उन्हें स्थानीय परिस्थितियों के अनुरूप अपनाने का अवसर मिलता है। इस अवसर पर महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े, महाराष्ट्र के विधायक डॉ. परिणय फुके, श्री विनोद अग्रवाल, श्री राजू कारेमोरे एवं श्री संजय पुराम, छत्तीसगढ़ मार्कफेड के अध्यक्ष श्री शशिकांत द्विवेदी, मुख्यमंत्री के सचिव श्री राहुल भगत सहित वरिष्ठ अधिकारीगण उपस्थित थे।

मंत्रियों की हाईलेवल मीटिंग पर कांग्रेस के तंज का अजय चंद्राकर ने दिया जवाब

कहा- सरकार में नहीं, कांग्रेस में बन चुकी है विस्फोटक स्थिति

रायपुर। मुख्यमंत्री निवास में बीती रात हुई मंत्रियों की हाई लेवल मीटिंग को लेकर कांग्रेस ने तंज कसते हुए सरकार में विस्फोटक स्थिति की बात कही थी। इस बयान पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने पलटवार करते हुए कहा कि विस्फोटक स्थिति तो कांग्रेस में बन चुकी है। कांग्रेस को बताना चाहिए कि क्यों लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। कांग्रेस पूरी तरह अप्रासंगिक हो चुकी है।

भाजपा के वरिष्ठ विधायक अजय चंद्राकर ने मीडिया से चर्चा में मंत्रियों की हाईलेवल मीटिंग को लेकर कहा कि भाजपा संगठन और मुख्यमंत्री की ओर से सार्थक पहल हुई है। यह सभी रूटीन बैठक है, नियमित प्रक्रिया के तहत बैठक हो रही है।

वहीं 21 जून को राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ आगमन पर अजय चंद्राकर ने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या राहुल गांधी के लिए भी गुलाब मंगवा रहे हैं, प्रियंका वाड्रा के लिए तो मंगवाये थे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को प्रशिक्षण की जरूरत क्यों पड़ रही है पता नहीं। राहुल गांधी शायद भूपेश बघेल को बधाई देने आ रहे हैं। भूपेश बघेल जहां-जहां जाते है, वहां-वहां पार्टी हार जाती है। कांग्रेस के मौजूदा विशेषज्ञों की स्थिति जनता ने देख ली है। विशेषज्ञ केवल एक ही परिणाम ला रहे हैं, और वो है पराजय।

छत्तीसगढ़ में शराब की ओवररेटिंग को लेकर भाजपा विधायक ने कहा कि कांग्रेस को ओवररेटिंग, या शराब को लेकर बात करने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में सभी तरह के भ्रष्टाचार में अपने हाथ धो चुकी है।

इसके साथ ही कांग्रेस नीत इंडिया ब्लॉक पर तंज कसते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि इंडिया ब्लॉक में भगदड़ मची है। देश में राजनीतिक अराजकता फैल रही है। कांग्रेस को जिम्मेदार विपक्ष की तरह बर्ताव करना चाहिए। भूपेश बघेल कांग्रेस के शुभंकर हैं। कांग्रेस में बचे ही गिनते के लोग हैं। वहीं नीट पेपर पर तमाम राज्यों में कांग्रेस के प्रेस कॉन्फ्रेंस पर विधायक अजय चंद्राकर ने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर की नैतिक जिम्मेदारी ने ली है। कांग्रेस के समय में जब ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई थी, तब किसी मंत्री ने नैतिक जिम्मेदारी नहीं ली थी। अबकी बार सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सोच पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसे नैरेटिव रखती है, जो जनता को समझ नहीं आती।

योग स्वस्थ और संतुलित जीवन का मूलमंत्र है: किरण देव

रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने आगामी 21 जून को मनाए जाने वाले अन्तरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएँ दी हैं। अपने सन्देश में श्री देव ने योग की वैश्विक उपयोगिता पर प्रकाश डालते हुए सभी से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आग्रह किया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष श्री देव ने कहा कि भारत की ऋषि परम्परा की यह अमूल्य धरोहर आज वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयासों से आज पूरा विश्व योग के महत्व को स्वीकार कर रहा है। योग शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करने का सबसे सशक्त माध्यम है। श्री देव ने कहा कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी और तनावपूर्ण माहौल में योग मानसिक शांति और आंतरिक ऊर्जा प्रदान करने का अचूक साधन है। यह न केवल शरीर को निरोगी रखता है, बल्कि एकाग्रता और सकारात्मकता को भी बढ़ाता है।

योग मत, पंथ या मजहब से परे संपूर्ण मानवता के कल्याण के लिए है। यह %वसुधैव कुटुंबकम% की भावना को चरितार्थ करता है। जब प्रत्येक नागरिक शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होगा, तभी एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र का निर्माण संभव है।

श्री देव ने छत्तीसगढ़ के सभी नागरिकों, विशेषकर युवाओं और बच्चों से अपील की है कि वे योग कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर हिस्सा लें। इस योग दिवस पर हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि %करो योग, रहो निरोग% के मंत्र को अपने जीवन में उतारेंगे और एक स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण में अपना योगदान देंगे।

नीट परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करने कलेक्टर पहुंचे पीएम श्री आत्मानंद, केंद्रीय विद्यालय व एनआईटी

रायपुर। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने नीट परीक्षा के दो दिन पूर्व आज शहर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों एवं केंद्र प्रभारियों को निर्देश दिए कि बारिश की स्थिति में किसी भी परीक्षार्थी को असुविधा न हो। केंद्र में पर्याप्त शेड की व्यवस्था करें ताकि फ्रिस्किंग करने एवं अन्य व्यवस्थाओं में असुविधा न हो। साथ ही फ्रिस्किंग स्थल पर भी शेड एवं अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं।

कलेक्टर डॉ सिंह ने पीएम श्री आत्मानंद आर.डी. तिवारी विद्यालय आमापारा, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2 डी.डी.यू नगर तथा एनआईटी स्थित परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने केंद्रों पर उपलब्ध मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा की और व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। डॉ. सिंह ने स्वयं कक्षाओं के भीतर पहुंचकर बैठने की व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, पेयजल, शौचालय सहित अन्य आवश्यक सुविधाओं की जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि परीक्षा के दौरान सभी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से संचालित हों तथा परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस अवसर पर डीसीपी श्री मयंक गुर्जर, एसडीएम श्री नंदकुमार चौबे, एडीसीपी श्री राहुल देव शर्मा, डिप्टी कलेक्टर श्री उपेन्द्र किण्डो सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने हड़ताल की दी चेतावनी

■ 7 सूत्रीय मांगों को लेकर कमिश्नर को सौंपा ज्ञापन

रायपुर। नगर पालिका निगम रायपुर के प्लेसमेंट कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी दी है। कर्मचारियों ने कमिश्नर को ज्ञापन सौंपते हुए मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की करने की बात कही है।

प्लेसमेंट कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय एड़े ने कहा कि नगर निगम के विभिन्न विभागों, जोनों, कार्यालयों और आवश्यक जनसेवाओं के सुचारू एवं अबाधित संचालन में रीढ़ की हड्डी की तरह कार्य कर रहे प्लेसमेंट कर्मचारियों के हितों, सामाजिक-आर्थिक सुरक्षा और उनके विधिक अधिकारों की रक्षा के लिए 7 सूत्रीय मांग की गई है।

कर्मचारियों की 7 सूत्रीय प्रमुख मांगें इस प्रकार हैं-

- न्यूनतम वेतन: बढ़ती महंगाई को देखते हुए न्यूनतम मानदेय 20,000 रुपये प्रतिमाह तत्काल लागू किया जाए।
- जॉब सुरक्षा: ठेका या एजेंसी बदलने पर पुराने कर्मचारियों को न निकाला जाए, टेंडर अनुबंध में सेवा सुरक्षा की कड़ी शर्त जोड़ी जाए।
- वेतन विसंगति दूर करना: संचालनालय नगरीय प्रशासन के यांत्रिकी प्रकोष्ठ की भांति निगम के प्लेसमेंट कर्मचारियों को भी संविदा अनुरूप मानदेय मिले।
- श्रम कानूनों का पालन: शासन द्वारा निर्धारित नवीन 04 श्रम कानूनों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो।
- सीधे भुगतान (डीबीटी): बिचौलियों व ठेकेदारों के शोषण से मुक्ति के लिए वेतन सीधे नगर निगम द्वारा बैंक खातों में (डीबीटी) दिया जाए।
- नियत समय पर वेतन: प्रत्येक माह की 5 तारीख तक अनिवार्य रूप से वेतन भुगतान सुनिश्चित किया जाए।
- सेटअप संशोधन: वर्तमान में कार्यरत वास्तविक संख्या और कार्यभार के आधार पर निगम के सेटअप में संशोधन किया जाए।

चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कारण कई ट्रेनें 21 से प्रभावित रहेंगी

रायपुर/बिलासपुर। बिलासपुर चांपा चौथी लाइन परियोजना के अंतर्गत जांजगीर नैला स्टेशन पर अपग्रिड में ऑटो सिग्नलिंग सहित चौथी लाइन कनेक्टिविटी के कमीशनिंग कार्य के लिए नॉन-इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाएगा। यह कार्य 21 जून 2026 से 5 जुलाई 2026 तक अलग अलग चरण में होंगे।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण एवं रेल परिवहन क्षमता में वृद्धि के लिए बिलासपुर-झारसुगुड़ा के बीच 206 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन परियोजना का कार्य लगभग 2135.34 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत अब तक 180 किलोमीटर से ज्यादा चौथी रेललाइन का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

परियोजना के पूर्ण होने पर इस महत्वपूर्ण रेलखंड की क्षमता में वृद्धि होगी। जिससे ट्रेनों का परिचालन सुगम और सरल होगा। इसके साथ ही यात्री एवं माल परिवहन को गति मिलने से क्षेत्र के उद्योग, व्यापार एवं रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। यात्रियों को बेहतर और सुविधाजनक रेल सेवाओं का भी लाभ मिल सकेगा।

रद्द होने वाली गाड़ियां

22 जून से 03 जुलाई 2026 तक रायगढ़ व बिलासपुर से चलने वाली 68737/68738 रायगढ़-बिलासपुर-रायगढ़ मेमू रद्द

21 जून से 02 जुलाई 2026 तक रायपुर से चलने वाली 68746 रायपुर-गेवरा रोड मेमू पैसेंजर रद्द

22 जून से 03 जुलाई 2026 तक गेवरा रोड से चलने वाली 68745 गेवरा रोड-रायपुर मेमू पैसेंजर रद्द

21 जून से 02 जुलाई 2026 तक रायपुर से चलने वाली 58204 रायपुर-कोरबा पैसेंजर रद्द

22 जून से 03 जुलाई 2026 तक कोरबा से चलने वाली 58203 कोरबा-रायपुर पैसेंजर रद्द

22 जून से 03 जुलाई 2026 तक बिलासपुर व गेवरा रोड से चलने वाली 68734/68733 बिलासपुर-गेवरा रोड-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द

22 जून से 03 जुलाई 2026 तक बिलासपुर व कोरबा से चलने वाली 68732/68731 बिलासपुर-कोरबा-बिलासपुर मेमू पैसेंजर रद्द

देरी से रवाना होने वाली गाड़ी

01 जुलाई 2026 को कोरबा से चलने वाली गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस अपने निर्धारित समय से 02 घंटे देरी से रवाना होगी

गंतव्य से पहले समाप्त व शुरू होने वाली गाड़ियां

22 जून से 03 जुलाई 2026 तक गोंदिया से चलने वाली 68861 गोंदिया-झारसुगुड़ा मेमू पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन में समाप्त होगी।

बिलासपुर-झारसुगुड़ा के मध्य रद्द रहेगी

22 जून से 03 जुलाई 2026 तक झारसुगुड़ा से चलने वाली 68862 झारसुगुड़ा-गोंदिया पैसेंजर बिलासपुर स्टेशन से प्रारम्भ होगी तथा झारसुगुड़ा-बिलासपुर के मध्य रद्द रहेगी।

यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष प्रबंध

कोरबा से चलने वाली गाड़ी संख्या 18237 कोरबा-अमृतसर छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस को दिनांक 22 जून से 03 जुलाई 2026 तक कोरबा-बिलासपुर के मध्य पैसेंजर के रूप में चलाई जाएगी

कार्यालय, कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकीय खण्ड
राजनांदगांव (छ.ग.)
छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 25
07744-299703
eeraj-phe-cg@nic.in

नि.सू क्रमांक 28/ निविदा प्रको./ का.अ./ लो.स्वा.यां. खण्ड / 2026 राजनांदगांव, दिनांक 17.06.2026

सिस्टम क्रमांक 193631

// द्वितीय निविदा आमंत्रण सूचना //

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल की ओर से एकीकृत पंजीयन प्रणाली के अन्तर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों से जिला खनिज संस्थान न्यास मद योजनांतर्गत राजनांदगांव जिले के प्रेस क्लब कौरिनभाठा, राजनांदगांव में पाईप लाईन प्रदाय कर जोड़ने, बिछाने, इन्टरकनेक्शन स्पेशल्स सहित नल कनेक्शन प्रदाय करने संबंधी आदि समस्त कार्य, टेस्टिंग, 03 माह का ट्रायल रन, 6 माह तक संचालन संधारण का कार्य (सम्पूर्ण कार्य सामग्री सहित) की निविदा ऑनलाईन पर आमंत्रित की जाती है। जिसकी अनुमानित लागत रू. 20.48 लाख निर्धारित है।

उपरोक्त कार्य के निविदा की सामान्य शर्तें, धरोहर राशि, विस्तृत निविदा विज्ञप्ति, निविदा दस्तावेज व अन्य जानकारी ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल https://eproc.cgstate.gov.in से दिनांक 24.06.2026 से डाउनलोड की जा सकती है तथा निविदा डाउनलोड करने की अंतिम दिनांक 08.07.2026 (शाम 5.30 बजे) तक है।

कार्यपालन अभियंता
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड,
राजनांदगांव (छ.ग.)

जी-262701558/5

एनडीए के झटकों से उबरने कांग्रेस में लौटेंगे शरद पवार

नीरज कुमार दुबे

भारतीय राजनीति इन दिनों एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुराने रिश्तों, टूटी महत्वाकांक्षाओं और सत्ता की नई हकीकतों ने विपक्ष की राजनीति को गहरे सवालों के सामने ला खड़ा किया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की करारी हार, महाराष्ट्र में शरद पवार की कमजोर होती पकड़ और उद्धव ठाकरे के सामने खड़ा राजनीतिक संकट अब केवल क्षेत्रीय दलों की परेशानी नहीं रह गया है, बल्कि यह पूरे विपक्ष की दिशा तय करने वाला मुद्दा बन चुका है। इसी पृष्ठभूमि में कांग्रेस में घर वापसी की बहस ने अचानक जोर पकड़ लिया है। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस के विलय की अटकलों ने तब तेजी पकड़ी जब ममता बनर्जी ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और उसके बाद अभिषेक बनर्जी की राहुल गांधी के साथ लंबी बैठक हुई। हालांकि दोनों दलों ने इन खबरों को सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन इस बहस ने एक बड़ा राजनीतिक सवाल खड़ा कर दिया कि क्या भाजपा के खिलाफ मजबूत मोर्चा बनाने के लिए कांग्रेस से अलग हुए नेताओं को अब फिर उसी छतरी के नीचे लौट आना चाहिए। दरअसल ममता बनर्जी की स्थिति पहली बार इतनी कमजोर नजर आ रही है। पंद्रह साल तक बंगाल की राजनीति पर एकछत्र राज करने वाली ममता की पार्टी विधानसभा चुनाव में महज अस्सी सीटों पर सिमट गई और भाजपा ने राज्य में पहली बार सरकार बना ली। चुनावी हार के बाद संकट और गहरा गया। कई विधायक और करीबी सहयोगी भाजपा के संपर्क में चले गए। कुछ ऐसी ही कहानी शरद पवार की भी है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी बनाकर कांग्रेस से अलग रास्ता चुनने वाले पवार आज अपनी ही पार्टी और चुनाव चिन्ह पर नियंत्रण खो चुके हैं। अजित पवार के विद्रोह ने उनकी राजनीतिक ताकत को बुरी तरह झटका दिया था। उद्धव ठाकरे की हालत भी अलग नहीं है। शिवसेना पर नियंत्रण गंवाने के बाद अब उनके सांसदों में भी टूट हो गयी है। इन घटनाओं ने यह साफ कर दिया है कि जिन क्षेत्रीय दलों को कभी अपने राज्यों में अजेय माना जाता था, वह अब भाजपा के आक्रामक विस्तार और अंदरूनी बिखराव के सामने कमजोर पड़ रहे हैं। इसी माहौल में शिवसेना नेता संजय राउत ने यह विचार उछाला कि कांग्रेस से निकले दलों को फिर से मूल पार्टी में लौट आना चाहिए। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता नाना पटोले ने भी इस सोच का समर्थन किया। पहली नजर में यह तर्क मजबूत लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि भाजपा आज देश की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बन चुकी है। कभी केवल सात राज्यों तक सीमित रहने वाली पार्टी अब 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सत्ता का हिस्सा है। विपक्ष बिखरा हुआ है और कई क्षेत्रीय दल कमजोर पड़ चुके हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि ये नेता कांग्रेस छोड़कर गए ही क्यों थे? ममता बनर्जी ने वैचारिक मतभेदों के कारण कांग्रेस नहीं छोड़ी थी। उन्हें लगता था कि कांग्रेस बंगाल में वाम मोर्चे को हराने में नाकाम हो चुकी है। उन्होंने आक्रामक राजनीति का रास्ता चुना और तृणमूल कांग्रेस बनाई। नतीजा यह हुआ कि उन्होंने चौंतीस साल पुरानी वाम सत्ता को उखाड़ फेंका। शरद पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर अलग पार्टी बनाई और महाराष्ट्र में अपनी अलग पहचान कायम की। जगन मोहन रेड्डी ने भी कांग्रेस नेतृत्व से उपेक्षा महसूस करने के बाद नई पार्टी बनाई और कुछ ही वर्षों में आंध्र प्रदेश में कांग्रेस को लगभग समाप्त कर दिया। आज हालात बदले हैं तो उसकी वजह कांग्रेस की मजबूती नहीं, बल्कि भाजपा का विस्फोटक उभार है। पहले क्षेत्रीय दल कांग्रेस की खाली होती जमीन पर फैलते थे।

दलीय टूट-फूट के सवालों से मुठभेड़ जरूरी

उमेश चतुर्वेदी

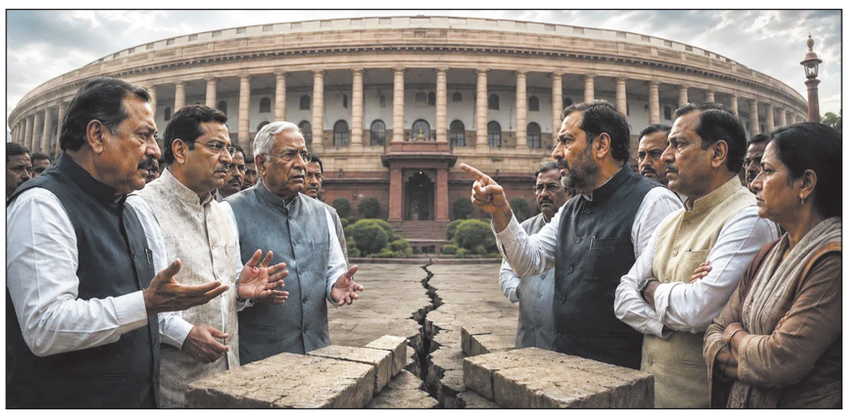

डॉक्टर लोहिया ने कहा तो था समाजवादियों से, लेकिन लगता है कि उनकी बात आज के विपक्षी दलों ने ज्यादा शिद्दत से मान ली है। लोहिया ने कहा था, सुधरो या टूट जाओ। लोहिया की इस अपील को उनके समाजवादी चेलों ने तो माना ही, अब गैर समाजवादी अनुयायी भी स्वीकार कर चुके हैं। चार मई को पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ी टूट उस ममता की पार्टी में हुई, जिन्हें राजनीतिक मैदान का योद्धा माना जाता था। जो झुकना नहीं जानतीं। पहले उनके 80 में से 53 विधायक टूट गए और विधानसभा में उन्होंने अपना अलग गुट बना लिया। इसके बाद लोकसभा के उनके 29 में से बीस सांसद भी टूट गए। दिलचस्प यह है कि उन्होंने एक अनाम-सी पार्टी नेशनल सिटिजन्स पार्टी में अपना विलय कर लिया। ममता की राह पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना के भी सांसद चल पड़े हैं और हो सकता है कि इन पंक्तियों के प्रकाशित होने तक उनके नौ में से छह लोकसभा सांसद पाला बदलकर एकनाथ शिंदे की शिवसेना के धनुष पर तीर चढ़ा रहे होंगे। सुगबुगाहट तमिलनाडु की द्रविड़ मुनेत्र कषगम् के संसदीय दल में भी टूट-फूट की दिख रही है। इस बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओमप्रकाश राजभर ने अखिलेश यादव की अगुआई वाली समाजवादी पार्टी में भी टूट की भविष्यवाणी जता दी है।

भारतीय राजनीति में दल-बदल कोई नई बात नहीं है। अतीत में भी दल-बदल होते रहे हैं। हरियाणा में तो तकरीबन पूरा विधायक दल ही दूसरे दल में समा गया था। उसी के बाद से दलबदल के लिए भारतीय राजनीति में 'आयाराम गयाराम' का मुहावरा ही चल पड़ा था। लेकिन पश्चिम बंगाल के चुनावों के बाद जिस तरह दल-बदल या दलों में टूटफूट हो रहा है, वह अप्रत्याशित है। इतने बड़े पैमाने पर राजनीतिक दलों में भगदड़ पहले नहीं हुई थी। पहले किसी एक या दो दल में ऐसा होता था। ऐसा लग रहा है कि जैसे बीजेपी विरोधी दलों को दल-बदल या टूट-फूट वाली छूत की बीमारी लग गई है। इस प्रभावित दल इस टूट-फूट के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनका आरोप है कि बीजेपी टूटने वाले नेताओं को मोटी रकम का लालच दे रही है। उनका यह भी आरोप है कि संवैधानिक सुधारों के लिए चूंकि बीजेपी को संसद के दोनों सदनों में दो तिहाई बहुमत की जरूरत है, इसलिए वह धन और बाहुबल का लालच देकर दलों को तोड़ रही है।

एक बारगी मान भी लें कि बीजेपी की शह पर ये टूट-फूट हो रही है तो एक प्रश्न जरूर उठता है कि आखिर राजनीतिक दलों ने कैसे नेताओं को अपना सांसद या विधायक बनाने के लिए चुना है? क्या उनके चयन में कोई गलती रही? सवाल यह भी उठता है कि जो टूट रहे हैं, क्या सांसद या विधायक बनाने को लेकर जब उनका चयन किया जा रहा था, तो उनकी कौन की खासियत देखी गई थी? क्या दल के प्रति न उनकी निष्ठा, उनके चरित्र आदि का ध्यान नहीं रखा गया। सवाल यह भी उठता है कि क्या बाहुबल या धन बल ही उनके चयन की बड़ी योग्यता मानी गई। इन सवालों का ईमानदारी से जवाब प्रभावित दल भले ही नहीं दे, लेकिन यह छुपी हुई बात नहीं है कि भारतीय राजनीति में संसद या विधानसभा में नुमाइंदगी के लिए दलीय निष्ठा की बजाय दूसरे कारकों का ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। इसमें चुनाव जीतने की क्षमता, चुनाव में खर्च करने की सामर्थ्य और जरूरत बड़ने पर पार्टी के लिए धन और बाहुबल के साथ खड़ा होने की शक्ति भी देखी जाती है। कई बार तो सिर्फ पैसे के दम पर ही टिकट हासिल कर लिए जाते हैं। यही वजह है कि मौका मिलते ही ये नेता अपनी निष्ठा बदलने में देर नहीं लगाते।

निश्चित तौर पर राजनीतिक दलों के गठन की बुनियाद उनका राजनैतिक और सामाजिक विचार और सिद्धांत होता है। इसके बावजूद लगातार महंगी होती चुनाव प्रक्रिया ने विचारधारा की राजनीति को पीछे खिसका दिया है। विचारधारा की दुहाई तभी तक दी जाती है, जब तक उसकी राह में धन बल या बाहुबल नहीं आता, जब तक कि सत्ता उससे दूर रहती है। अगर विचारधारा से विचलन के बाद सत्ता आती दिखती है तो राजनीतिक दल और नेता भी अपनी उस विचारधारा को कुछ वक्त के लिए ताक पर रख देते हैं। सिद्धांत और निष्ठाएं भी तब तक के लिए टाल दी जाती हैं। जब दलीय आधार पर ऐसा होता है तो निजी स्तर पर किसी सांसद और विधायक को आर्थिक या सत्ता में भागीदारी का मौका मिलेगा तो वह क्यों न टूटेगा। सवाल यह है कि जब दल और उसका अगुआ ही अपनी निष्ठा और विचारधारा को सत्ता के लिए किनारे रख देगा तो मौका मिलने पर उसका सांसद और विधायक ऐसा क्यों नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे के संसदीय दल में बिखराव की बड़ी वजह सत्ता के लिए पार्टी के सिद्धांतों से समझौता और कांग्रेस का साथ लेना रहा है।

टूट रहे सांसदों को लेकर आरोप लगाने वाले दलों को भी सोचना होगा कि आखिर उन्होंने किस तरह के लोगों को चुना? सवाल यह है कि जब पैसे लेकर टिकट दिए जाएंगे, जब दल और विचारधारा की निष्ठा के बजाय चुनावी टिकट हासिल करने के अन्य कारण होंगे तो फिर इस प्रक्रिया से चुनकर आए सांसदों और विधायकों की खरीद-बिक्री पर सवाल कैसे उठाए जा सकते हैं? कैसे उन्हें दलीय निष्ठा के प्रति बांधे रखा जा सकता है।

दलीय टूट-फूट का अभी कोई बड़ा नुकसान भले ही नहीं दिख रहा हो, लेकिन आने वाले दिनों में इसका एक बड़ा हश्र लोक विश्वास के दरकने के रूप में दिख सकता है। आज का मतदाता बहुविध सूचनाओं के तमाम स्रोतों से लैस है। उसकी राजनीतिक समझ पहले के मीडिया क्रांति केदौर के पहले के मतदाताओं की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित है। उसका सामान्य ज्ञान कमजोर भले ही हो सकता है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया और उसमें आ रहे निष्ठागत बदलावों की पृष्ठभूमि को वह समझ रहा है। ऐसे में उसका भरोसा मौजूदा राजनीतिक तंत्र से चूक सकता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से उसका भरोसा टूटना लोकतंत्र के लिए खतरनाक हो सकता है। दल बदलने वाले अपने प्रतिनिधि के बारे में वह सवाल उठा सकता है कि उसने जिस सोच के साथ उसे वोट दिया, उसका प्रतिनिधि उस सोच के साथ गद्दारी कर रहा है। कई बार स्थानीय कारणों के साथ ही अपनी वैचारिक निष्ठा के चलते भी अपना मत देता है।

हो सकता है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी दल विशेष को बड़ा समर्थन मिला हो, लेकिन उसी दल विशेष के किसी स्थानीय प्रतिनिधि को स्थानीय निष्ठाओं, जरूरतों और कारकों के साथ ही वैचारिक कारणों से मतदाताओं का समर्थन नहीं मिलता। मान लेते हैं कि राष्ट्रीय या राज्य स्तर पर किसी दल विशेष को भारी समर्थन मिला है, लेकिन स्थानीय स्तर पर इसके ठीक उलट किसी अन्य दल या उसके प्रतिनिधि को समर्थन मिला है। इसका मतलब यह है कि राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन हासिल करने वाले दल के कार्यक्रमों और योजनाओं की बजाय स्थानीय योजनाओं को लेकर स्थानीय लोगों की अपनी अलग दृष्टि है, या अपनी अलग चाहत है।

स्थानीय मतदाताओं का भरोसा उसे इसी वजह से मिला है। लेकिन उसका प्रतिनिधि अपनी निष्ठा बदल लेता है कि स्थानीय मतदाता खुद को आहत और ठगा हुआ महसूस कर सकता है। चूंकि इन दिनों दलीय टूट-फूट व्यापक स्तर पर हो रही है, इसलिए मतदाताओं में इसका व्यापक असर पड़ सकता है। इसके चलते मतदाता आहत महसूस कर स0कते हैं, विश्वासघात भी मान सकते हैं। इससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर भरोसा कमजोर हो सकता है। मौजूदा राजनीतिक तंत्र को मतदाताओं के मनमिजाज को इस नजरिए से भी समझना होगा। भारतीय लोकतंत्र को भरोसेमंद बनाने की राह राजनीतिक दलों को ही खोजना होगा। क्योंकि लोहिया की टूटने की अपील के पीछे भी सुधार को खोजना था। लेकिन सवाल यह है कि क्या राजनीतिक दल संपूर्णता में इस सवाल से मुठभेड़ करने को तैयार हैं?

पुराण दिग्दर्शन ....

सन्देहाभासनिकारणाध्यायः (नौवां अध्याय)

(गतांक से आगे...)

बदनी के सौदे, घुड़ दौड़ या बरसात के सट्टे, तथा लाटरी, प्रत्येक शहर में बड़ से बड़े सभ्य सेठ साहूकार -गर्दा तक की राजा और सम्राट भी आये दिन लगाते हैं। यद्यपि यह भी एक प्रकार का जुआ ही है और खतरे से भी खाली नहीं, तथापि प्रवृत्ति मार्ग वाले लोगों के लिये एक अंश तक लाभकारी तथा मनोरंजन का साधन है अतः शास्त्र और लोक-व्यवहार में इसे अपराध नहीं समझा जाता।

पुराणों के जिन प्रमाणों को उद्धत करके महाशय जी प्रश्न कर रहे हैं इनमें समाह्वय का ही विधान किया गया है जिह्म का नहीं।

जैसे कुर्यान्महोत्सवं राजा में कहा गया है कि राजा को दीवाली के मौके पर 7 या 6 दिन का एक महोत्सव मनाना चाहिये, जिसमें अनेक गाने बजाने वाले अपनी 2 कला दिखायें तथा द्यूत (घुड़दौड़, मल्लयुद्ध, बदनी के सौदे, और लाटरी आदि) का भी प्रबन्ध किया जाय।

आज भी जर्मनी, जापान, अमेरिका और इंग्लैंड जैसे प्रगतिशील देश युवक-वर्ग को साहसी बनाने के लिये ऐसे मनोरंजनकारक महोत्सव मनाते हैं। इसीलिए वे मुठ्ठीभर आदमी संसार के अरबों मनुष्यों पर शासन कर रहे हैं। परन्तु हमारे कूपमण्डूक कर्मानन्द जी को इस राष्ट्रीय उत्थान के समय में भी युवकवृन्द के साहस को प्रोत्साहन देने वाले ऐसे ऐसे आषं विधान वेद प्रतिकूल जंचते हैं, इसे मस्तिष्कदासता के सिवा और क्या कहा जा सकता है?

वेश्याओं की मुक्ति का अपूर्व उपाय

भविष्यपुराण उत्तर पर्व 4 अध्याय 111 श्लोक 41 से अध्याय-समाप्ति पर्यन्त।

यथेष्टाहारभुक्तञ्च तमेव द्विजसत्तमम्।
रत्यर्थं कामदेवोऽयमिति चित्तेऽवधार्य च ॥44॥

क्रमशः ...

विश्व शरणार्थी दिवस

अमृता गोस्वामी

शरणार्थी वह लोग होते हैं जो हिंसा, संघर्ष, युद्ध, उत्पीड़न या प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ या भूकंप जैसी मुसीबतों के चलते असहाय, लाचार और निराश्रय होकर अपने देश और घरों को छोड़कर किन्ही अन्य देशों में शरण लेने पर मजबूर हुए हों। 'विश्व शरणार्थी दिवस' ऐसे ही विस्थापित लोगों के साहस, शक्ति और संकल्प को प्रतिष्ठित करने और उनकी समस्याओं को समझने के लिए प्रतिवर्ष 20 जून को मनाया जाता है। शरणार्थियों को अंग्रजी भाषा में 'रिफ्यूजी' कहा जाता है।

आपदा-विपदा से ग्रसित कोई एक व्यक्ति भी शरणार्थी हो सकता है और बहुत सारे लोगों का समूह भी। सीरिया में हुई जंग तो आपको याद ही होगी जिसके चलते वहां के लाखों लोगों को अन्य देशों की शरण में जाना पड़ा। भारत की बात करें तो यहां काफी संख्या में तिब्बत और बांग्लादेश से आए शरणार्थी आपको मिल जाएंगे। म्यांमार, लीबिया, सीरिया, अफ़गानिस्तान, यूनान, मलेशिया व कई अफ्रीकी देशों से भी प्रतिवर्ष लाखों की संख्या में नागरिक अन्य देशों में शरणार्थी बनकर पहुंचते हैं। वेनेजुएला जैसे देश में आर्थिक संकट के चलते नागरिक को मजबूरीवश दूसरे देशों की शरण लेना पड़ रही हैं। शरणार्थियों के जीवन-यापन, उनके मानसिक व शारीरिक स्वास्थ्य तथा अन्य जरूरतों के लिए कई देशों में कई संस्थाएं काम कर रही हैं। संयुक्त राष्ट्र की संस्था यूएनएचसीआर (यूनाइटेड नेशन्स हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूज़ी) एक ऐसी ही संस्था है जो शरणार्थियों की मदद के लिए, उन्हें कानूनी हक दिलाने और उन्हें पुन: अपना जीवन बसर करने के प्रति उपयुक्त हल तलाशने में उनकी सहायता करती है। इस कार्य के लिए यूएनएचसीआर को 1954 व 1981 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है।

गौरतलब है कि अफ्रीकी देशों की एकता को अभिव्यक्त करने के लिये 4 दिसंबर, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था जिसमें ऑर्गनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी (ओएयू) अंतर्राष्ट्रीय शरणार्थी दिवस को अफ्रीकी शरणार्थी दिवस के साथ 20 जून को मनाने के लिये सहमत हुआ था, उसके बाद 2001 से प्रतिवर्ष दुनिया भर में 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जा रहा है।

इंटरनेशनल रेस्क्यू कमिटी और एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व शरणार्थी दिवस पर कई गतिविधियाँ आयोजित करते हैं। दोस्तों, अपने देश अपने घरों से विस्थापन के कारण शरणार्थियों को सामाजिक विघटन, असुरक्षा की भावना, नए वातावरण से तालमेल न बैठा पाना, बेरोजगारी और भूख जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आज 20 जून यानि विश्व शरणार्थी दिवस है इस विशेष दिन हर किसी का कर्तव्य है कि शरणार्थियों के प्रति प्रेम और मानवता का भाव रखते हुए उन्हें समस्याओं से निपटने में उनकी हर संभव मदद करें।

फ्रांस में ट्रंप-मोदी की मुलाकात के वैश्विक कूटनीतिक निहितार्थ

कमलेश पांडे

जब दुनिया के दो बड़े लोकतांत्रिक देशों के मशहूर राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो दुनियावी जनकल्याण की बातें अवश्य छिड़ती हैं। हाल ही में जब फ्रांस में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात हुई तो इसे केवल द्विपक्षीय शिष्टाचार भर नहीं मानी जा रही, बल्कि इसके व्यापक राजनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक संकेत मिले हैं।

वहीं, नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच हालिया मुलाकात को कई विश्लेषक केवल औपचारिक कूटनीतिक संवाद नहीं, बल्कि व्यक्तिगत समीकरणों को पुनर्जीवित करने की कोशिश के रूप में भी देख रहे हैं। हालांकि यह कहना जल्दबाजी होगी कि दोनों के रिश्तों पर जमी पूरी बर्फ पिघल गई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि दोनों नेताओं ने सार्वजनिक रूप से सकारात्मक संकेत देने का प्रयास किया है।

इस मुलाकात में सबसे बड़ी बात तो यह हुई कि अमेरिका ने भारत को आश्वस्त किया है कि मोदी काल में यदि भारत के ऊपर कोई हमला होता है तो यूएस यानी अमेरिका भारत के साथ रहेगा। हालांकि उनकी इस आश्वस्ति भाव के कूटनीतिक मायने भी बड़े दिलचस्प होंगे, जिसकी चर्चा मैं आगे करूँगा।

सवाल है कि क्या व्यक्तिगत रिश्ते सामान्य हो रहे हैं? तो जवाब होगा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में Howdy Modi और Namaste Trump जैसे आयोजनों ने दोनों नेताओं की व्यक्तिगत निकटता की छवि बनाई थी। बाद के वर्षों में कुछ मुद्दों—व्यापार, वीजा, रूस से भारत के संबंध और अमेरिकी घरेलू राजनीति—के कारण रिश्तों में उतनी गर्मजोशी सार्वजनिक रूप से दिखाई नहीं दी। जबकि हालिया मुलाकात से संकेत मिलता है कि दोनों नेता व्यक्तिगत संवाद की लाइन खुली रखना चाहते हैं। क्योंकि रणनीतिक हित व्यक्तिगत मतभेदों से अधिक महत्वपूर्ण हैं। भारत और अमेरिका दोनों बदलते वैश्विक समीकरणों में एक-दूसरे की आवश्यकता महसूस कर रहे हैं।

सबसे पहले मोदी-ट्रंप मुलाकात के अंतरराष्ट्रीय निहितार्थ की चर्चा कर लेते हैं, जो इस प्रकार है-

पहला, भारत-अमेरिका रणनीतिक साझेदारी की पुनर्पुष्टि: वैश्विक स्तर पर चीन के बढ़ते प्रभाव, हिंद-प्रशांत क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा और नई भू-राजनीतिक चुनौतियों के बीच यह मुलाकात दोनों देशों की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने का संदेश देती है। साथ ही, रक्षा सहयोग और तकनीकी साझेदारी पर जोर डालती है, क्योंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शक्ति संतुलन बनाए रखने की साझा चिंता दोनों देशों को है। इसलिए समुद्री सुरक्षा और आपूर्ति श्रृंखला सहयोग को बढ़ावा देने के लिए दोनों देश आगे आ चुके हैं।

दूसरा, भारत के प्रतिद्वंद्वी चीन के लिए महत्वपूर्ण संकेत: यह मुलाकात अप्रत्यक्ष रूप से चीन को संदेश देती है कि भारत और अमेरिका क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर संवाद बनाए हुए हैं। दक्षिण चीन सागर और हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की गतिविधियों पर नजर दोनों देशों की नजर है। लिहाजा क्वाड जैसी व्यवस्थाओं को मजबूती मिलने की संभावना है। इससे एशिया में शक्ति संतुलन की राजनीति को बल मिलेगा। हालांकि, भारत को अमेरिकी चालों के परिप्रेक्ष्य में सावधानी भी बरतनी होगी, उसके मतलबी इतिहास के दृष्टिगत।

तीसरा, रूस-यूक्रेन और वैश्विक संघर्षों पर संवाद: चूंकि भारत रूस और पश्चिमी देशों के बीच संतुलित कूटनीति अपनाता रहा है। इसलिए भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की नीति पर चर्चा भी संभव हुआ है। वहीं रूस-यूक्रेन वार और पश्चिम एशिया की स्थिति पर भी विचार-विमर्श हुआ होगा। क्योंकि इन मामलों में अमेरिका, भारत को संभावित मध्यस्थ या संवाद-सहयोगी के रूप में देखने का आदी बन चुका है और इसमें अमेरिकी रुचि भी अस्वाभाविक नहीं है।

चौथा, व्यापार और निवेश के मायने: दोनों देशों के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। उच्च तकनीक, सेमीकंडक्टर, एआई और रक्षा उत्पादन में सहयोग बढ़ा है। अमेरिकी निवेश आकर्षित करने की भारतीय कोशिशों को बल मिला है। साथ ही आपूर्ति श्रृंखलाओं को चीन पर निर्भरता से हटाने की रणनीति में भारत की भूमिका बढ़ी है।

पांचवां, भारत की वैश्विक प्रतिष्ठा में वृद्धि: यह मुलाकात दर्शाती है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण वैश्विक खिलाड़ी के रूप में देखा जा रहा है। जी-7 और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर भारत की बढ़ती स्वीकार्यता भी इस बात को जाहिर करती है। वहीं वैश्विक दक्षिण की आवाज के रूप में भारत की भूमिका मजबूत हुई है। खासकर ऊर्जा, जलवायु और विकास संबंधी मुद्दों पर भारत की अहमियत बढ़ना इसी बात का द्योतक है।

छठा, घरेलू राजनीतिक मायने: भारत में सरकार इसे भारत की बढ़ती अंतरराष्ट्रीय प्रतिष्ठा के प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकती है। विदेश नीति की उपलब्धियों को राजनीतिक विमर्श में प्रमुखता मिल सकती है। जबकि अमेरिका में ट्रंप प्रशासन के लिए भारत के साथ निकट संबंध एशिया नीति का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। भारतीय-अमेरिकी समुदाय के संदर्भ में भी यह राजनीतिक रूप से उपयोगी संदेश माना जा सकता है।

सातवां, फ्रांस की भूमिका भी महत्वपूर्ण : चूंकि यह मुलाकात भारत के मित्र फ्रांस की उपस्थिति में हुई, इसलिए इसका एक त्रिपक्षीय आयाम भी है। दरअसल फ्रांस, भारत और अमेरिका के बीच रक्षा एवं प्रौद्योगिकी सहयोग के नए अवसर पैदा हुए हैं। साथ ही इंडो-पैसिफिक में फ्रांस की सक्रिय भूमिका को समर्थन मिला है। इससे यूरोप-भारत-अमेरिका सहयोग के नए समीकरण बने हैं, जो भारत के दूरगामी हित में हैं।

जहां तक दुनिया के अन्य देशों पर मोदी-ट्रंप मुलाकात के संभावित प्रभाव की बात है तो

पहला, चीन पर प्रभाव: चीन इस मुलाकात को ध्यान से देखेगा, क्योंकि भारत-अमेरिका सहयोग मजबूत होने पर चीन को एशिया में अधिक संतुलित प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। चूंकि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत की भूमिका और महत्वपूर्ण हो सकती है। इसलिए चीन भारत के साथ संबंधों को स्थिर रखने की कोशिश भी बढ़ा सकता है ताकि वह दो मोर्चों पर दबाव न झेले।

दूसरा, रूस पर प्रभाव: रूस के लिए यह मिश्रित संकेत है, क्योंकि रूस समझता है कि भारत अमेरिका के साथ भी मजबूत संबंध रखेगा। इससे भारत की बहुध्रुवीय कूटनीति और मजबूत होगी। मॉस्को भारत को अपने प्रभाव क्षेत्र में बनाए रखने के लिए रक्षा और ऊर्जा सहयोग बढ़ा सकता है।

तीसरा, यूरोप पर प्रभाव: फ्रांस, जर्मनी और अन्य यूरोपीय देश इसे सकारात्मक रूप से देख सकते हैं। भारत पश्चिम और वैश्विक दक्षिण के बीच पुल की भूमिका निभा सकता है।यूरोपीय देशों के लिए भारत और भी आकर्षक रणनीतिक साझेदार बन सकता है। रक्षा और हरित प्रौद्योगिकी सहयोग में नए अवसर खुल सकते हैं।

चौथा, पाकिस्तान पर प्रभाव : पाकिस्तान इस घटनाक्रम को सावधानी से देखेगा। भारत-अमेरिका निकटता पाकिस्तान की रणनीतिक चिंताओं को बढ़ा सकती है। हालांकि अमेरिका पाकिस्तान के साथ भी संबंध बनाए रखेगा, लेकिन दक्षिण एशिया में भारत का महत्व अपेक्षाकृत अधिक बना रहेगा।

पांचवां, खाड़ी और अरब देशों पर प्रभाव: सउदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देश भारत-अमेरिका समन्वय को अवसर के रूप में देख सकते हैं। ऊर्जा, निवेश और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर परियोजनाओं को गति मिल सकती है। भारत की मध्य-पूर्व में कूटनीतिक भूमिका मजबूत हो सकती है।

आज का इतिहास

1819 320 टन की सवाना, किसी भी महासागर (अटलांटिक) को पार करने वाली पहली स्टीमशिप बन गई।
1837 विक्टोरिया ने ब्रिटिश सिंहासन के लिए कामयाबी हासिल की, जो कि 63 वर्षों से अधिक समय तक राज करता रहा।
1840 सैमुअल मोर्स ने टेलीग्राफ का पेटेंट कराया।
1862 रोमानिया के प्रधानमंत्री बार्बू कटारगिउ की हत्या की गई।
1863 पश्चिमी वर्जीनिया अमेरिका का 35वां राज्य बना।
1866 इटली की किंगडम ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ युद्ध की घोषणा की
1874 लुसियन क्लेमन्स को प्रथम यूएस लाइफशविंग मेडल से सम्मानित किया गया।
1877 अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने कनाडा के ओंटारियो में दुनिया का पहला वाणिज्यिक टेलीफोन सेवा शुरू की।
1895 कील नहर, जुटलैंडपिनसुला के आधार को पार करते हुए और दुनिया के सबसे व्यस्त कृत्रिम जलमार्ग, को खुलेआम खोला गया था।
1900 बॉक्सर विद्रोह-इंपीरियल चीनी सेना ने बीजिंग में लीजेशन क्वार्टर की 55 दिन की घेराबंदी शुरू की।
1931 कार्ल ब्यूरेश आस्ट्रिया के कुलपति बनाये गए।
1943 न्यू जॉर्जिया अभियान शुरू हुआ।
1943 बेले आइल, डेट्रायट, मिशिगन में अश्वेतों और गोरों के बीच दंगे शुरू हुए और तीन दिनों तक जारी रहे।
1947 कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में एक माफिया हिटमैन ने गैंगस्टर बगसी सिएगल की हत्या कर दी।
1960 माली फेडरेशन (बाद में माली और सेनेगल में विभाजन) को फ्रांस से स्वतंत्रता मिली।
1963 व्हाइट मिसाइल और क्रेमलिन के बीच तथाकथित लाल टेलीफोन स्थापित किया गया था, क्यूबाई मिसाइल संकट के बाद कि दोनों देशों के बीच असीमित संचार आवश्यक थे।
1991 एकीकृत जर्मनी की राजधानी फिर से बर्लिन को बनाने के प्रस्ताव को संसद ने मंजूरी दी।
2001 जनरल परवेज मुशर्रफ़ पाकिस्तान के राष्ट्रपति बने।
2005 रूस मालवाहक यान एम-53 अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पहुँचा।
2009 ईरानी चुनाव विरोध के दौरान, नेदा आगा-सोलटन की मौत को वीडियो पर कैप्चर किया गया और इंटरनेट पर व्यापक रूप से वितरित किया गया, जिससे यह %मानव इतिहास में संभवत: सबसे व्यापक रूप से देखी जाने वाली मौत% बन गई।
2012 लीबिया में सामुदायिक हिंसा में 105 लोगों की मौत, 500 घायल।

असम-नगालैंड के बीच दशकों का विवाद खत्म, शाह ने पूर्वोत्तर का भाग्य ही बदल दिया

नीरज कुमार दुबे

ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही मोदी सरकार को पूर्वोत्तर से एक बड़ी रणनीतिक सफलता मिली है। केंद्र, असम और नगालैंड के बीच तेल और प्राकृतिक गैस अन्वेषण को लेकर हुआ त्रिपक्षीय समझौता भारत को ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के अभियान का निर्णायक अध्याय है। दशकों से विवाद और अस्थिरता में फंसे असम, नगालैंड सीमा क्षेत्र में तेल खोज का रास्ता खोलकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस मिशन को नई ताकत दे दी है, जिसका लक्ष्य विदेशी तेल निर्भरता घटाकर भारत को ऊर्जा महाशक्ति बनाना है। यही वजह है कि अमित शाह ने इसे विकसित पूर्वोत्तर और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया है।

हम आपको बता दें कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में भारत सरकार, असम सरकार और नगालैंड सरकार के बीच असम-नगालैंड सीमावर्ती क्षेत्रों में खनिज तेल संचालन के संबंध में एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस मौके पर केन्द्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा और नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो सहित केंद्र, असम एवं नगालैंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। अमित शाह ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताते हुए साफ कहा कि इस समझौते ने विकसित पूर्वोत्तर के रास्ते में खड़ी अंतिम बड़ी बाधा हटा दी है।

हम आपको बता दें कि असम और नगालैंड की सीमा से लगे विवादित क्षेत्र में तीन दशक से अधिक समय से तेल और खनिज अन्वेषण ठप पड़ा था। अधिकार क्षेत्र को लेकर दोनों राज्यों के बीच तनाव बना रहता था, जिसके कारण हजारों करोड़ रुपये की संपदा जमीन के नीचे दबी रह गई। अब इस समझौते के तहत एक हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में तेल, गैस और खनिज संसाधनों की खोज और उत्पादन का रास्ता खुल गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों राज्यों ने संसाधनों के बंटवारे पर 50-50 की सहमति बनाई है। यही वह राजनीतिक परिपक्वता है जिसने इस समझौते को टकराव से निकालकर साझेदारी के मॉडल

में बदल दिया।

अमित शाह ने दावा किया कि इस एक समझौते से प्रतिदिन एक हजार से पंद्रह सौ बैरल तेल उत्पादन क्षमता को दस गुना तक बढ़ाया जा सकता है। केवल एक तेल क्षेत्र से पंद्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक की संभावित प्राप्ति का अनुमान जताया गया है। यह बयान केवल आर्थिक संभावना का संकेत नहीं, बल्कि उस रणनीतिक दिशा का संकेत है जिसमें भारत तेजी से आगे बढ़ना चाहता है। वैश्विक भू-राजनीतिक तनाव, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और ऊर्जा आपूर्ति संकटों के दौर में भारत लंबे समय से आयातित तेल पर निर्भरता घटाने की कोशिश कर रहा है। ऐसे समय में पूर्वोत्तर के विशाल तेल और गैस भंडार भारत के लिए नई ऊर्जा रीढ़ साबित हो सकते हैं।

दरअसल यह समझौता केवल तेल निकालने का मसला नहीं है। यह पूर्वोत्तर को संघर्ष की पहचान से निकालकर सामरिक और आर्थिक शक्ति केंद्र में बदलने की कवायद है। अमित शाह ने कहा कि यदि नगालैंड में फैले तेल और गैस भंडार का पूरा दोहन हुआ तो भारत विदेशी देशों पर अपनी ऊर्जा निर्भरता काफी हद तक कम कर सकेगा। इसका सीधा मतलब है कि भारत अपने ऊर्जा हितों को लेकर अधिक स्वतंत्र रणनीति अपना सकेगा। देखा जाये तो ऊर्जा आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक मुद्दा नहीं होती, यह राष्ट्रीय सुरक्षा का मूल तत्व बन चुकी है।

साथ ही इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा बड़ा पहलू सुरक्षा और शांति से जुड़ा है। अमित शाह ने पूर्वोत्तर में हिंसा की घटनाओं में लगभग अस्सी प्रतिशत गिरावट का दावा करते हुए कहा कि वर्ष 2019 के बाद 12 शांति समझौते हुए हैं। यही कारण है कि अब सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम को भी पूर्वोत्तर के अधिकांश हिस्सों से हटाने की तैयारी चल रही है। अमित शाह ने विश्वास जताया कि अगले वर्ष एक या दो राज्यों को छोड़कर पूरे पूर्वोत्तर से यह कानून हटाया जा सकता है। यह बयान बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि दशकों तक पूर्वोत्तर की पहचान उग्रवाद, सैन्य उपस्थिति और अस्थिरता से जुड़ी रही है। अब केंद्र सरकार यह संदेश देना चाहती है कि क्षेत्र संघर्ष से विकास की ओर बढ़ चुका है।

रणनीतिक दृष्टि से देखें तो यह समझौता चीन और दक्षिण पूर्व एशिया से जुड़ी भारत की व्यापक नीति से भी मेल खाता है। पूर्वोत्तर भारत लंबे समय तक केवल भौगोलिक सीमा माना जाता रहा, लेकिन अब उसे आर्थिक गलियारे, ऊर्जा केंद्र और संपर्क सेतु के रूप में विकसित किया जा रहा है। सड़क, रेल, निवेश, पर्यटन और ऊर्जा परियोजनाओं के जरिए केंद्र सरकार इस क्षेत्र को राष्ट्रीय विकास की मुख्यधारा में लाने की कोशिश कर रही है। तेल और गैस परियोजनाओं के सक्रिय होने से निजी निवेश बढ़ेगा, रोजगार पैदा होंगे और क्षेत्रीय असंतोष कम होगा। यही वह बिंदु है जहां विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक दूसरे के पूरक बन जाते हैं।

असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने भी कहा कि यह समझौता देश की दीर्घकालिक ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा। वहीं नगालैंड के मुख्यमंत्री नेफियू रियो की सहमति इस बात का संकेत है कि अब पूर्वोत्तर की राजनीति टकराव से अधिक आर्थिक साझेदारी की दिशा में बढ़ रही है। यही कारण है कि अमित शाह ने इसे जीत हार का नहीं, बल्कि सबकी जीत का समझौता बताया।

बहरहाल, अब स्पष्ट है कि यह त्रिपक्षीय समझौता केवल सीमाई विवाद सुलझाने का प्रयास नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर के भविष्य को नए सिरे से परिभाषित करने की शुरुआत है। यदि सरकार अपने दावों के अनुरूप तेल उत्पादन, निवेश और शांति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में सफल रहती है, तो आने वाले वर्षों में पूर्वोत्तर भारत की ऊर्जा शक्ति, सामरिक मजबूती और आर्थिक विस्तार का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र बन सकता है।

सनातन व नारी सम्मान पर बड़ी लकीर खींचते योगी आदित्यनाथ

मृत्युंजय दीक्षित

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राजनीति से ऊपर उठकर सनातन धर्म तथा स्त्री गरिमा तथा सम्मान के हित में बड़ी रेखाएं खींच रहे हैं। इसी क्रम में उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी के प्रति सोशल मीडिया के माध्यम से आपत्तिजनक बयानबाजी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने केआदेश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद अपराधियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गयी है। मुख्यमंत्री ने सख्ती के साथ कहा है कि किसी भी बेटी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी स्वीकार्य नहीं होनी चाहिए हर बेटी का सम्मान होना चाहिए। हम उन संस्कारों में पले -बढ़े हैं जहां गांव की बेटी-बहन को पूरे गांव की बेटी -बहन माना जाता है। मुख्यमंत्री योगी बेटियों की सुरक्षा के लिए संकल्पवान हैं। वह कई जनसभाओं मे अपना मंतव्य स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर किसी ने बेटियों की सुरक्षा में सेंध लगाने का प्रयास किया तो अगले चैराहे पर उसका इंतजार यमराज कर रहा होगा। योगी जी के बयानों का असर धरातल पर भी दिखाई पड़ता है। बेटियों के साथ होने वाली अप्रिय घटनाओं पर त्वरित कार्यवाही हो रही है। आरोपियों का हाफ एनकाउंटर हो रहा है तथा आवश्यकता पड़ने पर बुलडोजर एक्शन भी हो रहे हैं। प्रदेश में नारी समाज को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। नवरात्रि के अवसर पर मिशन शक्ति जैसे अभियान चलाए जा रहे हैं। केंद्र व राज्य सरकार की योजनाओं के माध्यम से नारी सशक्तीकरण का महाअभियान चलाया जा रहा है। सपा मुखिया अखिलेश यादव की बेटी पर टिप्पणी करने वालों के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा रवैया दिखाकर सपा मुखिया अखिलेश यादव द्वारा बुने जा रहे चक्रव्यूह को एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया है। सपा मुखिया अखिलेश की बेटी अदिति पर सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के बाद मुख्यमंत्री योगी ने जो एक्शन लिया है उसने इस दुखद घटना पर बनाए जा रहे सपा के राजनैतिक नैरेटिव को ध्वस्त कर दिया है। जब सोशल मीडिया के माध्यम से यह विवाद बड़े राजनीतिक तूफान में बदल रहा था और सपा योगी जी व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह कहकर घेरने का प्रयास कर रही थी कि, जिनका खुद का परिवार नहीं वो परिवार का दर्द क्या समझेंगे तब योगी जी इस घटना के जिम्मेदार लोगों को ढूंढ रहे थे। योगी जी ने अपराधियों पर तुरंत एफआईआर कराने के निर्देश जारी करते हुए कहा कि वह किसी भी बेटी क्यों न हो बेटी पर अभद्र टिप्पणी बर्दाश्त नहीं है। यूपी चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने अपने इस कदम से सिद्ध कर दिया है कि महिला सुरक्षा और सम्मान के मामले में उनकी सरकार बिना किसी भेदभाव के काम करती है। इससे सपा मुखिया रक्षात्मक रुख अपनाने को बाध्य हो गए हैं। अब भाजपा सपा के पुराने बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट्स को लेकर उस पर हमलावर है। जो मुद्दा सरकार को घेरने के लिए तैयार किया जा रहा था उस पर योगी जी की प्रशासनिक और राजनीतिक सूझबूझ का बुलडोजर चल गया है। समाजवादी पूर्व में कई बार नारी सम्मान व उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाली बयानबाजी करते रहे हैं। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ने एक बार कहा था कि लड़के हैं गलतियां हो जाती हैं। सपा के कद्दावर नेता माने जाने वाले आजम खां जैसे नेता तो कई बार महिलाओं की गरिमा के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर चुके हैं। मायावती जी पर तो सपाइयों ने हमला ही बोल दिया था। सपा राज में महिला सुरक्षा की कितनी बुरी स्थिति थी यह हर कोई जानता है। योगी की पाती दे रही सनातन विचार-विश्व वृद्धजन दुर्व्यवहार जागरुकता दिवस पर योगी जी ने एक पाती जारी की है। इस पाती में उन्होंने वृद्धजनों की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए लिखा है कि उम्र के अमृतकाल में वृद्धजनों को अपनत्व की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, दुर्भाग्य से समाज ऐसे समय का साक्षी बन रहा है जब वृद्धजनों को अपनों का दुर्व्यवहार सहना पड़ता है। योगी जी ने आगे लिखा है कि सनातन संस्कृति में माता-पिता और गुरु को साक्षात ईश्वर माना जाता है। पाती में योगी ने एक प्राचीन कथा के माध्यम से इस विषय को समझाया। भगवान शिव-पार्वती ने पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय के समक्ष समस्त जगत की परिक्रमा की चुनौती रखी। भगवान गणेश ने माता-पिता को ही संपूर्ण सृष्टि मानकर उनकी परिक्रमा कर ली।

1948 के राजनीति की झलक 2026 में

सनत जैन

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो अभिनेता से नेता बने थलापति विजय ने तमिलनाडु की राजनीति में नई शुरुआत की है। 1948 से 1952 में जिस तरह की राजनीति देश में हो रही थी, उसकी यादों को ताजा कर रही है। तमिलनाडु में विजय की पार्टी टीवीके को कांग्रेस ने समर्थन दिया है। तमिलनाडु सरकार में कांग्रेस पार्टी का एक मंत्री भी है। तमिलनाडु में कांग्रेस का कोई विशेष वर्चस्व नहीं है। केंद्रीय राजनीति में कांग्रेस एक महत्वपूर्ण भूमिका में है। आज भी कांग्रेस पार्टी का सीधा मुकाबला 300 लोकसभा सीटों पर भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों के साथ होता है। वर्तमान की राजनीति में जिस तरह से राजनीतिक दलों के बीच में वैमनष्य देखने को मिलता है, जिस तरह की असुरक्षा की भावना देखने को मिलती है।

सत्ता में ज्यादा से ज्यादा सहभागिता मिले इसके लिए राजनीतिक दल हर संभव प्रयास करते हैं इसके विपरीत तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय ने राज्यसभा की दो सीटें सहयोगी दल कांग्रेस को देने का फैसला किया है। उनका मानना है, उनकी पार्टी केंद्र की राजनीति में कांग्रेस के साथ सहयोग करके तमिलनाडु के हितों का संरक्षण ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकती है। दो सांसद उनकी पार्टी के राज्यसभा में चले भी गए, तो वह तमिलनाडु का पक्ष सशक्त तरीके से नहीं रख सकते हैं जितने सशक्त तरीके से कांग्रेस उनकी लड़ाई केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में लड़ सकती है। गठबंधन की राजनीति में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री का यह निर्णय, स्वतंत्रता के पश्चात अनूठा है। जब संविधान सभा और केंद्रीय मंत्रिमंडल का निर्माण हो रहा था, उस समय कांग्रेस पार्टी ने सभी समुदाय और सभी राजनीतिक दलों के लोगों को संविधान सभा और मंत्रिमंडल में स्थान देकर मजबूत संविधान और मजबूत सरकार बनाने का काम किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मंत्रिमंडल में अपने विरोधी और अन्य विचारधारा के लोगों को भी शामिल करके स्वतंत्रता के पश्चात समन्वय की राजनीति का मार्ग अपनाया था। वही मार्ग 2026 में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री द्वारा अपनाया गया है।

वर्तमान में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन के रूप में देश के अधिकांश राजनीतिक दल गठबंधन की राजनीति में शामिल हैं। क्षेत्रीय दल एक-एक सीट के लिए अपनी मजबूत दावेदारी रखते हैं। ऐसी स्थिति

में तमिलनाडु की राजनीति में मुख्यमंत्री थलापति विजय ने कांग्रेस को राज्यसभा की रिक्त दो सीटें देकर गठबंधन की राजनीति को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है। राज्य की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का बहुत बड़ा योगदान होता है।

क्षेत्रीय राजनीति में भाषा संस्कृति तथा आम जनता के साथ उनका जुड़ाव गहरा होता है। लेकिन केंद्रीय राजनीति में राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार को निर्णय करने पड़ते हैं। संघीय व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध बेहतर हों। पिछले एक दशक में इस स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। मोदी सरकार के अस्तित्व में आते ही योजना मंडल को भंग कर दिया गया था। उसके स्थान पर नीति आयोग बनाया गया, नीति आयोग जिस तरीके से काम कर रहा है। उसके बाद से राज्य सरकारें आरोप लगाती रही हैं, केंद्र सरकार उनके साथ न्याय नहीं कर रही है। मनमाने तरीके से संसाधन और धन का बंटवारा किया जा रहा है। जिन राज्यों में गैर भाजपा की सरकारें हैं उनके साथ भेदभाव की शिकायत बढ़ती चली जा रही है। जिस तरह से जाति और धर्म के आधार पर राजनीति हो रही है, उसमें राज्यों के साथ केंद्र सरकार की दूरियां बढ़ रही है। रही सही कसर राज्यपालों ने पूरी कर दी है। राज्य विधानसभा द्वारा लिए गए निर्णय और कानूनों का पालन राज्यपाल नहीं होने देते हैं। एक समानांतर सत्ता राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में गैर भाजपाई शासित राज्यों में देखने को मिलती है।

ऐसी स्थिति में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने भारतीय राजनीति में एक बार फिर दशकों पुरानी राजनीति को स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। अपने सहयोगी दल कांग्रेस, जो केंद्र में एक प्रभावी भूमिका में है, उस पार्टी को राज्यसभा की 2 रिक्त सीट देकर, स्वार्थ की राजनीति से इतर विश्वास का नया मार्ग चुना है। उसकी सारे देश में अच्छी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। क्षेत्रीय दल 1990 के दशक के बाद से महत्वपूर्ण भूमिका में आये हुए हैं। केंद्रीय राजनीति में जो भूमिका क्षेत्रीय दलों की होनी चाहिए थी, उसका स्थान सीमित होकर रह गया है। तमिलनाडु से अब बदलाव की एक बयार बही है। अपने सहयोगी दल कांग्रेस पर जो विश्वास मुख्यमंत्री ने किया है उस विश्वास पर कांग्रेस सही उतरे। डीएमके और अन्ना डीएमके का पिछले पांच दशक से मजबूती के साथ तमिलनाडु की राजनीति में वर्चस्व था। बहुत समय के बाद अभिनेता से राजनेता बने विजय तमिलनाडु की जनता के विश्वास का केंद्र बने हैं।

कांग्रेस राष्ट्रीय विचारधारा का पोषण करती है, सभी पक्षों को साथ लेकर चलती है। ऐसी स्थिति में तमिलनाडु से जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वह भारत की राजनीति को एक नई दिशा दे सकता है। इस बात की संभावनाएं बनी हैं। इंडिया गठबंधन में कांग्रेस को लेकर असमंजस की स्थिति बनी रहती है। क्षेत्रीय दल इंडिया गठबंधन में शामिल है। गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दलों को भाजपा से लड़ना है। इंडिया गठबंधन में शामिल क्षेत्रीय दल भाजपा के स्थान पर कांग्रेस से ज्यादा लड़ते हुए नजर आते हैं। तमिलनाडु की राजनीति में डीएमके के साथ कांग्रेस राजनीति कर रही थी। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। विजय की पार्टी को सबसे ज्यादा सीटों पर विजय प्राप्त हुई । गैर भाजपा की सरकार बनाने के लिए कांग्रेस ने उन्हें समर्थन दिया। इससे डीएमके नाराज हो गई। कांग्रेस के पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था। कांग्रेस विजय को समर्थन नहीं देती ऐसी स्थिति में भाजपा वहां अन्ना डीएमके के साथ मिलकर एनडीए की सरकार बनाना चाहती थी। स्टालिन को यह बात समझनी चाहिए। राजनीति में बहुत सारे निर्णय समय और परिस्थिति को देखकर लिए जाते हैं। जिस तरह से स्टालिन ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाई है, इससे ऐसा लगता है कि क्षेत्रीय राजनीति में स्टालिन विजय से डरे हुए हैं। तमिलनाडु की राजनीति को ध्यान में रखते हुए स्टालिन ने इंडिया गठबंधन से दूरी बनाकर एक बड़ी राजनीतिक गलती की है। यही कहा जा सकता है।

अमेरिका बनाम ईरान: कौन जीता... कौन हारा

ब्रेट स्टीफेंस

ईरान के सैन्य नेताओं ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ हुए युद्धविराम समझौते को अपनी जीत करार दिया है। उनका दावा है कि उन्होंने अपनी 'अपनी दैवीय और मजबूत इच्छाशक्ति के दम पर' अमेरिका और इस्राइल को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। काफी हद तक वे सही भी हैं। लेकिन, यह याद रखना जरूरी है कि ईरान की मौजूदा सरकार, सात अक्तूबर, 2023 को इस्राइल पर हमास के हमले से पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गई है। उस समय सीरिया, लेबनान, गाजा और यमन में ईरान के मजबूत सहयोगी और प्रॉक्सी (उसके लिए लड़ने वाले गुट) मौजूद थे। उसका परमाणु कार्यक्रम सुरक्षित था और वह लगातार उच्च स्तर पर संवर्धित यूरेनियम का भंडार बढ़ा रहा था। साथ ही, उसके पास एक सक्षम सैन्य-औद्योगिक ढांचा, चुनौतियों के बावजूद काम करती अर्थव्यवस्था और ऐसी सरकार थी, जिसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त थी, भले ही उस पर दमनकारी नीतियों के आरोप लगते रहे।

लेकिन, आज हालात काफी बदल चुके हैं। ईरान की कई रणनीतिक ताकत या तो कमजोर पड़ गई है या लगभग समाप्त हो चुकी है। ईरान अब परमाणु हथियार बनाने के अपेक्षया कम करीब है। सीरिया में उसका प्रमुख सहयोगी सत्ता से बाहर हो चुका है। हिज्बुल्लाह, हमास और हूती विद्रोही जैसे उसके प्रमुख सहयोगी गुट पहले की तुलना में काफी कमजोर हो गए हैं। ईरानी रियाल दुनिया की सबसे कमजोर मुद्राओं में गिनी जा रही है। देश की सरकार एक ऐसे समाज पर शासन कर रही है, जिसमें व्यापक असंतोष दिखाई देता है और कट्टर समर्थकों को छोड़ दें, तो बड़ी संख्या में लोग अवसर मिलने पर सत्ता परिवर्तन का समर्थन कर सकते हैं। इस्राइल पर दागी गई उसकी हालिया बैलिस्टिक मिसाइलों से भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ। वहीं, होर्मुज जलडमरूमध्य में तनाव और संभावित नाकेबंदी ने वैश्विक ऊर्जा बाजारों पर दबाव तो जरूर बनाया, लेकिन वे पूरी तरह से ठप नहीं हुए।

एक दमनकारी और विस्तारवादी शासन के खिलाफ यह निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। फिर भी,

किसी युद्ध का नतीजा केवल दोनों पक्षों की सैन्य ताकत से नहीं, बल्कि दोनों की इच्छाशक्ति के स्तर से भी तय होता है। और, इस मोर्चे पर तेहरान के सख्त रुख वाले नेताओं ने वाशिंगटन के नेतृत्व पर निर्णायक जीत हासिल की है।

मैं यह बात एक ऐसे व्यक्ति के तौर पर लिख रहा हूं, जिसने शुरू से ही इस युद्ध का समर्थन किया और उम्मीद की थी कि ट्रंप इसे किसी निर्णायक नतीजे तक पहुंचाएंगे। भले ही ईरानी शासन सत्ता में बना रहता, पर कम से कम ऐसा समझौता तो होता, जिसमें ईरान अपनी सभी यूरेनियम संवर्धन क्षमताओं को छोड़ने पर मजबूर हो जाता और होर्मुज जलडमरूमध्य से वैश्विक आवाजाही बिना किसी रोक-टोक के जारी रहती। और, इन लक्ष्यों को हासिल करना राष्ट्रपति ट्रंप के लिए असंभव भी नहीं था। लेकिन, जब ईरान में सत्ता परिवर्तन के संकेत नहीं मिले और तेल-गैस की कीमतें बढ़ने लगीं, तो ट्रंप घबरा गए। करीब छह सप्ताह तक चली सैन्य कार्रवाई के बाद उन्होंने उस युद्ध से लगभग हाथ खींच लिए, जिसे उन्होंने खुद बढ़ाया था। उन्होंने बार-बार सैन्य कार्रवाई की चेतावनी दी, पर आखिरी समय में पीछे हट गए। इन कदमों ने ईरान और उसके सहयोगियों को संदेश दिया कि अमेरिकी नेतृत्व अपने फैसलों को लेकर पूरी तरह स्पष्ट और दृढ़ नहीं है। इससे अमेरिका की स्थिति मजबूत होने के बजाय कमजोर दिखाई दी।

गौरतलब है कि ट्रंप ईरान से 'बिना शर्त आत्मसमर्पण' की मांग कर चुके थे और अफगानिस्तान से अपमानजनक वापसी के लिए अपने पूर्ववर्ती नेतृत्व की बार-बार आलोचना भी करते रहे थे। हालांकि, यह ऐसे राष्ट्रपति के लिए बिल्कुल अजीब नहीं है, जिसकी फितरत ही हर किसी को धोखा देना और अपनी ही बातों से मुकर जाना है। हालांकि, इस समझौते की पूरी शर्तें अभी सामने नहीं आई हैं, जो इसके कमजोर होने का बड़ा संकेत है। अगर समझौता वास्तव में मजबूत होता, तो ट्रंप प्रशासन उसकी उपलब्धियों का खुलकर प्रचार करता। पर, इतना जरूर साफ है कि ट्रंप ने उन ईरानी नागरिकों से किया अपना वादा पूरा नहीं किया, जिनसे उन्होंने कहा था कि 'मदद रास्ते में है।' यह आश्वासन उस समय दिया गया था, जब जनवरी में सरकार विरोधी प्रदर्शनों को हिंसक तरीके से दबाया जा रहा था।

ट्रंप इस लड़ाई में अपने मुख्य सहयोगी इस्राइल को भी धोखा देने की राह पर हैं। वह यरूशलेम पर दबाव डाल रहे हैं कि वह उत्तर में हिज्बुल्लाह के हमलों को रोकने की कोशिश से पीछे हट जाए। इस तरह वह तेहरान को लेबनान और होर्मुज के बीच कूटनीतिक संबंध बनाने की जीत भी सौंप रहे हैं। अगर ईरान को अब होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों के लिए किसी तरह का सेवा शुल्क वसूलने की इजाजत दी जाती है, तो इसका मतलब होगा कि ट्रंप फारस की खाड़ी में अमेरिका के सहयोगियों को भी धोखा देंगे। ऐसा करके वह ईरान को ऐसी वित्तीय और रणनीतिक बढ़त देंगे, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है और जो उसके पास पहले भी नहीं था।

सबसे बुरा धोखा उन अमेरिकियों के साथ हुआ है, जिन्होंने इस युद्ध का समर्थन किया था। सिर्फ मेरे जैसे परंपरागत रूढ़िवादी ही नहीं, बल्कि ट्रंप के कई मागा समर्थक भी इस युद्ध के पक्ष में थे, क्योंकि उनका मानना था कि पिछले 47 वर्षों से अमेरिका के विरोध में खड़ा ईरान अब देश की सुरक्षा और रणनीतिक हितों के लिए बड़ा खतरा बन चुका है।

यह युद्धविराम उस खतरे को न तो समाप्त करता है और न ही उसे कम करता है। इस समझौते ने ईरान पर दबाव बनाए रखने के अमेरिका के एकमात्र जरिये, उसके बंदरगाहों की नौसैनिक घेराबंदी को कमजोर किया है, जबकि परमाणु कार्यक्रम को लेकर अभी कोई अंतिम सहमति भी नहीं बनी थी। इसका फायदा उठाकर ईरान बातचीत को तब तक टालता रह सकता है, जब तक ट्रंप पद से हट नहीं जाते।

अन्नामलाई अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने के प्रयास में!

कल्याणी शंकर

तमिलनाडु में भाजपा के पूर्व प्रमुख के. अन्नामलाई ने इस सप्ताह अपने राजनीतिक भविष्य को आकार देने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए, जिनमें दिल्ली में शीर्ष भाजपा नेताओं के साथ बैठक और पार्टी से अपने इस्तीफे की घोषणा करना शामिल है। इसका उद्देश्य उनकी राजनीतिक छवि को ऊपर उठाना और पाठकों को उनकी बदलती रणनीति के साथ जोड़े रखना है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए, अन्नामलाई की अपनी नई पहल के लिए बड़ी योजनाएं हैं। दिल्ली में प्रमुख भाजपा नेताओं के साथ उनकी बैठकों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, खासकर इसलिए क्योंकि वह अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, विशेष रूप से फिल्म स्टार विजय की हालिया जीत के बाद, जिसने उन्हें नए अवसर तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया है। अन्नामलाई इस कदम को अपने सार्वजनिक जीवन का अगला चरण मानते हैं। वह खुद को टी.वी.के. के मुख्य चुनौतीकर्त्ता के रूप में देखा जाना चाहते हैं। अन्नामलाई हमेशा से महत्वाकांक्षी रहे हैं और उन्होंने खुद को सत्ताधारी पार्टी के नेता के खिलाफ खड़ा किया है। हालांकि, 2026 के विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार सूची से उनकी हालिया अनुपस्थिति ने उनके समर्थकों को उनके भविष्य पर सवाल उठाने के लिए मजबूर कर दिया है। जटिल सीट-बंटवारे की व्यवस्था और पार्टी रणनीतियों ने कई लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि वह आगे क्या करेंगे। अन्नामलाई इस बात से नाराज थे कि उन्हें राज्य भाजपा प्रमुख के पद से हटा दिया गया था। तमिलनाडु का राजनीतिक दृश्य बदल रहा है, खासकर इसलिए क्योंकि पारंपरिक द्रविड़ मॉडल को नई वास्तविकताओं का सामना करना पड़ा है। अन्नामलाई अपने नए आंदोलन के वैचारिक अग्रदूत के रूप में कलाम को चुनकर राजनीतिक परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना चाहते हैं। कलाम के जीवन और उपलब्धियों को उजागर करके, अन्नामलाई आकांक्षा और एकता का संदेश देना चाहते हैं, जो राज्य के लिए एक नई राजनीतिक शब्दावली पेश कर सकता है। अन्नामलाई का नेतृत्व आक्रामक, एकल राजनीति की शैली द्वारा परिभाषित था। उनके नेतृत्व में, राज्य भाजपा एक छोटी पार्टी से, जो अन्नाद्रमुक पर निर्भर थी, एक मजबूत तीसरी ताकत में बदल गई। उन्होंने 'एन मान, एन मक्कल' (मेरी मिट्टी, मेरे लोग) पदयात्रा जैसे हाई-प्रोफाइल अभियानों का नेतृत्व किया, जो सभी 234 निर्वाचन क्षेत्रों तक पहुंचे। परिणामस्वरूप, पार्टी का वोट शेयर 2019 में सिर्फ 3.6 प्रतिशत से बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनावों में 11 प्रतिशत से अधिक हो गया। अन्नामलाई ने सत्ताधारी द्रमुक पर रोज हमले शुरू किए, भ्रष्टाचार के आरोपों को उजागर किया और पेरियारवादी विचारधाराओं को चुनौती दी। इस टकरावपूर्ण दृष्टिकोण ने क्षेत्रीय नेताओं को भाजपा को अधिक गंभीरता से लेने के लिए मजबूर किया लेकिन इसने एन.डी.ए. गठबंधन, विशेष रूप से अन्नाद्रमुक के साथ संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया। राष्ट्रीय पार्टी छोड़ने के बाद, अन्नामलाई ने तमिलनाडु में एक नया राजनीतिक आख्यान तैयार करने पर ध्यान केंद्रित किया, जिसमें द्रमुक और अन्नाद्रमुक से स्वतंत्र युवा, ईमानदार नेताओं के विकास पर जोर दिया गया। जब से नैनार नागेंद्रन राज्य अध्यक्ष बने हैं, अन्नामलाई ज्यादातर सुर्खियों से दूर रहे हैं। अन्नामलाई, जो पहले 2021 के विधानसभा चुनावों में द्रमुक के आर. इलांगो से हार गए थे, ने 2026 में विजय की राजनीतिक शुरुआत के बारे में मजबूत भविष्यवाणियां कीं और कहा, ''विजय अच्छा प्रदर्शन करेंगे।

पहला रियल वर्ल्ड गेम...

आज के दौर में वर्चुअल रियलिटी का क्रेज लोगो पर दिनों-दिन बढ़ता चला जा रहा है, नई जनरेशन हर एप्प को वर्चुअल रियलिटी में ही देखना चाहती है।

इसको देखते हुए एक नया गेम बनाया गया है जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देता है। लैंड्स एंड गेम के को-डिजाइनर केन वोंग का कहना है कि जो लोग वर्चुअल रियलिटी को नहीं मानते उनको यकीन दिलवाने के लिए इसे बनाया गया है। इस गेम में कोई फिजिकल कंट्रोल्स नहीं दिए गए और आपको लुक पॉइंट्स पर फोकस कर इसे खेलना होगा। इस गेम को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता क्योंकि गेम के मूविंग ऑब्जेक्ट और कनेक्ट पैटर्न्स आपको हैरत में डाल देगें और आप सोचने पर मजबूर हो जाएगे कि ऐसा हो कैसे रहा है।

क्या है खास

इस गेम की मोन्यूमेंट वैली में कोई टेक्स्ट और वॉइस नहीं दी गई जिससे आपको गेम खलते समय इंटरेक्शन करने से ही स्टोरी का पता चलता है। यह गेम 360-डिग्री लैंडस्केप पर खेली जाती है जिससे रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। इस गेम में चट्टानों पर चलना, पहेलियां और हवा में उड़ना आदि शामिल है।

सब कुछ रियल

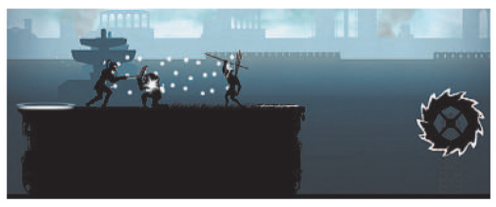

इस गेम की स्टोरी को इस तरीके से बनाया गया है कि सब कुछ रियल लाइफ एक्टिविटीज की तरह यूजर को देखने को मिलती है। इसे डेवेलप करने के बाद इसे पार्टीज और फ्रेंड्स को गेम एक्सपीरियंस करने के लिए भेज दिया गया है।

ज्यादा सेल्फी लेने से हो सकता है त्वचा को नुकसान

लोगों में आजकल सेल्फी लेने का चलन जोरों पर है। सेल्फी के लिए लोगों की दीवानगी देखते ही बनती है। सेल्फी लेने के चक्कर में अपनी जान गंवाने वालों के बारे में तो आपने बहुत सुना ही होगा लेकिन आज हम आपको सेल्फी से होने वाले ऐसे नुकसान के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आप सेल्फी लेने से घबराने लगेंगे। जीं हां दुनिया के कई मशहूर डर्मटोलॉजिस्ट ने इस बात की चेतावनी जारी की है कि ज्यादा सेल्फी लेना आपकी त्वचा को नुक्सान पहुंचा सकता है।

ज्यादा सेल्फी लेने के नुकसान

त्वचा विशेषज्ञों का मानना है कि चेहरे पर लगातार स्मार्टफोन की लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जोखिम त्वचा को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे उम्र बढ़ने के साथ चेहरे पर झुर्रियां भी बढ़ सकती है। ज्यादा सेल्फी लेने से आपकी त्वचा की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और आप समय से पहले बूढ़े लगने लगते हैं।

शोधकर्ताओं के अनुसार फ्लैश लाइट और स्क्रीन से चेहरे पर पड़ने वाली ब्लू लाइट त्वचा के लिए काफी नुकसानदायक है। इसी के साथ बताया कि ब्लॉगर्स और ज्यादा सेल्फी लेने वालों को अब जल्दी ही संभल जाना चाहिए।

त्वचा पर सेल्फी का असर

एक्सपर्ट्स के अनुसार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडियेशन आपकी त्वचा में मौजूद डीएनए पर बुरा असर डालता है। इस रेडियेशन के चलते शरीर की स्किन रिपेयरिंग की क्षमता पर भी काफी बुरा असर पड़ता है जिससे समय से पहले झुर्रियां दिखनी शुरू हो जाती हैं और माना जाता है कि किसी भी तरह की क्रीम या सनस्क्रीन इससे बचाव नहीं कर सकती। हालांकि एक अच्छा स्क्रब त्वचा के सेहत काफी अच्छी रख पाता है। त्वचा विशेषज्ञों का कहना हैं कि आप त्वचा को बाहर से हाइड्रेट नहीं कर सकते यानि उसकी पानी की जरूरत को बाहर से पूरा नहीं कर सकते। ये जरूरत अंदर से ही पूरी की जा सकती है।

जिसके हृदय में सच्चा प्रेम होता है वही व्यक्ति ईश्वर का भक्त हो सकता है। जरूरत है बस प्रेम की चाहे वह पैसे से हो, किसी स्त्री से, बच्चे से या अन्य सांसारिक वस्तुओं से। अगर हृदय में प्रेम होगा ही नहीं तो ईश्वर क्या संसार में किसी चीज से लगाव हो ही नहीं सकता। भगवान से प्रेम करना वास्तव में उसी प्रकार है जैसा एक दिशाहीन गाड़ी को सही दिशा देना। जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर होता है उस व्यक्ति को भक्ति की ओर प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम का वृक्ष तभी उग सकता है जब प्रेम का बीज, प्रेम का अंकुर हृदय में मौजूद हो।

हृदय में प्रेम का अंकुर जरूरी...

प्रेम शक्ति भी है और आसक्ति भी। जब व्यक्ति का प्रेम कामना रहित होता है तो यह शक्ति होती है और जब प्रेम में किसी चीज को पाने का लोभ रहता है तो यह आसक्ति बन जाती है। सच्चा प्रेम वह होता है जो प्रेम में किसी प्रकार का लोभ और किसी चीज को पाने की कामना नहीं रखता है। ऐसा व्यक्ति प्रेम में ऐसा कमाल कर जाता है कि बड़े से बड़े बलवान और धनवान उसके आगे घुटने टेक देते हैं। मीराबाई को दिया गया जहर असरहीन होना। प्रह्लाह का आग के शोलों में भी मुस्कुराते हुए रहना और तुलसीदास का उफनती नदी को पार कर जाना यह प्रेम की शक्ति का उदाहरण है। संतजन कहते हैं कि जिसके हृदय में सच्चा प्रेम होता है वही व्यक्ति ईश्वर का भक्त हो सकता है। जरूरत है बस प्रेम की चाहे वह पैसे से हो, किसी स्त्री से, बच्चे से या अन्य सांसारिक वस्तुओं से। अगर हृदय में प्रेम होगा ही नहीं तो ईश्वर क्या संसार में किसी चीज से लगाव हो ही नहीं सकता। भगवान से प्रेम करना वास्तव में उसी प्रकार है जैसा एक दिशाहीन गाड़ी को सही दिशा देना। जिसके हृदय में प्रेम का अंकुर होता है उस व्यक्ति को भक्ति की ओर प्रेरित किया जा सकता है, क्योंकि प्रेम का वृक्ष तभी उग सकता है जब प्रेम का बीज, प्रेम का अंकुर हृदय में मौजूद हो। बिना बीज के खेती भला कैसे हो सकती है। इस संदर्भ में एक कथा है कि एक बार संत श्रीगोसाई गोकुलनाथ जी के यहां एक धनवान व्यक्ति बहुत सारा धन लेकर शिष्य बनने की कामना से आया। गोसाईं जी ने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या तुम्हारा कहीं किसी वस्तु पर ऐसा स्नेह है, जिसके बिना तुम्हारा मन व्याकुल हो जाता हो। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया मेरा कहीं किसी वस्तु में तनिक भी स्नेह नहीं है। उत्तर सुनकर गोसाईं जी ने कहा कि फिर तो हम तुम्हें दीक्षा कदापि नहीं दे सकते। तुम किसी और गुरू को ढूंढ लो। भक्ति मार्ग में प्रेम ही प्रधान है। जो प्रेम संसार से होता है, दीक्षा शिक्षा से उसी को पलटकर भगवान में लगा दिया जाता है। जब तुम्हारे हृदय में कहीं प्रेम है ही नहीं तो भगवान के प्रेम से भला कैसे सराबोर हो सकते है।

धर्म क्या है?

कुछ लोग कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति का धर्म अलग है, जैसे राजा का धर्म है प्रजा का ध्यान रखना। सैनिक का धर्म है युद्ध लड़ना, व्यापारी का धर्म है व्यापार करना। जब हम धर्म की परिभाषा इस तरह से करते हैं तो सवाल उठता है कि क्या चोर का धर्म है चोरी करना? फिर तर्क दिया जा सकता है कि नहीं, जो नीति-नियम सम्मत आचरण है वही धर्म है। अर्थात नैतिकता का ध्यान रखा जाना जरूरी है, तो सिद्ध हुआ की नीति ही धर्म है? श्रेष्ठ आचरण ही धर्म है? यदि ऐसा है तो दांत साफ करना नैतिकता है, लेकिन दांत साफ करना हिंसा भी है, क्योंकि इससे हजारों किटाणुओं की मृत्यु हो जाती है। जो आपके लिए नैतिकता है वह हमारे लिए अनैतिकता हो सकती है। धर्म के लिए हजारों लोगों की हत्या भी कर दी जाए तो वह नीति है उसे आप धर्मयुद्ध कहते हैं। तब हम कैसे मान लें की नीति या नैतिकता ही धर्म है? या फिर आप नैतिकता के नाम पर जो-जो गलत है उसे अलग हटाइए। इस नजरिए से वैदिक ऋषियों का विचार सबसे ज्यादा उपयुक्त लगता है कि सृष्टि, धर्म और स्वयं के हित और विकास में किए जाने वाले सभी कर्म धर्म हैं।

धर्म का मर्म

रहस्य यह है कि सभी आध्यामत्मिक पुरुषों ने अपने अपने तरीके से आत्मज्ञान प्राप्त करने और नैतिक रूप से जीने के मार्ग बताए थे। वेद, पुराणों, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार असल में धर्म का अर्थ सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग माना जाता है। लेकिन समाज के ठेकेदारों ने धर्म के अर्थ को अधर्म का अर्थ बनाकर रख दिया है। आप लाख कितना ही किसी को भी समझाओं की दुनिया के सारे संप्रदाय एक ही तरह की शिक्षा देते हैं। उनका का इतिहास भी सम्मलित है, लेकिन फिर भी वे दूसरे के संप्रदाय से नफरत ही रखेंगे। इसका सीधा सा कारण है प्रत्येक अधार्मिक व्यवस्थाओं को धर्म मान लिया गया है। धर्म को परिभाषित करना उतना ही कठिन है जितना ईश्वर को। हिन्दू धर्म में धर्म को एक जीवन को धारण करने, समझने और परिष्कृत करने की विधि बताया गया है। धर्म ग्रंथो, पुराणो में व्याप्त कथाओं का अनुसरण कर ही हम अपने धर्म को भलीभांति जान सकते हैं। बहु-प्रचलित कथाओं के अनुसरण के आधार पर देखते हैं कि वह कथा हमें क्या शिक्षा देती है।

धर्म का अर्थ सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग माना जाता है। देव, दानव, मनुष्य, पशु, पक्षी, इस सृष्टि में व्याप्त प्राणी मात्र में प्रेम का भाव ईश्वरीय देन है। इस आधार पर प्रेम ही सत्य है, प्रेम ही शाश्वत है। सच्चे प्रेम में एक दूजे से सत्य बोलना और सच्चाई और ईमानदारी से अपने साथी का साथ निभाने का गुण होता है। यही उनके प्रेम की सत्यता को प्रमाणित करने का प्रथम आधार होता है। प्रेम तो बस प्रेम मांगता जिससे भी हम प्रेम

मुक्ति का मार्ग

करते है उसकी खुशी, उसका साथ चाहता है। प्रेम मे तो वह दिव्य शक्ति है, जो हिंसक को भी अहिंसक बना दे। प्रेम हिंसा का नहीं, अपितु अहिंसा का मार्ग है। प्रेम निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ आपस में एक दूजे से प्रेम करने वाले, जीवन भर के लिए एक दूजे का साथ पाने की सुखद अनुभूतियों व सपनों को जीने की इच्छा रखने वाले दो प्रेमियों के जीवन को प्रभावित करता है। विरह की वेदना प्रेमियो को तोड़कर रख देती है। वही अपने प्रेम को पाने की खुशी उसे ऊर्जा व विश्वास से भर देती है। अपने प्रेम को पाना, अपने प्रेमी का साथ पाना किसी भी तरह से किसी के साथ अन्याय नहीं है। हम जिससे प्रेम करते है उसका साथ पाने के लिये किया गया हर कर्म अपने साथी के साथ न्याय है। इस आधार पर प्रेम न्याय है। अर्थात निश्चित रूप से दो प्रेम करने वालो को अलग करना अन्याय है।

प्रेम तो प्रेम है

प्रेम तो प्रेम ही है। बिना किसी दुर्भावना के निश्छलता के साथ अपने साथी की खुशी व साथ निभाने के लिये किया गया प्रेम ही वास्तविक प्रेम है। धर्म ग्रंथो में प्राणी मात्र के प्रति प्रेम व करुणा का भाव रखने की बात कही गई है। निश्चित रूप से आपका प्रेम भी इस सृष्टि का ही हिस्सा है। कुछ लोग कहेंगे कि यह तो ईश्वर के प्रति प्रेम के बारे में होगा। प्रेम तो प्रेम ही होता है। प्रेम तो हृदय से उत्पन्न भाव है। हृदय के भाव तो किसी के भी प्रति हो सकता है। ईश्वरीय प्रेम और मानवीय प्रेम में भेद नही किया जा सकता है। फिर प्राणीमात्र के प्रति समानता का भाव रखना भी तो धर्म ही है। सबसे महत्वपूर्ण तो बात यह है कि धर्मग्रंथों में व्याप्त कथाओं में कही भी केवल ईश्वर के प्रति प्रेम की बात नहीं कही गई। कथाओं में सती का शिव के प्रति हो या पार्वती का शिव के प्रति या फिर राधा का कृष्ण के प्रति या रुक्मिणी का गोविन्द के प्रति हर जगह प्रेम एक प्रेमिका का उसके प्रेमी के प्रति ही दर्शाया गया न कि भगवान के रूप में या भगवान के प्रति दर्शाया गया।

प्रेम सर्वोपरि

धर्म का व्यक्तिगत स्वतंत्रता वाला पहलु प्राणिमात्र को अपनी स्वेच्छा से जीवन जीने व अपना जीवनसाथी चुनने व प्रेम करने का अधिकार देता है। सत्य, अहिंसा, न्याय, प्रेम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेम पूर्वक अपनों - परायों में भेद भाव न कर समानता से न्याय की बात करना। प्राणिमात्र के प्रति दया व करुणा का भाव रखते हुए। ईमानदारी के साथ हंसी खुशी अंतिम सांस तक जिंदादिली के साथ जीवन जीने पर ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है।

धर्म ग्रंथो में प्रेम का स्थान सर्वोपरि बताये जाने को जितना जाना, समझा गया है उस आधार पर तो यही कारण नजर आता है। धर्म के हर पहलु को लिए हुए होने के कारण ही शिव-शक्ति, राधा-कृष्ण, श्याम-रुक्मणि, अनेक महापुरुषों और ऋषि मुनियों ने प्रेम का गुणगान किया ।

संत कबीर का दोहा भी प्रेम की इसी विशालता व सर्वोपरिता को दर्शाता है ।

पोथी पढ़ि पढ़ि जग मुआ, पंडित भया न कोय,
ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय।

यानी बड़ी बड़ी पुस्तकें पढ़ कर संसार में कितने ही लोग मृत्यु के द्वार पहुंच गए, पर सभी विद्वान न हो सके। कबीर मानते हैं कि यदि कोई प्रेम या प्यार के केवल ढाई अक्षर ही अच्छी तरह पढ़ ले, अर्थात प्यार का वास्तविक रूप पहचान ले तो वही सच्चा ज्ञानी होगा।

जहां ज्ञान हारा और भक्ति जीती...

वृंदावन में एक स्थान ऐसा है, जहां ज्ञान हारा और भक्ति जीती। इस प्रसंग ने लोक मानस में यह बैठाया कि ज्ञानार्जन से अधिक ज्ञानानुभव महत्वपूर्ण होता है। बुद्धि से ज्यादा भावनाएं प्रमुख होती हैं। मस्तिष्क से अधिक दिल की बात सुननी चाहिए। इस स्थान को ज्ञान गूदड़ी कहते हैं। लोक में यह प्रसंग उद्धव-गोपी संवाद के रूप में जाना जाता है। भक्तिकालीन कवियों ने इस प्रसंग से यह स्थापित किया कि भगवान को पाने का सबसे सहज और सरल मार्ग भक्ति का है। शास्त्रों-पुराणों में यह प्रसंग नाम मात्र है। महाकवि सूरदास ने इस प्रसंग को विस्तार दिया। बात उस समय की है जब- कृष्ण गुरु संदीपन के यहां ज्ञानार्जन के लिए गये थे तब उन्हें ब्रज की याद सताती थी। वहां उनका एक ही मित्र था उद्धव, वह सदैव ज्ञान-नीति की, निर्गुण ब्रह्म और योग की बातें करता था। श्रीकृष्ण का उद्धव से परिचय मथुरा में हुआ। उद्धव हर संदर्भ में नीतियों का सहारा लेते। परिणामस्वरूप उनसे बात करने वाला निरुत्तर रह जाता। उनके गहन अध्ययन और विद से प्रभावित लोग उन्हें देवताओं के गुरु बृहस्पति का शिष्य मानते। पहले परिचय में ही उद्धव ने अपनी ज्ञानपूर्ण बातों से श्रीकृष्ण को प्रभावित किया। श्रीकृष्ण को यह अनुभूति थी कि उद्धव को ज्ञान का गर्व है। शंका निवारण के लिए श्रीकृष्ण ने युक्ति निकाली। एक दिन उन्होंने उद्धव से बात करते हुए कहा कि मैं मानता हूं कि ज्ञान का मार्ग सर्वोत्तम है। ज्ञान से व्यक्ति के मोहपाश खुल जाते हैं। माया के बंधनों से उसे मुक्ति मिल जाती है। इस तरह मोह-माया उसे दु:ख नहीं पहुंचाते। उद्धव को अपनी बात गंभीरता से सुनते देख गंभीर लंबी सांस लेकर श्रीकृष्ण ने कहा- उद्धव जी, क्या यह संभव है कि आप ब्रज जाकर गोपियों को समझाएं। उन्हें बताएं कि दुनिया का सार ज्ञान है, प्रेम नहीं। ज्ञान से प्राप्ति होती है, भावनाओं से नहीं। ज्ञान से शांति मिलती है, जबकि प्रेम अशांत करता है। ज्ञान दुखों से ऊपर उठाता है और प्रेम दुखों में डुबोता है। ज्ञान समस्याओं का अंत है और प्रेम दुखों का आरंभ। श्रीकृष्ण की बात सुनकर उद्धव के भीतर ज्ञानजन्य गर्व हिलोरें लेने लगा। उन्होंने ब्रज जाकर गोपियों को समझाने की बात मान ली। उन्होंने श्रीकृष्ण को आश्वासन दिया कि वे गोपियों को समझाकर कुछ दिन में ही लौट आएंगे। श्रीकृष्ण का संदेश लेकर उद्धव वृंदावन पहुंचे। उद्धव के आगमन का समाचार पूरे ब्रज में फैल गया। नंद बाबा के घर कुछ समय बिताने के बाद उद्धव गोपियों से मिलने पहुंचे। उद्धव ने देखा गोपियां बेहाल हैं। उद्धव को यह सब विचित्र लगा। गोपियों की दशा पर वे मन ही मन मुस्कुरा उठे। ज्ञान गर्व पीड़ित हो उन्होंने आंखें मूंद लीं। आगे बढ़ने पर उन्हें सखियां से घिरी राधा दिखीं। अपूर्व सौंदर्य, सौंदर्य से अभिभूत उद्धव ने अपने को कृष्ण सखा बताकर राधा को प्रणाम किया। उद्धव ने बात आगे बढ़ाते हुए कहा कि मैं आपके लिए उनका संदेश लाया हूं। वह सोच रहे थे कि श्रीकृष्ण का संदेश सुनते ही गोपियां, मां यशोदा और नंदबाबा की तरह आनंद से भर उठेंगी। लेकिन राधा तो लगता है मद में हैं। उन्हें किसी की चिंता ही नहीं। उद्धव के अभिमान ने करवट ली। उनके मन ने कहा-अपने ज्ञान से वे कितने मूर्खों का जीवन बदल चुके हैं। फिर ये गोपियां क्या हैं? आखिर हैं तो स्त्रियां ही। प्रेम ने इनका मस्तिष्क दूषित कर दिया है। इनसे हार मानकर लौटना उचित नहीं। उद्धव ने एक बार फिर बात शुरू करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आपको श्रीकृष्ण के पास मथुरा कोई संदेश भेजना हो तो बताइए। इस पर राधा बोल पड़ीं- उद्धव जी हमारे हृदय प्रेम से भरे हैं। इसलिए हमें किसी संदेश या संदेशवाहक की आवश्यकता नहीं। प्रेम संदेश तो हृदय सुन लेता है। हम तो नित्य अपने मनमोहन को अपना संदेश सुनाती और उनका सुनती हैं। श्रीकृष्ण के प्रेम में गोपियां इस तरह डूबी हैं कि इन्हें संसार का ज्ञान ही नहीं रह गया। सांसारिक आचरण से यह ऊपर हो गई हैं। गोपियों के प्रेम के प्रति उद्धव के मन में आदरभाव पनप उठा। ज्ञान से बंजर हुए मस्तिष्क में प्रेम का अंकुर फूट पड़ा। ज्ञान की गूदड़ी में उन्हें प्रेम का हीरा मिल गया। उद्धव शांत हो गए। उन्हें लगा कि उन्होंने ज्ञानार्जन तो बहुत किया, लेकिन ज्ञानानुभव आज ही हुआ। उनका मन श्रद्धा से भर उठा। मस्तक वृंदावन की प्रेम भूमि पर नत हो गया।

नैतिकता से दूर दानव की राह...

नैतिक शिक्षा ही मानव को 'मानव' बनाती है क्योंकि नैतिक गुणों के बल पर ही मनुष्य वंदनीय बनता है। सारी दुनिया में नैतिकता अर्थात सच्चरित्रता के बल पर ही धन-दौलत, सुख और वैभव की नींव खड़ी है। प्रसंग बताता है कि 'इन्द्र ने ब्राह्मण का रूप धारण करके प्रह्लाद के पास जाकर पूछा- ''आपको तीन लोकों का राज्य कैसे मिला ?'' प्रह्लाद ने इसका कारण नैतिकता यानी शील को बताया। इन्द्र ने प्रह्लाद से वरदान में नैतिकता यानी शील को मांग लिया। शील के जाते ही धर्म, सत्य, सदाचार, बल, लक्ष्मी सभी चले गये।''भारत की नैतिकता इतनी ऊंची थी कि सारा संसार अपने चरित्र के अनुसार शिक्षा प्राप्त करे। ऐसी घोषणा यहां की जाती थी। नैतिकता के अंग हैं -सच बोलना, चोरी न करना, अहिंसा, दूसरों के प्रति उदारता, शिष्टता, विनम्रता, सुशीलता आदि। परन्तु आज ये शिक्षा ना तो बालक के माता-पिता, जिन्हें बालक की प्रथम पाठशाला कहा जाता है, ना ही विद्यालय दे पा रहा है। नैतिक शिक्षा के अभाव के कारण ही आज जगत में अनुशासनहीनता का बोल-बाला है। आज का छात्र कहां जानता है, बड़ों का आदर-सत्कार, छोटों से शिष्टता-प्यार, स्त्री जाति की सुरक्षा-सम्मान सत्कार। रही-सही कसर पूरी कर देता है हमारा फिल्मजगत और टेलिविजन प्रसारण। जो अश्लीलता की हर हदें पार कर चुका है और उसका मूल्य चुकाना पड़ता है समाज को, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव है अनुकरण करना। वह अनुकरण से ही सीखता है।

सही सोच जरूरी

समाज में एक ज्वाला जली है हवस की। चारों तरफ, जहां पढ़ो, सुनो व देखने को मिलता है देश में महिलाओं के खिलाफ असामाजिक घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। दूसरी ओर यदि हम देखें तो साहित्य व सिनेमा जगत समाज का दर्पण होते हैं। जहां एक ओर वे गलत दिखाकर समाज को गलत राह पर ले जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सही सोच, सही प्रदर्शन दिशा भ्रमित होने से बचा सकता है। इतिहास बताता है कि 'राजा जयसिंह अपनी नव विवाहिता के प्रेम प्यार में आबद्ध होकर राजकाज भूल गये थे। बिहारी कवि की एक श्रृंगारिक अन्योक्ति ने राजा को सचेत कर कर कर्तव्य पथ पर अग्रसर कर दिया- नहिं परागु नहिं मधुर मधु नहिं विकास इहिकाल। अलि कली ही सों बिंध्यौ, आगे कौन हवाल ।। इस दोहे ने राजा जयसिंह की आंखें खोल दी थी। यहां पूरे ही समाज का दायित्व हो जाता है कि हम अपने नैतिक मूल्यों का पुर्नस्थापन करें।

मार्ग को भूल गए

स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि भारत ही वह देश है जो जीवन के नैतिक मूल्यों के साथ अब तक पर्वत से भी अधिक दृढ़ भाव से खड़ा है। अफसोस! आज हम अपने पूर्वजों के दिखाए, बताये मार्ग को भूल गए हैं। पाश्चात्य सभ्यता, संस्कृति को अपनाते-अपनाते, ना तो हम खुद को ही पहचान पा रहे हैं, ना ही पाश्चात्य को। कुछ हम आजादी मिलने का अर्थ कुछ और ही ले रहे हैं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर वहां की महिलाओं की स्थिति है। नारी राष्ट्रीय व सामाजिक जीवनामृत का केन्द्र है। जो राष्ट्र समाज में स्त्रियों का आदर नहीं करना चाहते व कभी महान बन ही नहीं पाएंगे। देश के वर्तमान पतन का मुख्य कारण यही है कि हमने शक्ति की इन सजीव प्रतिमाओं के प्रति आदरभाव नहीं रखा। स्त्रियों के प्रति घृणित दृष्टि निन्दनीय है। माँ के रूप में, बहन-बेटी के रूप में महिलाओं को सुरक्षा, सुविधा, स्नेह व दुलार देना समाज का कर्तव्य है। नैतिकता और सदाचार ही राष्ट्रीय जीवन का आधार है।

सही मार्गदर्शन मिलें

आज समाज में इन्हीं नैतिक मूल्यों की स्थापना की सबसे अधिक जरूरत है। प्रत्येक बच्चे को सही मार्गदर्शन मिले, यह उचित शिक्षा ही कर सकती है। नैतिकता का पाठ पढ़ाया नहीं जा सकता, वरन् उसे चरित्र में उतारना है। गीता को कंठ से गाना ही नहीं होता वरन् उसका अक्स अपने हृदय में बसाना होगा तभी यह देश स्त्रियों, मासूम बच्चियों का आदर, सुरक्षा का दर्जा दे पायेगा। वरना मानव दानव का रूप धर चुका है तथा उसका रूकना कठिन ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा।

जॉब छोड़ने के पहले क्या करें...?

क्या आप अपनी मौजूदा कंपनी छोड़ कर किसी अन्य कंपनी में नौकरी करने की तैयारी कर रहे हैं? अगर ऐसा है, तो जॉब छोड़ने की प्रक्रिया के दौरान कुछ खास बातों का ख्याल रखना चाहिए, ताकि कोई समस्या पैदा न हो। अगर आप कंपनी छोड़ रहे हैं, तो नोटिस या इस्तीफा देने से पहले बोनस आदि के नुकसान के बारे में जानकारी जुटा लें। अगर पेपरवर्क सही नहीं होगा, तो वित्तीय नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। आपको कंपनी की अपेक्षाओं को समझने का प्रयास भी करना चाहिए।

बात पर कायम रहें: आपने अपनी पुरानी कंपनी से जो वायदा किया है, उसे निभाएं। आपकी पहचान आपके कमिटमेंट्स से होनी चाहिए। अगर आप किसी कंपनी को बीच में ही छोड़ते हैं, तो इससे कंपनी की योजनाओं पर नेगेटिव असर पड़ता है। सो, अपना प्रोजेक्ट पूरा करके ही कंपनी छोड़ें।

प्रोटोकॉल फॉलो करें: आपको कंपनी छोड़ने के बारे में एचआर या बॉस को सबसे पहले बताना चाहिए। ऐसा न हो कि दोस्तों और कलीग्स को इसके बारे में पहले पता लगे और बॉस को बाद में। अगर कंपनी के प्रति गुस्से को सबके सामने जाहिर करेंगे, तो गैर-पेशेवर माना जाएगा।

रेफरेंस तैयार करके जाएं: आपको आईटी, एचआर और बॉस को रेफरेंस, प्रूफ ऑफ सर्विस, सैलेरी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आदि के लिए तैयारी करनी चाहिए। कई बार नई कंपनी लिखित में रेफरेंस मांगती है या मौजूदा बॉस से बात करवाने के लिए कहती है। इसलिए आपको प्रोफेशनल तरीके से इसका प्रबंध पहले ही कर लेना चाहिए।

दरवाजे खुले रखें: ध्यान रखें कि अगर नई कंपनी में आपकी चाहत के मुताबिक नहीं हुआ तो आपको कुछ महीने या सालभर बाद वापस अपनी पुरानी कंपनी में लौटना पड़ सकता है। इसलिए कंपनी छोड़ते समय कोई भी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए।

बात पते की: ज्यादातर लोग कंपनी छोड़ते वक्त सभी लोगों से मिल कर धन्यवाद कहना भूल जाते हैं। यह गलत असर डालता है। इसलिए सभी से मिल कर जाएं। इस्तीफा देने के बाद कई लोग कंपनी या बॉस के खिलाफ हर तरफ जहर उगलने लगते हैं। उनकी बुराई करने लगते हैं, यह गलती करने से बचें।

राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय
प्रमुख समाचार

उद्धव की दो टूक: भरोसा नहीं तो पद छोड़ दूंगा

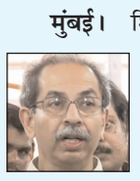

मुंबई। शिवसेना (यूबीटी) प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के 60वें स्थापना दिवस पर विरोधियों को करारा जवाब दिया है। मुंबई में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में उन्होंने कांग्रेस के साथ पार्टी के विलय की खबरों को पूरी तरह खारिज कर दिया। उद्धव ठाकरे ने दो टूक शब्दों में कहा कि जब हमने 30 साल के गठबंधन के बाद भी भाजपा के साथ अपनी पार्टी का विलय नहीं किया, तो फिर कांग्रेस के साथ विलय करने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

अपनी पार्टी के छह लोकसभा सांसदों की बगावत के बीच शिवसेना-यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने शुक्रवार को भावुक होते हुए कहा कि चुनौतियों और हमलों के बावजूद मेरा संकल्प कमजोर नहीं पड़ा है, लेकिन अगर पार्टी को मुझ पर भरोसा नहीं है, तो मैं अपना पद छोड़ने को तैयार हूं। चार साल में दूसरी बार पार्टी में होने जा रही टूट पर अपनी पहली प्रतिक्रिया में ठाकरे ने कहा कि वे एक दशक से ज्यादा समय से पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं।

ममता और अभिषेक को अवमानना का नोटिस

कोलकाता। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी को अदालत की अवमानना का नोटिस जारी किया है। यह मामला टीएमसी की शहीद दिवस रैली से जुड़ा है। अदालत में दाखिल याचिका में आरोप लगाया गया है कि 21 जुलाई 2025 को आयोजित इस रैली के दौरान हाईकोर्ट के साल 2018 के फैसले का उल्लंघन किया गया। जस्टिस अरिजित बनर्जी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को इस मामले में प्रारंभिक सुनवाई की। सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों नेताओं को नोटिस जारी करने का आदेश दिया। मामले की अगली सुनवाई तीन जुलाई को निर्धारित की गई है।साल 2018 में कलकत्ता हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक अहम फैसला सुनाया था, जिसमें कोई भी राजनीतिक दल शहर के मुख्य रास्तों को पूरी तरह से बंद नहीं करेगा। कोर्ट ने साफ निर्देश दिए थे कि सड़क का एक हिस्सा हमेशा पैदल चलने वालों और गाड़ियों के लिए खुला रहना चाहिए। खास तौर पर एंबुलेंस जैसे आपातकालीन वाहनों के लिए रास्ता छोड़ना अनिवार्य किया गया था।

आज से तीन दिवसीय पंजाब दौर पर नितिन नबीन

लुधियाना। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शनिवार से तीन दिवसीय पंजाब दौरे पर रहेंगे। अपने इस प्रवास के दौरान नवबीन अमृतसर, जालंधर और लुधियाना में धार्मिक, सामाजिक, संगठनात्मक एवं बौद्धिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। बीजेपी पंजाब के प्रदेश महामंत्री अनिल सरीन ने बताया कि नितिन नबीन 20 जून को अमृतसर पहुंचेंगे और अपने दौरे की शुरुआत श्री हरमंदिर साहिब में मत्था टेककर करेंगे। इसके बाद वे ऐतिहासिक जलियांवाला बाग, श्री दुर्गियाना मंदिर और श्री राम तीर्थ मंदिर में भी दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे और पंजाब की समृद्ध आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को नमन करेंगे।मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 21 जून को नवीन अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके बाद वे लुधियाना पहुंचेंगे, जहां दुगरी रोड स्थित बीजेपी के जिला कार्यालय का औपचारिक उद्घाटन करेंगे।

टेलीग्राम को हाईकोर्ट से बड़ा झटका, 22 तक प्रतिबंध बरकरार

नई दिल्ली। भारत में 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टेलीग्राम को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए पांच दिन के अस्थायी प्रतिबंध को बरकरार रखते हुए टेलीग्राम की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने स्पष्ट कहा कि सरकार ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया है और राष्ट्रीय हित में ऐसा आदेश जारी करने की शक्ति उसके पास मौजूद है।

टेलीग्राम की याचिका पर फैसला सुनाते हुए हाईकोर्ट ने कहा कि प्रतिबंध लगाने के पीछे पर्याप्त कारण मौजूद थे और आदेश की आपात प्रकृति को देखते हुए सरकार की कार्रवाई उचित थी। अदालत ने यह भी माना कि उपलब्ध सामग्री पर केंद्र सरकार ने विधिवत विचार किया था तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया में किसी प्रकार की कमी नहीं थी। कोर्ट ने टेलीग्राम के उस तर्क को भी स्वीकार नहीं किया, जिसमें आदेश की पूर्व सूचना न दिए जाने पर सवाल उठाया गया था।

होर्मुज खुला तो भारत पहुंचा पहला एलएनजी टैंकर

भरुच। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से चली आ रही तनातनी थमने और होर्मुज जलडमरूमध्य से प्रतिबंध हटने के बाद ऊर्जा आपूर्ति में भारत को बड़ी राहत मिली है। दरअसल होर्मुज दोबारा खुलने के साथ ही तरलीकृत प्राकृतिक गैस से लदा पहला टैंकर गुजरात के भरूच जिले स्थित दहेज टर्मिनल पहुंच गया। लगभग 110 दिनों की अनिश्चितता के बाद इस खेप का भारत पहुंचना देश की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, जहाज अपने साथ 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आया है। दहेज टर्मिनल पर इसकी सुरक्षित अनलोडिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे व्यस्त ऊर्जा व्यापार मार्गों में से एक है और इसके बाधित होने से वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा कीमतों पर असर पड़ता है। इस बीच, ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों के आवागमन से जुड़ी सभी अपीलों और अनुमतियों के त्वरित निपटारे का निर्देश जारी किया है।

पीएम मोदी का आज से बंगाल दौरा किसानों को देंगे बड़ी सौगात

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह में लेंगे हिस्सा

नईदिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 और 21 जून को पश्चिम बंगाल का दौरा करेंगे, जहाँ वे पश्चिमबंग दिवस (पश्चिम बंगाल दिवस) में शामिल होंगे और 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व करेंगे। 20 जून को दोपहर लगभग 3:45 बजे, प्रधानमंत्री हुगली ज़िले के तारकेश्वर में पश्चिम बंगाल दिवस समारोह में शामिल होंगे। यह जगह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी से जुड़ी हुई है। राज्य के कार्यक्रम की थीम पश्चिम बंगाल: विरासत, सद्भाव और विकास है, जो राज्य की सांस्कृतिक समृद्धि, सामाजिक एकता और विकास के लक्ष्यों को दर्शाती है।

इस कार्यक्रम के दौरान, मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे, उन्हें राष्ट्र को समर्पित करेंगे और उनकी आधारशिला रखेंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) की 23वीं किस्त भी जारी करेंगे, जिसके तहत देश भर के 9.44 करोड़ से ज़्यादा किसानों को सीधे 18,880 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि ट्रांसफर की जाएगी। अकेले पश्चिम बंगाल में, 45 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों के खातों में 900 करोड़ रुपये से ज़्यादा की राशि जमा की जाएगी, जिससे राज्य में कुल बांटी गई राशि 15,000 करोड़ रुपये से ज़्यादा हो जाएगी। राष्ट्रीय स्तर पर, 2019 से इस योजना के तहत बांटी गई कुल राशि 4.46 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो गई है।

मोदी राज्य में कई अहम केंद्रीय कृषि योजनाओं की शुरुआत करेंगे, जिनमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन के तहत एग्री स्टैक, नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग और प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि योजना (PMDD-KY) शामिल हैं। PMFBY का मकसद लगभग 14 लाख हेक्टेयर ज़मीन पर खेती करने वाले करीब 50 लाख किसानों को फसल बीमा कवर देना है। इसमें लगभग 28,140 करोड़ रुपये की बीमित फसल का मूल्य शामिल है और इसके लिए भारी प्रीमियम सब्सिडी दी जाएगी।

21 जून को कोलकाता में, प्रधानमंत्री मोदी रेड रोड पर 12वें अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के राष्ट्रीय कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे। वे वहां मौजूद लोगों को संबोधित करेंगे और हजारों योग करने वालों के साथ कॉमन योग प्रोटोकॉल सत्र में हिस्सा लेंगे। 2026 के लिए थीम है स्वस्थ उम्र बढ़ने के लिए योग (Yoga for Healthy Ageing)। यह थीम शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक भलाई, भावनात्मक मजबूती और सक्रिय रूप से उम्र बढ़ने में योग की भूमिका पर जोर देती है, जो बढ़ती जीवन प्रत्याशा और स्वस्थ व सम्मानजनक तरीके से उम्र बढ़ने पर दिए जा रहे ध्यान के अनुरूप है।

जब से संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2015 में 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया है, तब से प्रधानमंत्री ने देश और विदेश में कई जगहों पर इन कार्यक्रमों का नेतृत्व किया है। 2026 में योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2,500 जगहों पर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन और पोस्ट शामिल हैं। यह योग को स्वास्थ्य और सद्भाव के एक वैश्विक आंदोलन के रूप में रेखांकित करता है।

झारखंड राज्यसभा चुनाव के हार ने इंडिया गठबंधन खोली पोल

■ गहरी हुई अंदरूनी कलह की खाई

रांची। विधानसभा में सत्ताधारी गठबंधन के पास संख्या बल होने के बावजूद राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार को मिली करारी हार ने कांग्रेस, आरजेडी और सीपीआई (एमएल) नेताओं के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर शुरू कर दिया है। राज्यसभा चुनाव के नतीजों ने झारखंड में इंडिया गठबंधन के भीतर मौजूद अंदरूनी मतभेदों को उजागर कर दिया है। चुनाव से पहले ही उम्मीदवार चुनने और राजनीतिक तालमेल को लेकर जेएमएम और कांग्रेस के बीच मतभेद साफ़ हो गए थे, और अप्रत्याशित नतीजों ने गठबंधन सहयोगियों के बीच रिश्तों में और तनाव पैदा कर दिया है तथा अविश्वास को और बढ़ा दिया है।

झारखंड कांग्रेस के प्रभारी के राजू ने आरोप लगाया कि जेएमएम ने कांग्रेस उम्मीदवार को पूरा समर्थन दिया, फिर भी आरजेडी और सीपीआई (एमएल) ने गठबंधन के साथ धोखा किया। के राजू ने कहा कि हमें कांग्रेस के सभी 16 वोट और जेएमएम से चार अतिरिक्त वोट मिले, जिससे हमारी कुल संख्या 20 हो गई। हालाँकि, यह नतीजा आरजेडी और सीपीआई (एमएल) की धोखेबाज़ी का नतीजा है। राजू के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए, आरजेडी ने कांग्रेस प्रभारी के बयान की कड़ी निंदा की और इसे घटिया मानसिकता का प्रतीक बताया। आरजेडी विधायक और मंत्री संजय प्रसाद यादव ने कहा कि आरजेडी कांग्रेस की तरह धोखेबाज़ नहीं है और उसकी अपनी अलग पहचान है। यादव ने कहा कि मुझे अच्छी तरह पता है कि किसके कहने पर के. राजू आरजेडी विधायकों पर ये आरोप लगा रहे हैं। उन्हें यह भी अच्छी तरह पता है कि कांग्रेस के कौन से विधायक दूसरी राजनीतिक पार्टियों के दरवाज़े खटखटाने के बाद पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि आरजेडी अपनी नीतियों और नियमों के अनुसार काम करती है; पार्टी के विधायकों के सभी चार वोट कांग्रेस को गए।

यादव ने सवाल उठाया कि के. राजू—जो अपने ही विधायकों के लगातार संपर्क में थे—यह कैसे नहीं देख पाए कि असल में अंदर क्या हो रहा था। आरजेडी के महासचिव भोला यादव ने भी कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि राजनीति में आरजेडी कांग्रेस पर निर्भर नहीं है। भोला यादव ने कहा कि कांग्रेस को बयान देने से पहले सोचना चाहिए; दूसरों पर आरोप लगाने से पहले पार्टी को गंभीरता से आत्म-मंथन करने की ज़रूरत है। सीपीआई (एमएल) ने भी कांग्रेस के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। सीपीआई (एमएल) नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि उनके दोनों विधायकों ने इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार के पक्ष में वोट दिया था।

कर्नाटक में क्रॉस वोटिंग से भाजपा में हड़कंप

बेंगलुरु। कर्नाटक विधान परिषद के चुनाव ने भाजपा के नेतृत्व वाले विपक्षी खेमे में खलबली मचा दी है। सत्ताधारी कांग्रेस के सात में से पांच सीटें जीतने के बाद, भाजपा ने उन विधायकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की बात कही है जिन्होंने क्रॉस-वोटिंग की थी। गुरुवार को हुए इस चुनाव ने कांग्रेस को अप्रत्याशित बढ़त दिलाई और भाजपा तथा उसके सहयोगी दल जेडी (एस) के भीतर की दरारों को उजागर कर दिया। जहाँ बीजेपी दो सीटें जीतने में सफल रही, वहीं जेडी (एस) अपनी एकमात्र सीट भी नहीं बचा सकी, क्योंकि दोनों पार्टियों के विधायकों द्वारा कथित क्रॉस-वोटिंग ने मुकाबले का रुख कांग्रेस के पक्ष में मोड़ दिया। कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बी.वाई. विजयेंद्र ने कहा कि जिन विधायकों ने कथित तौर पर पार्टी लाइन के खिलाफ वोट किया, उनकी पहचान कर ली गई है और उन्हें चेतावनी दी गई है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विजयेंद्र ने कहा कि मेरे पास इस बात की पूरी जानकारी है कि गुरुवार को किसने क्रॉस-वोटिंग की।

अमेरिका-ईरान डील पर बोले शशि थरूर

शांति सभी के लिए अच्छी भारत को मिलेगा फायदा

नईदिल्ली। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने शुक्रवार को अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि एक शांति-प्रिय देश के तौर पर भारत को इस घटनाक्रम का समर्थन करना चाहिए, क्योंकि इससे देश और दुनिया दोनों को फ़ायदा होगा। समझौते के महत्व पर बात करते हुए थरूर ने कहा कि इससे उन ज़रूरी चीज़ों की सप्लाई फिर से शुरू हो सकेगी जो टकराव की वजह से रुक गई थीं।

पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि बात यह है कि हमारे देश को इस तरह के हालात का काफ़ी अनुभव रहा है। एशिया में, यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया में भी फ़ैक्टरियाँ बंद हो रही थीं। इसलिए, ऐसे हालात में जब कोई समाधान निकलता है और शांति आती है, तो यह सभी के लिए अच्छा होता है, दुनिया के लिए अच्छा होता है। उन्होंने भारत के लिए आर्थिक फ़ायदों पर भी ज़ोर दिया, ख़ासकर ज़रूरी चीज़ों के आयात के मामले में।

थरूर ने आगे कहा कि हमें उम्मीद है कि इसके बाद, हमारे तेल और गैस, हमारे फ़र्टिलाइज़र, हमारे एल्युमीनियम की सप्लाई जो वहाँ से आती थी और जो सप्लाई वहाँ फंसी हुई थी, वे सभी आ पाएँगी। इसलिए, जब यह सब हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि पूरे देश और दुनिया को इससे फ़ायदा होगा। ग्लोबल स्टेबिलिटी पर भारत का रुख़ दोहराते हुए उन्होंने कहा, मेरी राय में, हम एक शांति-प्रिय देश हैं और हमें निश्चित रूप से इसका समर्थन करना चाहिए।

उनकी ये बातें तब सामने आई हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने वर्चुअली 14-पॉइंट वाले मेमोरेंडम ऑफ़ अंडरस्टैंडिंग (एमओयू) पर साइन किए हैं। इसका मकसद दोनों देशों के बीच दुश्मनी खत्म करना, होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) को फिर से खोलना और प्रतिबंधों व ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतिम समझौते के लिए बातचीत की 60-दिन की प्रक्रिया शुरू करना है।

खेल
प्रमुख समाचार

भारत और अफगानिस्तान के बीच तीसरा वनडे मैच आज

चेन्नई। पहले दो मैच में धमाकेदार जीत से उत्साहित भारतीय टीम अफगानिस्तान के खिलाफ शनिवार को यहां होने वाले तीसरे और अंतिम एकदिवसीय अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच में क्लीन स्वीप करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी जिसमें केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के प्रदर्शन पर नजर रहेगी। राहुल की वनडे टीम में जगह को लेकर कभी कोई संदेह नहीं रहा है, लेकिन जायसवाल शीर्ष क्रम में कड़ी प्रतिस्पर्धा को देखते हुए अपनी जगह पक्की करने के लिए बड़ी पारी खेलना चाहेंगे।

जायसवाल ने 2025 के बाद वनडे टीम में वापसी की है लेकिन वह लखनऊ में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे मैच में केवल चार रन ही बना पाए। बाएं हाथ के इस बल्लेबाज ने इससे पहले जो आखिरी वनडे खेला था उसने उन्होंने विशाखापत्तनम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ नाबाद 116 रन बनाए थे, लेकिन उसके बाद स्थिति काफी बदल गई है और अब ईशान किशन की वापसी ने शीर्ष क्रम में एक और दावेदार को जोड़ दिया है। किशन ने लखनऊ में शतक लगाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है।

कप्तान शुभमन गिल ने जायसवाल को जगह देने के लिए तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी की और शतक जड़ा। लेकिन जब विराट कोहली मांसपेशियों में खिंचाव से उबरने के बाद वापसी करेंगे तो उनका तीसरे नंबर पर खेलना पक्का है। इससे गिल के पास रोहित शर्मा के साथ पारी की शुरुआत करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। किशन और श्रेयस अय्यर क्रमश: चौथे और पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में जायसवाल को सीमित अवसरों का पूरा फायदा उठाना होगा। जायसवाल के लिए इस मैच में बड़ा स्कोर बनाना बेहद जरूरी है क्योंकि इंग्लैंड दौरे के लिए भारत की वनडे टीम की घोषणा जल्द ही की जाएगी।

आर्थिक/वाणिज्य/विज्ञान/
प्रमुख समाचार

सेंसेक्स 608 अंक टूटा निफ्टी 24,013 पर बंद

नईदिल्ली। सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन भारतीय शेयर बाजार दबाव में बंद हुआ। वैश्विक आईटी कंपनी Accenture के कमजोर बिक्री अनुमान और निराशाजनक आउटलुक का असर घरेलू आईटी शेयरों पर भी देखने को मिला, जिसके चलते सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। निफ्टी 50 में 155 अंकों यानी 0.64 प्रतिशत की गिरावट आई और यह 24,013.10 पर बंद हुआ। वहीं, सेंसेक्स 608 अंक यानी 0.78 प्रतिशत टूटकर 76,802.90 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा नुकसान उठाने वाले शेयरों में इंफोसिस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और टेक महिंद्रा शामिल रहे।मुख्य सूचकांकों में गिरावट के बावजूद व्यापक बाजार अपेक्षाकृत मजबूत रहा। निफ्टी मिडकैप इंडेक्स 0.22 प्रतिशत और निफ्टी स्मॉलकैप इंडेक्स 0.42 प्रतिशत की बढ़त के साथ बंद हुए।

आरबीआई के वीआरआर नीलामी में बैंकों की मांग सुस्त

नई दिल्ली। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की एक लाख करोड़ रुपए की तीन दिन की परिवर्ती दर रेपो (वीआरआर) नीलामी को शुक्रवार को बैंकों की सुस्त प्रतिक्रिया मिली जो अल्पकालिक धन की सीमित आवश्यकता का संकेत देती है। केंद्रीय बैंक को वीआरआर नीलामी में बैंकों से एक लाख करोड़ रुपए की अधिसूचित राशि के मुकाबले 16,750 करोड़ रुपए की बोलियां प्राप्त हुईं। आरबीआई ने नीलामी में पूरी राशि को 5.26 प्रतिशत की कट-ऑफ और भारित औसत दर पर स्वीकार कर लिया। बैंकिंग प्रणाली में नकदी की स्थिति अधिशेष में बनी रही, हालांकि इसका स्तर अपेक्षाकृत कम रहा। आरबीआई के पास उपलब्ध नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, 18 जून तक प्रणाली में नकदी अधिशेष करीब 19,163.11 करोड़ रुपए रहा।

जियो प्लेटफॉर्म्स सेबी के समक्ष दाखिल करेगा आईपीओ दस्तावेज

नई दिल्ली। रिलायंस इंडस्ट्रीज की डिजिटल सेवा इकाई जियो प्लेटफॉर्म्स शुक्रवार को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के समक्ष आईपीओ लाने के लिए दस्तावेज दाखिल करेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन एवं प्रबंध निदेशक मुकेश अंबानी ने कंपनी की 49वीं वार्षिक आम बैठक में यह जानकारी दी। विश्लेषकों का अनुमान है कि जियो का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) अब तक का सबसे बड़ा सार्वजनिक निर्गम हो सकता है, जिसका संभावित मूल्यांकन 130-180 अरब अमेरिकी डॉलर के बीच आंका जा रहा है। मुकेश अंबानी ने कहा, मेरे प्रिय शेयरधारकों, मुझे यह बताते हुए अत्यंत खुशी हो रही है कि जियो प्लेटफॉर्म्स के निदेशक मंडल ने आईपीओ दस्तावेज को आज मंजूरी दे दी। इसे आज ही सेबी के समक्ष दाखिल किया जाएगा। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की 66.43% हिस्सेदारी है।

रियल एस्टेट में 14-17 अरब डॉलर की बढ़ोतरी संभव

नईदिल्ली। जनरेटिव आर्टिफिशल इंटेलिजेंस अगले सात साल में रियल एस्टेट क्षेत्र के सकल मूल्य वर्धन में 14 से 17 अरब डॉलर कर सकता है, जो उद्योग के कुल राशि मूल्य में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि के बराबर है। ईवाई-पार्थेनॉन और क्रेडाई की संयुक्त रिपोर्ट में यह बात कही गई है। जेनएआई की मदद से डेवलपर्स को बिक्री की रफ्तार में 30-50 प्रतिशत तक सुधार और प्रोजेक्ट लॉन्च में लगभग 30 प्रतिशत की तेजी देखने को मिल सकती है। रिपोर्ट के अनुसार, प्रॉपर्टी डील्स के मूल्यांकन का समय लगभग 50% तक घट सकता है और जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया 30-35 तक तेज हो सकती है। एआई की मदद से स्वचालित मॉडलिंग, निवेश रिटर्न के बेहतर अनुमान और तेजी से डील एनालिसिस संभव होगा।

किसान की आय बढ़े बिना भारत विकसित नहीं बन सकता

राज बाजोरिया

भारत की विकास यात्रा की सबसे बड़ी सच्चाई गांवों में छिपी है। शहरों में मेट्रो, एक्सप्रेसवे, बड़े अस्पताल और चमकदार बाजार दिखते हैं, लेकिन देश की बड़ी आबादी अब भी खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर है। ताजा पीएलएफएस 2025 के अनुसार भारत में 15 वर्ष से अधिक आयु के करीब 61.6 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। इनमें से 43 प्रतिशत लोग कृषि क्षेत्र में लगे हैं। यानी लगभग 26.5 करोड़ कामगार सीधे खेती और उससे जुड़े कामों पर निर्भर हैं। यह संख्या किसी भी नीति-निर्माता को यह याद दिलाने के लिए काफी है कि भारत की असली आर्थिक शक्ति खेतों में खड़ी है।

समस्या यह है कि जिस क्षेत्र में देश का इतना बड़ा मानव संसाधन लगा है, वहां आय बहुत कम है। किसान आय पर राष्ट्रीय स्तर का नवीनतम उपलब्ध सर्वे नाबार्ड का ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वे है, जिसे 2024 में जारी किया गया। इसके अनुसार कृषि परिवारों की औसत मासिक आय 13,661 रुपये थी। इसमें भी खेती से आय केवल लगभग एक-तिहाई थी। बाकी आय मजदूरी, नौकरी, पशुपालन या छोटे व्यवसाय से आती है। इसका मतलब साफ है कि किसान केवल खेती करके सम्मानजनक जीवन नहीं चला पा रहा।

कम आय का असर केवल किसान की जेब पर नहीं पड़ता। इसका असर बच्चों की पढ़ाई, परिवार के पोषण, महिलाओं के स्वास्थ्य, घर की स्वच्छता, पीने के पानी, इलाज और जीवन की आकांक्षाओं पर पड़ता है। यही कारण है कि हमारे बहुत से गांव आज भी जीवन-स्तर के मामले में यूरोप के गांवों से बहुत पीछे दिखते हैं। वहां गांव का अर्थ पिछड़ापन नहीं, बल्कि साफ सड़क, बेहतर स्कूल, स्वास्थ्य सेवा, तकनीक, बाजार

और सम्मानजनक आय है। भारत में भी गांव को दया का विषय नहीं, विकास का केंद्र बनाना होगा।

विकसित देशों से तुलना करते समय जमीन, मौसम, लागत और सरकारी सहायता के फर्क को समझना जरूरी है। अमेरिका में बड़े व्यावसायिक पारिवारिक खेतों की 2024 में खेती से मध्य आय लगभग 1.75 लाख डॉलर थी। नीदरलैंड में 2025 में कृषि और बागवानी कारोबार की औसत आय प्रति पूर्णकालिक पारिवारिक कामगार लगभग 1.29 लाख यूरो आंकी गई। भारत का छोटा किसान इस स्तर से बहुत दूर है, लेकिन इससे यह सीख मिलती है कि जब खेती को पानी, तकनीक, प्रसंस्करण, भंडारण, निर्यात और मजबूत बाजार से जोड़ा जाता है, तो किसान गरीब उत्पादक नहीं रहता; वह ग्रामीण अर्थव्यवस्था का उद्यमी बनता है।

भारत के लिए तीन मॉडल विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं- पहला, इजरायल का जल प्रबंधन मॉडल : कम पानी और कठिन जलवायु के बावजूद इजरायल ने सूक्ष्म सिंचाई, पुनर्चक्रित पानी, नियंत्रित सिंचाई और जल अनुशासन से खेती को उत्पादक बनाया। राजस्थान, बुंदेलखंड, मराठवाड़ा, विदर्भ और गुजरात जैसे क्षेत्रों में यह सोच बेहद उपयोगी हो सकती है।

दूसरा, नीदरलैंड का उच्च मूल्य बागवानी मॉडल : वहां ग्रीनहाउस, बेहतर बीज, नियंत्रित तापमान, पैकेजिंग, कोल्ड चेन और निर्यात व्यवस्था ने छोटे देश को कृषि शक्ति बना दिया। भारत में यह मॉडल सब जगह नहीं, लेकिन सब्जी, फल, फूल, मसाले, औषधीय पौधे और शहरों के पास की खेती में लागू किया जा सकता है।

तीसरा, सहकारी और किसान उत्पादक संगठन मॉडल: अमूल ने दिखाया कि जब किसान उत्पादन के साथ खरीद, प्रसंस्करण, ब्रांड और वितरण में हिस्सेदार बनता है, तो आय बढ़ती है। यही मॉडल दूध से आगे दाल, मिलेट, फल, सब्जी, मछली, मसाले और जैविक उत्पादों तक ले जाना होगा।

किसान आय बढ़ाने के लिए केवल न्यूनतम समर्थन मूल्य की चर्चा पर्याप्त नहीं है। असली जरूरत पूरी कृषि संरचना बदलने की है। हर खेत तक भरोसेमंद पानी, सूक्ष्म सिंचाई, तालाब, चेकडैम और भूजल पुनर्भरण चाहिए। अच्छी गुणवत्ता के बीज, समय पर खाद, मिट्टी जांच, जैविक कार्बन सुधार और फसल सलाह हर किसान तक पहुंचनी चाहिए।

150वीं जयंती वर्ष पर डोंडराही में भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण

जनजातीय विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज जशपुर जिले के विकासखंड बगीचा के ग्राम डोंडराही में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती वर्ष के अवसर पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि यह स्थल अब बिरसा मुंडा चौक के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री ने भगवान बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि उनका जीवन अन्याय, शोषण और अंग्रेजी शासन के विरुद्ध संघर्ष के साथ-साथ जल, जंगल और जमीन की रक्षा के लिए समर्पित रहा। उन्होंने जनजातीय अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा का जीवन आज भी जनजातीय समाज सहित पूरे देश को अपने अधिकारों, संस्कृति और परंपराओं की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को 'जनजातीय गौरव दिवस' के रूप में मनाने का ऐतिहासिक निर्णय लेकर जनजातीय नायकों के योगदान को राष्ट्रीय पहचान दिलाने का कार्य किया है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने क्षेत्र के विकास एवं सामाजिक-सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न निर्माण कार्यों हेतु कुल 37 लाख रुपये की घोषणा की। उन्होंने बैगाटोली कर्मा में सामुदायिक भवन निर्माण के लिए 15 लाख रुपये, कुदमुरा नांदो टोली में रंगमंच निर्माण हेतु 8 लाख रुपये, कुदमुरा पतराटोली (डिबा टोली) में सांस्कृतिक मंच निर्माण के लिए 7 लाख रुपये तथा केशव घर के समीप स्थित हनुमान मंदिर परिसर में मंच निर्माण के लिए 7 लाख रुपये स्वीकृत करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार जनजातीय समाज के सर्वांगीण विकास के लिए निरंतर कार्य कर रही है। पीएम जनमन योजना और धरती आबा ग्राम उत्कर्ष योजना के माध्यम से जनजातीय क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ के 6,661 गांव इस योजना में शामिल हैं, जहां सड़क, पेयजल, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं को प्राथमिकता दी जा रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु का देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचना जनजातीय समाज के सम्मान और गौरव का प्रतीक है। उन्होंने जशपुर को जनजातीय संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण केंद्र बताते हुए कहा कि यहां स्थित अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम देशभर में जनजातीय समाज के उत्थान के लिए उल्लेखनीय कार्य कर रहा है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार ने मोदी की गारंटी के अधिकांश वादों को ढाई वर्षों के भीतर पूरा किया है। सरकार गठन के 24 घंटे के भीतर 18 लाख प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें से 10 लाख 60 हजार से अधिक आवास पूर्ण हो चुके हैं। किसानों को 3,100 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान का मूल्य दिया जा रहा है तथा 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की जा रही है।

वनांचल के युवाओं का पराक्रम
शंकरगढ़ के 11 युवा बने अग्निवीर

रायपुर । छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र शंकरगढ़ के युवाओं ने यह साबित कर दिया है कि प्रतिभा और दृढ़ संकल्प के सामने संसाधनों की कमी कोई मायने नहीं रखती। बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ विकासखंड के 11 युवाओं का भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती में चयन हुआ है। इनमें ग्राम जोकापाठ निवासी श्री अरविंद यादव का चयन भारतीय सेना की प्रतिष्ठित स्पेशल फोर्स 'पैरा कमांडो' में हुआ है। वे जिले से इस गौरवशाली इकाई में चयनित होने वाले पहले युवा बन गए हैं।

वनांचल और ग्रामीण परिवेश से निकलकर इन युवाओं ने कठिन परिस्थितियों, सीमित सुविधाओं और संसाधनों के अभाव के बावजूद अपनी मेहनत, अनुशासन और देशसेवा के जज्बे के बल पर यह मुकाम हासिल किया है। उनकी सफलता पूरे सरगुजा संभाग के युवाओं के लिए प्रेरणास्रोत बन गई है।हाल ही में चयनित युवा अपने प्रशिक्षकों के साथ कलेक्टर श्रीमती चंदन संजय त्रिपाठी से मिले। कलेक्टर ने सभी युवाओं को बधाई देते हुए कहा कि क्षेत्र के युवाओं में असीम संभावनाएं हैं। यदि उन्हें सही दिशा, प्रशिक्षण और प्रोत्साहन मिले तो वे राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान स्थापित कर सकते हैं। उन्होंने युवाओं से अपने गांव और आसपास के अन्य युवाओं को भी सेना तथा अन्य प्रतिस्पर्धी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करने का आह्वान किया।इस उपलब्धि के पीछे अतिथि शिक्षक श्री सुदर्शन यादव और एक सेवानिवृत्त सैनिक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दोनों ने युवाओं को भर्ती प्रक्रिया की जानकारी देने, शारीरिक दक्षता विकसित करने और लिखित परीक्षा की तैयारी कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके मार्गदर्शन और युवाओं की अथक मेहनत का परिणाम आज पूरे जिले के सामने प्रेरक उदाहरण के रूप में है।विशेष रूप से श्री अरविंद यादव की सफलता ने इस उपलब्धि को और भी खास बना दिया है।

केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने पर प्रदेशभर में जनकल्याण शिविरों की शुरुआत

रायपुर। केंद्र सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित विकास के विश्वास जनकल्याण अभियान के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से जोड़ने के लिए विशेष पंजीकरण एवं जनसेवा शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में बलरामपुर जिले के शंकरगढ़ विकासखंड में तीन दिवसीय जनकल्याण शिविर का शुभारंभ किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोगों ने विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने के लिए पंजीयन कराया। शिविर में महिला एवं बाल विकास, कृषि, राजस्व, श्रम, समाज कल्याण तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग सहित कई विभागों ने अपने स्टॉल लगाकर नागरिकों से आवेदन प्राप्त किए। महिला एवं बाल विकास विभाग ने महतारी वंदन योजना एवं आधार संबंधी आवेदनों का पंजीयन किया, वहीं कृषि विभाग ने किसानों का एग्रीस्टेक पंजीयन कर उन्हें डिजिटल कृषि सेवाओं से जोड़ने की पहल की।

राजस्व विभाग को आय, निवास और जाति प्रमाण-पत्र सहित नामांतरण संबंधी आवेदन प्राप्त हुए, जबकि श्रम विभाग ने श्रमिक पंजीयन की प्रक्रिया पूरी की। समाज कल्याण विभाग ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन तथा खाद्य विभाग ने राशन कार्ड से संबंधित आवेदनों का पंजीयन किया। कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण निराकरण सुनिश्चित किया जाए।

उन्होंने कहा कि शासन की मंशा है कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और जनकल्याण शिविर इस उद्देश्य को पूरा करने का प्रभावी माध्यम बन रहे हैं। प्रदेश में आयोजित ऐसे शिविरों के माध्यम से नागरिकों को विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही छत के नीचे उपलब्ध कराई जा रही हैं।

न्यायालय परिसर विशेष चेकिंग अभियान

रायपुर। राजधानी रायपुर में न्यायालय परिसर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए पुलिस ने विशेष आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान संदिग्ध गतिविधियों में शामिल पाए गए 4 व्यक्तियों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। अभियान का उद्देश्य परिसर में शांति व्यवस्था बनाए रखना और असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण सुनिश्चित करना बताया गया। पुलिस आयुक्त डॉ. संजीव शुक्ला के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई। अभियान का मार्गदर्शन पुलिस उपायुक्त (सेंट्रल जोन) उमेश प्रसाद गुप्ता और पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला ने किया। वहीं अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त (मध्य क्षेत्र) तारकेश्वर पटेल और सहायक पुलिस आयुक्त सिविल लाइन

रमाकांत साहू के निर्देशन में पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया।

अभियान में थाना सिविल लाइन, देवेन्द्र नगर थाना, एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट, अन्य थाना बल और रक्षित केंद्र के लगभग 70 पुलिसकर्मियों की विशेष टीम शामिल रही। टीम ने न्यायालय परिसर और आसपास के क्षेत्रों में सघन जांच और निगरानी की। चेकिंग के दौरान परिसर में आने-जाने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर लगातार नजर रखी गई।

तय मानकों के अनुसार लगाए जा रहे है विद्युत स्मार्ट मीटर

■ अब गलत मीटर रीडिंग पर लगेगा विराम

रायपुर। स्मार्ट मीटर किसी राज्य सरकार की अलग योजना नहीं, बल्कि भारत सरकार की पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना के तहत पूरे देश में लागू की गई राष्ट्रीय पहल है। इसी योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और निर्धारित मानकों के अनुसार छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्यों में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार इस केंद्रीय योजना का क्रियान्वयन करते हुए विद्युत वितरण व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, आधुनिक और उपभोक्ता हितैषी बनाने की दिशा में कार्य कर रही है।

केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में देशभर में स्मार्ट मीटरिंग योजना लागू करने का निर्णय लिया था। इसका उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों की कार्यक्षमता बढ़ाना, तकनीकी एवं वाणिज्यिक हानियों में कमी लाना, बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता सुधारना तथा उपभोक्ताओं को सटीक बिलिंग की सुविधा उपलब्ध कराना है।

छत्तीसगढ़ में स्मार्ट मीटर परियोजना लागू करने का निर्णय पूर्ववर्ती सरकार वर्ष 2022 में लिया गया था। परियोजना के लिए टेंडर जारी होने और कार्यादेश दिए जाने के बाद फरवरी 2024 से स्मार्ट मीटर लगाने का कार्य प्रारंभ हुआ। वर्तमान में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा पूर्व में जारी निविदाओं, अनुबंधों और कार्यादेशों के आधार पर ही परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है।

प्रदेश में लगभग 55 लाख उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाने का लक्ष्य है, जिनमें से करीब 40 लाख मीटर स्थापित किए जा चुके हैं।स्मार्ट मीटर से उपभोक्ताओं को कई सुविधाएं मिल रही हैं। बिजली की खपत का आंकड़ा हर 30 मिनट में उपलब्ध होता है, जिससे उपभोक्ता अपने उपयोग पर बेहतर निगरानी रख सकते हैं। मीटर रीडर द्वारा गलत रीडिंग दर्ज होने की संभावना समाप्त हो जाती है और बिलिंग अधिक सटीक होती है।इसके अलावा स्मार्ट मीटर के माध्यम से बिजली भार, वोल्टेज और ऊर्जा खपत सहित अन्य तकनीकी आंकड़े वास्तविक समय में प्राप्त होते हैं।

छत्तीसगढ़/राजधानी

प्रमुख समाचार

मुख्यमंत्री, मंत्रियों का भरोसा खो बैठे है: दीपक बैज

रायपुर। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि मुख्यमंत्री निवास में अचानक मंत्रियों की बैठक बुलाना तथा बैठक के बाद जो खबरे सामने आ रही वह बताती है कि भाजपा की सरकार आपसी अंतर्कलह से जूझ रही तथा सरकार अपने लोगों को विश्वास खो चुकी है। सत्ता का संघर्ष अब खुलकर सामने आने लगा है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर

खाने में आपसी विरोध चल रहा है। मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों का भरोसा खो चुके हैं।प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि पिछले एक पखवाड़े से चर्चा चल रही थी कि मंत्रियों का सामूहिक इस्तीफा लिया जायेगा। मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा, मंत्रिमंडल में बदलाव किया जाएगा। कल इसी संबंध में मुख्यमंत्री निवास में मंत्रियों की अचानक बैठक बुलाई गयी तथा संगठन के वरिष्ठ नेताओं की उपस्थिति में मंत्रियों के कामकाज की बातें हुई, कुछ मंत्रियों के काम काज पर असंतोष जताया गया। आधे से अधिक मंत्रियों के कामकाज असंतोषजनक पाये गये है। सरगुजा संभाग के दो मंत्री तथा एक उपमुख्यमंत्री के कामकाज पर तो बेहद नाराजगी सामने आई। इसके बाद अचानक तथा सभी मंत्रियों से इस्तीफा मांगा गया ताकि मंत्रिमंडल में फेरबदल किया जा सके लेकिन बताते है मंत्रियों ने इस्तीफा देने से मना कर दिया गया।

भाजपा ने झारखंड में लोकतंत्र का चीरहरण किया : शुक्ला

रायपुर। भाजपा ने झारखंड में लोकतंत्र का चीरहरण किया है। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झारखंड राज्यसभा के चुनाव को पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां के आर्ब्जवर थे। उनसे जोड़कर के भारतीय जनता पार्टी ने जो पोस्टर जारी किया है तथा जो बयान दे रहे है, वह बेशर्मी की पराकाष्ठा है। भारतीय

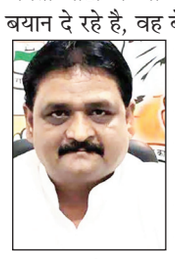

जनता पार्टी इतनी बेशर्म पार्टी बन गयी है। इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। झारखंड में भाजपा को बहुमत नहीं था, उसने वहां पे पैसा देके खरीद फरोख्त करके पूंजीपति दलाल किस्म के व्यक्ति को राज्यसभा का प्रत्याशी बनाया, उसको समर्थन किया, उसके लिये विधायकों की खरीद फरोख्त किया और चुनाव जीत गये।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि झारखंड के जीत के बाद बेशर्मी पूर्वक विपक्षी दल के आर्ब्जवर के बारे में ओक्षी टिप्पणी कर रहे है। यह भाजपा की स्तरहीन राजनीति है। भारतीय जनता पार्टी को माफी मांगना चाहिये कि वो लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे है।प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि एआईसीसी महासचिव एवं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां के आर्ब्जवर बनाये गये थे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के समन्वय स्थापित करने के लिये।

आवास मेला-2025 के लक्की ड्रॉ विजेताओं की घोषणा 22 को

रायपुर। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल ने वर्ष 2025-26 में आवासीय एवं व्यावसायिक संपत्तियों के विक्रय के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडल द्वारा अप्रैल 2025 से मार्च 2026 के दौरान लगभग 5,145 संपत्तियों का विक्रय किया गया, जिसका कुल मूल्य 1,104 करोड़ रुपये से अधिक है। यह मंडल के इतिहास का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक विक्रय है। शासन द्वारा संचालित वन टाइम सेटलमेंट योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को 30 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई, जिससे लगभग 1,533 संपत्तियों का विक्रय हुआ। लगभग 232.30 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियां विक्रय हुईं तथा बड़ी संख्या में मध्यम एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों को लाभ मिला। इसी क्रम में 23 से 26 नवम्बर 2025 तक रायपुर के बीटीआई ग्राउंड, शंकर नगर में आयोजित राज्य स्तरीय आवास मेला-2025 को नागरिकों का व्यापक प्रतिसाद प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने मेले का शुभारंभ किया था। आवास मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी के विशेष मार्गदर्शन तथा मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंह देव के नेतृत्व में आयोजित इस चार दिवसीय मेले में प्रदेशभर की आवासीय एवं व्यावसायिक योजनाओं की जानकारी एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई गई। मेले के दौरान मंडल द्वारा राज्य के 26 जिलों में लगभग 2,080 करोड़ रुपये लागत की 56 नई आवासीय योजनाओं का शुभारंभ किया गया।

अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना में आवेदन 22 जून से

रायपुर। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संचालित अटल उत्कृष्ट शिक्षा योजना के तहत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के प्रतिभावान बच्चों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना के माध्यम से बच्चों को राज्य के चयनित निजी आवासीय विद्यालयों में कक्षा 6वीं से 12वीं तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। योजना के अंतर्गत चयनित विद्यार्थियों की शैक्षणिक फीस, आवासीय सुविधा, भोजन, गणवेश, लेखन सामग्री सहित अन्य आवश्यक खर्चों का वहन कल्याण मंडल द्वारा किया जाएगा। इसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों के बच्चों को बेहतर शैक्षणिक अवसर उपलब्ध कराकर उनके उज्ज्वल भविष्य का निर्माण करना है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र एवं पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों को श्रम विभाग के पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन प्रक्रिया, पात्रता एवं चयन संबंधी विस्तृत जानकारी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 जून 2026 से शुरू होगी तथा 3 जुलाई 2026 तक आवेदन किए जा सकेंगे। इच्छुक आवेदक श्रम विभाग के पोर्टल https://shramevjayate.cg.gov.in/shramik पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा निकटतम श्रम कार्यालय, लोक सेवा केंद्र, श्रमेव जयते ऐप एवं पोर्टल के माध्यम से भी आवेदन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। पर आवेदन कर सकते हैं।

शास्त्री मार्केट में नापतौल विभाग का निरीक्षण

रायपुर। कलेक्टर जनदर्शन में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के निर्देशानुसार शास्त्री मार्केट रायपुर में नापतौल विभाग द्वारा आकस्मिक निरीक्षण किया गया। उक्त कार्यवाही नियंत्रक डॉ देवेंद्र भारद्वाज के नेतृत्व में निरीक्षण के दौरान अनियमितता पाए जाने पर 6 प्रकरण दर्ज कर कुल 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। विभागीय अधिकारियों ने अन्य व्यापारियों को समय पर बाट-माप का सत्यापन एवं मुद्रांकन कराने के निर्देश दिए। साथ ही स्पष्ट किया कि उपभोक्ता हितों की सुरक्षा के लिए इस प्रकार की आकस्मिक निरीक्षण की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। कार्रवाई के समय सहायक नियंत्रक श्री आर.एस सोरी, निरीक्षक श्रीमती उमेश्वरी जांगड़े, निरीक्षक जितेन्द्र कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

लोकसाहित्य के दर्पण में अतीत का प्रतिबिंब विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का समापन

लोककथाओं- जनश्रुतियों में संरक्षित है इतिहास

रायपुर। लोक साहित्य में निहित ऐतिहासिक चेतना, जनजातीय ज्ञान परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को नई दिशा प्रदान करते हुए संस्कृति विभाग के अंतर्गत पुरातत्व, अभिलेखागार एवं संग्रहालय संचालनालय द्वारा आयोजित दो दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन लोकसाहित्य के दर्पण में अतीत का प्रतिबिंब का शुक्रवार को सफल समापन हुआ। महंत घासीदास स्मारक संग्रहालय, रायपुर के सभागार में आयोजित इस सम्मेलन में इतिहासकारों, लोक साहित्य विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं और विद्वानों ने लोक परंपराओं में संरक्षित ऐतिहासिक

स्मृतियों के महत्व पर व्यापक विमर्श किया।

सम्मेलन का उद्देश्य लोककथाओं, लोकगाथाओं, जनश्रुतियों और पारंपरिक ज्ञान में सुरक्षित इतिहास को पहचानना, उसका प्रलेखन करना तथा भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित करने की दिशा में अकादमिक संवाद को प्रोत्साहित करना था। समापन दिवस पर आयोजित तीन तकनीकी सत्रों में प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से आए विशेषज्ञों ने अपने शोधपत्रों के माध्यम से लोक साहित्य और इतिहास के गहरे संबंधों को रेखांकित किया। तृतीय तकनीकी सत्र की अध्यक्षता वरिष्ठ विदुषी डॉ. सत्यभामा आडिल ने की। सत्र में लोक साहित्य में संरक्षित पारंपरिक ज्ञान और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर केंद्रित शोध प्रस्तुत किए गए। डिंडोरी से आए डॉ. विजय चौरसिया ने बैगा जनजाति की पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वनस्पतियों और जड़ी-बूटियों पर आधारित यह ज्ञान प्रणाली आज भी अनेक जटिल रोगों के उपचार में प्रभावी है।

महासमुंद की डॉ. अनुसुईया अग्रवाल ने छत्तीसगढ़ी लोकोक्तियों के माध्यम से इतिहास के विभिन्न आयामों को प्रस्तुत किया, जबकि डॉ. अरुण कुमार निगम ने महानदी, शिवनाथ, लीलागर और नर्मदा जैसी नदियों से जुड़ी लोककथाओं और जनश्रुतियों का विश्लेषण कर उनके ऐतिहासिक महत्व को सामने रखा। डॉ. पीसी लाल यादव ने पुरातात्त्विक अवशेषों के आधार पर 'कुँवर अछरिया' लोकगाथा की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला, वहीं श्रीमती शकुंतला तरार ने बस्तर के पूजनीय प्रेमी युगल देवता 'झिटकू-मिटकी' की लोककथा का भावपूर्ण प्रस्तुतीकरण किया। सत्राध्यक्ष डॉ. सत्यभामा आडिल ने कहा कि पारंपरिक चिकित्सा ज्ञान और आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के समन्वय से समाज को व्यापक लाभ मिल सकता है।

बारिश से पहले नालो की हुई सफाई
जोन कमिश्नर ने किया निरीक्षण

रायपुर । नगर पालिक निगम की महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर ने नगर निगम जोन 10 के विभिन्न वार्डों में वार्ड पार्षद गायत्री नौरंगे, सुषमा तिलक साहू, विनय पंकज निर्मलकर सहित नगर निगम जोन 10 जोन कमिश्नर मोनेश्वर शर्मा, उपअभियंता राहुल वैष्णव, जोन स्वास्थ्य अधिकारी अमित बेहरा, जोन स्वच्छता निरीक्षक अनिल झा की उपस्थिति में सभी बडे नालो की वर्षा पूर्व सफाई के अभियान का प्रत्यक्ष निरीक्षण किया। स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर ने बडे नालो की सफाई सहित वार्डों में जलभराव क्षेत्रो और वर्षा पूर्व निकासी प्रबंधन का प्रत्यक्ष निरीक्षण करते हुए जोन 10 जोन कमिश्नर को व्यवहारिक आवश्यकतानुसार वर्षा पूर्व साफ सफाई करवाकर आवश्यकता के अनुरूप नालो की जोन के माध्यम से तत्काल मरम्मत करवाकर वर्षा पूर्व जोन क्षेत्र में निकास की व्यवस्था सुगम बनाने के स्थल पर कडे निर्देश दिये।

आर.एन.आई.रजि. क्र. CHHHIN/2021/80529, स्वत्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक- शशांक शर्मा द्वारा मिशन मीडिया प्रा. लि., प्रेस कॉम्प्लेक्स, रजबंधा मैदान, रायपुर (छ.ग.) 492001 से मुद्रित एवं 29/1110, सेवती स्मृति, आजाद चौक, रायपुर (छ.ग.) 492001 से प्रकाशित। संपादक-शशांक शर्मा, मो. 94255-20531.